वीं

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के समीप),
नई दिल्ली-110067

वेबसाइट: www.nipfp.org.in

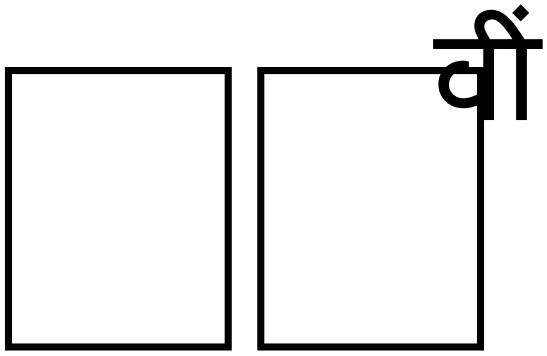

वार्षिक रिपोर्ट

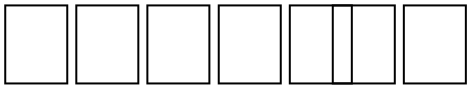

01 अप्रैल□2021- 31 मार्च□2022

प्रकाशक:

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
□वित्त मंत्रालय□भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी
अनुसंधान संस्थान)

18/2□सत्संग विहार मार्ग□विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू
के समीप)□नई दिल्ली-110067

दूरभाष: □□□□□□□9□□□□□□□□9□□□□□□□9□□□

फैक्स: □9□□□□□□□□□□□□□

ई-मेल:polic□communication□@nip□p.org.in

वेबसाइट: □□□.nip□p.org.in

संकलनकर्ता: अमिता मन्हास

डिजाइन : रोहित दत्ता

मुद्रक : हमिांशी इंटरप्राइजेज

ई-मेल : naturalimp9@gmail.com

विषय-सूची

प्रस्तावना	
अनुसंधान क्रियाकलाप	
पूर्ण किए गए अध्ययन	
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप	
वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप	9
अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप	
चल रहे अध्ययन	
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चल रहे अध्ययन	
वित्त मंत्रालय के लिए चल रहे अध्ययन	
अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए चल रहे अध्ययन	
आरंभ की गई नई परियोजनाएं	
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आरंभ की गई नई परियोजनाएं	
वित्त मंत्रालय के लिए आरंभ की गई नई परियोजनाएं	
अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए आरंभ की गई नई परियोजनाएं	
कार्यशालाएं बैठकें और सम्मेलन	
प्रशिक्षण कार्यक्रम	
प्रकाशन और संचार	
पुस्तकालय और सूचना केंद्र	
कम्प्यूटर केंद्र	
संकाय क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं	
अनुबंध	
अनुबंध I अध्ययनों की सूची –	
अनुबंध II एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला	9
अनुबंध III एनआईपीएफपी आंतरिक संगोष्ठी श्रंखला	9
अनुबंध I शासी निकाय के सदस्यों की सूची	9
अनुबंध समूल्य प्रकाशनों की सूची	
अनुबंध I एनआईपीएफपी संकाय द्वारा प्रकाशित सामग्री	
अनुबंध II की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची	
अनुबंध III की स्थिति के अनुसार प्रायोजक निगमित स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची	9
अनुबंध I वित्त और लेखे	

प्रस्तावना

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)□नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट संस्थान में किए गए कार्यों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है तथा इसके शासी निकाय और जनता के प्रति इसकी जवाबदेही को प्रतिबिंबित करती है। □□वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष □□□□□□ के दौरान एनआईपीएफपी के क्रियाकलापों का एक सिंहावलोकन दर्शाती है। इस वर्ष के दौरान□कोविड-□9 ने संस्थान के कामकाज को प्रभावित करना जारी रखा□ जिससे संकाय और कर्मचारी संक्रमित हो रहे थे। ऑफ़लाइन काम-काज पर कुछ सीमित समय के लिए ही प्रतिबंध लगाए गए थे। संस्थान के कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करने का लचीलापन प्रदान किया गया था और संस्थान अनुसंधान आउटपुट पर अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के साथ-साथ विभिन्न मोर्चों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में सक्षम रहा है। वर्तमान और विगत वार्षिक रिपोर्टों की डिजिटल प्रतियां संस्थान की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

संस्थान का परिचय

एनआईपीएफपी की स्थापना 1976 में सार्वजनिक अर्थशास्त्र और नीतियों के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान के लिए एक केंद्र के रूप में की गई थी। वित्त मंत्रालय□योजना आयोग□अनेक राज्य सरकारों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की संयुक्त पहल पर संस्थान को एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईपीएफपी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम□1860 के अधीन पंजीकृत है।

संस्थान सार्वजनिक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान□नीति समर्थन और क्षमता निर्माण का कार्य करता है। संस्थान के मुख्य अधिदेशों में से एक साक्ष्य-आधारित नीति संबंधी विवरण प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और सुधारने में केंद्र□राज्य और स्थानीय सरकारों की सहायता करने से जुड़ा हुआ है।

अपने अस्तित्व के 46 वर्षों में□संस्थान भारत में एक उत्कृष्ट चिंतन केंद्र के रूप में उभरा है और इसने सरकार के सभी स्तरों पर नीतिगत सुधारों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ कार्यात्मक संबंध बनाए रखा है तथा भारत और विदेश□दोनों ही स्थानों में स्थित अन्य शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध बनाए हैं। यद्यपि संस्थान को वित्त मंत्रालय□भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है□यह अनुसंधान और नीति के क्षेत्रों में कार्य करते हुए स्वतंत्र गैर-सरकारी प्रकृति धारित करता है।

शासी मंडल

संस्थान के शासी निकाय की 18 जून 2020 को आयोजित बैठक में शासी निकाय का चार और वर्ष की अवधि के लिए□अर्थात 5 अप्रैल 2020 से 4 अप्रैल 2024 तक पुनर्गठन किया। डॉ उर्जित पटेल अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय के प्रमुख हैं। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री तरुण बजाज□राजस्व सचिव□श्री अजय सेठ□सचिव (आर्थिक मामले) और डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन□मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व डॉ. राजीव रंजन□प्रभारी सलाहकार□मौद्रिक नीति विभाग□और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व सुश्री अन्ना रॉय□वरिष्ठ सलाहकार द्वारा किया जाता है।

प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं: श्री समीर कुमार सिन्हा□आईएएस□प्रमुख सचिव□असम सरकार□श्री संजय एम. कौल□आईएएस□सचिव (वित्त व्यय)□केरल सरकार□और श्री दिनेश कुमार जैन□आईएएस□अतिरिक्त

मुख्य सचिव□महाराष्ट्र सरकार। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि श्री शमशेर सिंह रावत□प्रधान वित्त सचिव (एफएसी)□ आंध्र प्रदेश सरकार□श्री आई.एस.एन. प्रसाद□अतिरिक्त मुख्य सचिव□कर्नाटक सरकार□और श्रीमती स्मारकी महापात्रा सचिव□वित्त विभाग□पश्चिम बंगाल सरकार ने शासी निकाय में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

आईसीआईसीआई बैंक ने श्री प्रसन्ना बी□ग्लोबल हेड - मार्केट्स (सेल्स□ट्रेडिंग एंड रिसर्च) को शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया है। श्री सुमंत सिन्हा□अध्यक्ष□एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और श्री संजीव मेहता□अध्यक्ष□फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)□ संस्थानों की ओर से नामित किए गए हैं।

शासी निकाय में तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं - डॉ. एम. गोविंदा राव□पूर्व सदस्य□चौदहवां वित्त आयोग□डॉ. ज्योत्सना जालान□अर्थशास्त्र के प्रोफेसर□सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र□कोलकाता□और डॉ. माला लालवानी□ प्रोफेसर□राजनीतिक अर्थव्यवस्था, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी□मुंबई विश्वविद्यालय□ मुंबई।

सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि हैं - डॉ. पूनम गुप्ता□महानिदेशक□नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) और सुश्री यामिनी अय्यर□अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी□सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सुश्री) केमिशा सोनी□काउंसिल सदस्य□इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया□शासी निकाय की सहयोजित-सदस्य हैं।

डॉ. आर. कविता राव शासी निकाय की वर्तमान निदेशक और पदेन सदस्य हैं। डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती ने 31 मार्च 2022 को निदेशक पद का कार्यभार छोड़ दिया है। डॉ. लेख चक्रवर्ती□प्रोफेसर□बोर्ड में एनआईपीएफपी संकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शासी निकाय में विशेष आमंत्रितों में श्री नितिन गुप्ता□अध्यक्ष□केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड□वित्त मंत्रालय और श्री विवेक जौहरी□अध्यक्ष□केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड□वित्त मंत्रालय□भारत सरकार शामिल हैं। (विवरण के लिए अनुबंध I□ देखें।)

परियोजनाओं का सारांश : पूर्ण की गई और चल रही

रिपोर्ट के वर्ष में हमारे शोध लक्ष्यों निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे दलों द्वारा हासिल किया गया है: कराधान और राजस्व□सार्वजनिक व्यय और वित्तीय प्रबंधन□व्यापक आर्थिक मुद्दे□अंतर सरकारी वित्तीय संबंध□और राज्य योजना और विकास।

कराधान क्षेत्र में□आंध्र प्रदेश के राजस्व पर जीएसटी मुआवजे की वापसी के प्रभाव के चल रहे अध्ययन सहित□ डिजिटलीकरण और माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की विकसित गतिशीलता से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

व्यय कार्यक्रमों की दक्षता का आकलन करने के लिए कई अध्ययनों की मांग की गई। इनमें मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना का आकलन□स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय की दक्षता के संदर्भ में राज्यों की तुलना और विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में देश में स्वास्थ्य और शिक्षा में विकसित हो रहे रुझानों का विश्लेषण□ शामिल हैं। ईएसी-पीएम के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का अध्ययन: पुनर्गठन और युक्तिकरण भी संचालित किया गया था।

ऋण स्थिरता और अधिक सामान्यत: राजकोषीय स्थिरता पर सतत रूप से ध्यान दिया जाना जारी है - वर्ष में

किए गए दो अध्ययन केंद्र सरकार के लिए ऋण स्थिरता पर और दूसरा ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय स्थिरता पर आधारित हैं। कोविड -19 के कारण अर्थव्यवस्था में व्यवधान और वित्तीय संकट के संदर्भ में प्रधानमंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए एक अध्ययन कोविड-उपरांत राजकोषीय ढांचा: मुद्दे और विकल्प संचालित किया गया था।

संस्थान के दल अर्थव्यवस्था की स्थिति और वित्तीय स्थिरता की समय-समय पर समीक्षा करती हैं। ईएसी-पीएम के लिए एक त्रैमासिक अर्थव्यवस्था और विकास दृष्टिकोण तैयार किया जाता है जबकि आर्थिक मामले विभाग के लिए मासिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है।

हरियाणा में राज्य वित्त आयोगों के अधीन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को निधियों के हस्तांतरण पर किया गया अध्ययन तथा भारत में राज्य वित्त आयोगों की समीक्षा विषय पर एक चल रहा अध्ययन स्थानीय निकायों को निधियों के प्रवाह में विद्यमान प्रवृत्तियों की जांच करता है।

हम राज्य के वित्त की बहुत बारीकी से निगरानी करना जारी रखे हुए हैं और अपने राज्य वित्त डेटा बैंक को लगातार अपडेट करते हैं जो एनआईपीएफपी में एक अनूठा संसाधन है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान हमने राज्य के वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध-पत्र प्रकाशित किए। राजस्थान सरकार के लिए भी कोविड महामारी और राजस्थान का वित्त: मुद्दे और विकल्प पर कार्य शुरू किया गया था।

क्षमता-निर्माण कार्यक्रम

एनआईपीएफपी ने अपने अधिदेश की प्रासंगिकता के मुद्दों पर वर्ष के दौरान कई कार्यशालाओं बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया।

संस्थान ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ म्यूनिख जर्मनी के साथ साझेदारी करते हुए 29-30 जून 2021 को पेपर्स इन पब्लिक फाइनेंस पर दो-दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

एनआईपीएफपी ने निम्न का आयोजन भी किया :

- माइकल कीन और जोएल स्लेमरोड द्वारा हाल ही में रिबेलियन रास्कल्स एंड रेवेन्यू नामक पुस्तक पर एक वेबिनार। 19 जुलाई 2021.

- तमिलनाडु छठे वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे 6 अगस्त 2021 पर एक आधे दिन का वेबिनार।

- पीएफएम रेडीनेस इंडेक्स पर एक आधे दिवसीय कार्यशाला। 1 अक्टूबर 2021.

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ संयुक्त रूप से फ्रैजाइल फ्यूचर्स: द अनसर्टेन इकोनॉमिक्स ऑफ डिजास्टर्स पैनडेमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज पर एक वेबिनार। 16 नवंबर 2021.

- एनआईपीएफपी ने आपदा प्रबंधन पहल और अभिसरण सोसायटी (डीएमआईसी) हैदराबाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) नई दिल्ली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) दिल्ली अन्य वैज्ञानिक तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करते हुए नई दिल्ली में प्रबंधन पर पांचवीं विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीडीएम 2021) में कोविड-19: आर्थिक मंदी पर काबू पाने और लचीलेपन के निर्माण के लिए वित्तीय तनाव पर एक सत्र का आयोजन किया। 24-27 नवंबर 2021.

- सोलहवीं पांच संस्थान बजट संगोष्ठी - अनपैकिंग द यूनियन बजट 2022-23' 7 फरवरी 2022 को आयोजित

की गई थी। इस ऑनलाइन आयोजन की मेजबानी करने के लिए पांच संस्थान - सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर□□इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआईईआर□□इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ□□नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनआईपीएफपी□और एनआईपीएफपी एक मंच पर साथ आए।

- एनआईपीएफपी ने दिल्ली में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में □एन इंक्वायरी इन एक्जिट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड□ विषय पर आधे दिन के वेबिनार की मेजबानी की। 25 मार्च 2022.

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया:

- भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए □सार्वजनिक वित्त□पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। □□□□□ जून □□□□.
- तमिलनाडु सरकार के समूह □क□अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। □□ अगस्त से □ अक्टूबर □□□□.
- तमिलनाडु सरकार के समूह □ख□अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।□□ अक्टूबर से □□ दिसंबर □□□□.
- बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार□वित्त मंत्रालय (ईआरडी अधिकारी) के अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□पर एक सप्ताह का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम। □□ मार्च से □ अप्रैल □□□□.

वर्ष 2021-22 के दौरान□जब कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटाए जा रहे थे□एनआईपीएफपी ने संस्थान के संचालन के संबंध में ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में एक सफल रूपांतरण किया। तथापि□ऑनलाइन कार्यक्रम□ प्रशिक्षण और ज्ञान का प्रसार अकादमिक कर्मचारियों और सलाहकारों को उनकी इष्टतम क्षमता पर काम करने के लिए निरंतर लचीलापन प्रदान करता रहा।

आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर रिपोर्ट□

एनआईपीएफपी अपने मुख्य कर्मचारियों के वेतन व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुदान को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से प्राप्त होता है। वेतन व्यय का शेष भाग तथा अन्य प्रशासनिक एवं पूंजीगत व्यय संस्थान के अपने संसाधनों से पूरे किए जाते हैं। अनुदान के अलावा□संस्थान विभिन्न मंत्रालयों के लिए परियोजनाएं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर भी राजस्व अर्जित करता है। संस्थान के स्वयं के संसाधनों से होने वाले व्यय का प्रतिशत 2020-21 में 59.10 प्रतिशत था□जो 2021-22 में घटकर 47.14 प्रतिशत□ हो गया।

घटनाक्रम□

नियुक्तियां □

- डॉ. आर. कविता राव ने □□ जून □□□□ को एनआईपीएफपी के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

[1]यह कमी मुख्य रूप से इस वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 में 1 जनवरी, 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि के संवितरण के कारण हुई है।

- डॉ मनीष गुप्ता ने □9 नवंबर □□□□ को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ. रुद्राणी भट्टाचार्य ने □9 नवंबर □□□□ को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- डॉ अमेय सप्रे ने □9 नवंबर □□□□ को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री पंकज कुमार सिन्हा ने □ सितंबर □□□□ को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

सेवानिवृत्ति□

- श्री राजू □□ मई □□□□ को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।
- श्री पूरनचंद उपाध्याय □□ सितंबर □□□□ को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।
- श्री नवीन कुमार सिंह □□ दिसम्बर □□□□ को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।
- श्री परविंदर कपूर □□ जनवरी □□□□ को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।

त्यागपत्र □

- डॉ. सब्यसाची कार□आरबीआई प्रोफेसर ने त्यागपत्र दे दिया और वे □□ मई □□□□ को कार्यमुक्त कर दिए गए ।
- डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती□निदेशक ने त्याग-पत्र दे दिया और वे □□ मार्च □□□□ को कार्यमुक्त कर दिए गए। □
- डॉ. इला पटनायक□प्रोफेसर ने त्यागपत्र दे दिया और □□ मार्च □□□□ को कार्यमुक्त कर दिए गए। □

अनुसंधान क्रियाकलाप

पूर्ण किए गए अध्ययन

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

.कोविड महामारी और राजस्थान का वित्त : मुद्दे और विकल्प – सितम्बर 2021 से मार्च 2022.

प्रायोजक: मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक रूपांतरण परामर्श परिषद (सीएमआरईटीएसी)

दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता और स्मृति मेहरा

उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य हैं (क) राज्य सरकार के नियंत्रण में संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण करना, ख) निकट भविष्य में राज्य के राजस्व पर प्रभाव का आकलन करने के लिए संघ के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण करना, ग) कोविड-19 द्वारा कारित आर्थिक आघात के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक राजस्व और व्यय पक्ष उपायों को शुरू करने में राज्य की मदद के लिए केंद्र और राज्यों पर कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के प्रभाव का विश्लेषण करना, और (ग) संभावित तीसरी लहर के हो सकने वाले आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना और ऐसी किसी भी घटना के लिए राज्य को आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करने के तरीकों का सुझाव देना।

. और दिसम्बर से सितम्बर तक मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की द्वि-वार्षिक समीक्षा।

प्रायोजक मध्य प्रदेश सरकार

दल प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

उद्देश्य यह मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य के वित्त की एक स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया और राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम अधिनियम) के अनुपालन के भाग के रूप में तैयार और प्रस्तुत की जाती है। मूल्यांकन रिपोर्ट इन दो वर्षों के लिए राजकोषीय प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख निष्कर्षों और पाठों का सार प्रस्तुत करती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के लक्ष्यों के लिए राज्य के अनुपालन को उजागर करने के अलावा, रिपोर्ट में राजकोषीय प्रबंधन की व्यापक प्रवृत्ति भी शामिल होती है। बजटीय योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार की क्षमता का आकलन करने के प्रयोजनार्थ परिणामों को ध्यान में रखते हुए आय और व्यय से संबंधित बजटीय अनुमानों का विश्लेषण किया गया था।

. वर्ष के लिए राज्य एफआरबीएम अधिनियम के सिक्किम सरकार द्वारा किए जा रहे अनुपालन की समीक्षा। अगस्त से मार्च.

प्रायोजक सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह

उद्देश्य: रिपोर्ट का उद्देश्य सामान्य रूप से राज्य के वित्त और विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करना है;

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफआरबीएम अधिनियम के उपबंधों के लिए राज्य सरकार का अनुपालन। इनमें घाटे, ऋण और अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य वित्तीय व्युत्पन्नों से संबंधित राजकोषीय लक्ष्य शामिल हैं।
- समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन: एफआरबीएम अधिनियम राज्य को अपनी मध्यम अवधि की वित्तीय योजना (एमटीएफपी) के साथ एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान करता है।
- राजस्व प्रयास, केंद्रीय अंतरणों, व्यय पैटर्न और ऋण प्रबंधन के संदर्भ में राज्य के वित्त का आकलन।

. सिक्किम के लिए मध्यम अवधि राजकोषीय योजना : से . जून से अगस्त .

प्रायोजक: सिक्किम सरकार

दल: प्रताप रंजन जेना

उद्देश्य: रिपोर्ट ने सिक्किम सरकार के लिए वर्ष से के लिए मध्यम अवधि वित्तीय योजना (एमटीएफपी) प्रस्तुत की। एमटीएफपी ने आगामी बजट वर्ष और दो बाहरी वर्षों में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों और अनुमानित वित्तीय लक्ष्यों की जानकारी प्रदान की। रिपोर्ट मौजूदा मैक्रो-वित्तीय वातावरण के आधार पर और सिक्किम में एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। रिपोर्ट में एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुरूप बजट वर्ष सहित तीन वर्षों के लिए राजकोषीय व्युत्पन्नों का अनुमान लगाया गया है।

. गर्भवती महिला मजदूरों के मध्य बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर सशर्त नकद हस्तांतरण का प्रभाव: मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना मध्य प्रदेश से साक्ष्य। फरवरी से नवंबर .

प्रायोजक: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश

दल: भावेश हजारिका दिनेश कुमार नायक एन.आर. भानुमूर्ति कनिका गुप्ता और मनीष प्रसाद

उद्देश्य: मध्य प्रदेश सरकार 2018 से पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए राज्य-विशिष्ट सशर्त नकद हस्तांतरण योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना (एमएमएसएसपीएसवाई) लागू कर रही है। गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य के संबंध में संचालित अध्ययन इस बात का विश्लेषण करने पर केंद्रित है कि एमएमएसएसपीएसवाई ने पंजीकृत (पीडब्ल्यू) मजदूरों के बीच बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को किस हद तक आगे बढ़ाया है। यह योजना जागरूकता निधि प्रवाह (डिजाइन और विलंब) व्यय प्रोफ़ाइल और योजना कार्यान्वयन के बारे में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की धारणा जैसे कार्यान्वयन और शासन संबंधी मुद्दों का भी विश्लेषण करता है।

□.□हरियाणा में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत यूएलबी को निधियों के हस्तांतरण का अध्ययन : एक समालोचनात्मक समीक्षा। जून-दिसम्बर □□□□.□

प्रायोजक□हरियाणा का छठा वित्त आयोग

दल□मनीष गुप्ता, स्मृति बहल और संप्रीतकौर

उद्देश्य□इस अध्ययन में हरियाणा में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की रिपोर्टों की समीक्षा करना□उनमें से प्रत्येक द्वारा अपने सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और राज्य में यूएलबी को धन (हस्तांतरण और अनुदान) देने में उनके द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करना और छठे राज्य वित्त आयोग को विभिन्न श्रेणियों के शहरी स्थानीय निकायों के बीच हस्तांतरण मानदंड□मात्रा और वितरण पद्धति के बारे में सुझाव देना शामिल है।

वित्त मंत्रालय के लिए पूर्ण किए गय अनुसंधान क्रियाकलाप□

□.□निजी क्रिप्टोकरंसी और स्टेबल कॉइंस के अभ्युदय की वित्तीय□विधिक और सुरक्षा संबंधी विवक्षाओं पर टिप्पण। अप्रैल □□□□से मार्च□□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल□इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□दुनिया भर में निजी वर्चुअल मुद्राओं के तेजी से उभरने से तकनीकी प्रगति में तेजी आई है जो वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में मदद कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र तकनीक संभावित रूप से संव्यवहारों को स्टोर और सत्यापित करने का एक अधिक सुरक्षित तरीका प्रस्तुत करती है। विकेंद्रीकृत वित्त (डी-फाई) सहित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का बढ़ता विकेंद्रीकरण अधिक पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन प्रदान करता है। हालाँकि□निजी वर्चुअल मुद्राओं को अपनाने से विभिन्न वित्तीय सेवाओं के विधि निर्माताओं□ मौद्रिक प्राधिकरणों और विनियामकों के समक्ष साथ-साथ अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह टिप्पण वित्तीय बाजार जोखिमों पर चर्चा करता है□जिसमें क्रिप्टो-समर्थित उधार और मार्जिन ट्रेडिंग से उत्पन्न जोखिम शामिल हैं। टिप्पण इसके उपरांत स्टेबल कॉइंस से उभरने वाले विशेष जोखिमों पर चर्चा करता है□जिसमें मुद्रा प्रतिस्थापन के जोखिम और भंडार की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम भी शामिल हैं।

एक बार जब किसी विशेष क्षेत्राधिकार में विनियामक और विधि निर्माता वर्चुअल मुद्राओं के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर निर्णय लेते हैं (चाहे इसे प्रतिबंधित करना या विनियमित करना और यदि विनियमित करना है□तो विनियमन का स्तर) तो अनेक विधिक विचारों का का विचारण किया जाएगा। टिप्पण में लाइसेंसिंग/पंजीकरण ढांचे□सूचना प्रकटीकरण के लिए ढांचे□विवेकपूर्ण विनियमों और आभासी मुद्राओं और व्युत्पन्नों की प्रकृति जैसे वर्चुअल मुद्राओं को अपनाने से उत्पन्न विधिक विवक्षाओं पर चर्चा की गई है□जिसमें उनके उपयोग के मामले और उसकी सीमा□वर्चुअल मुद्राओं के माध्यम से उपयोग□ उधार□सीमा पार प्रेषण आदि शामिल है।

□.□केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) पर टिप्पण और समूची विश्व का हालिया घटनाक्रम। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□ आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□यह टिप्पण सीबीडीसी को परिभाषित करने के दृष्टिकोण□उनकी प्रमुख विशेषताओं□ डिजाइन सुविधाओं और कुछ संबंधित विधिक□विनियामक और वित्तीय विचारों को निर्धारित करता है। विभिन्न केंद्रीय बैंकों (आरबीआई सहित) के भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा संचालित वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर टिप्पण उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सीबीडीसी की शुरुआत के लिए प्रमुख प्रेरणाओं पर चर्चा करता है। पहचान की गई प्रमुख प्रेरणाएँ हैं: वित्तीय समावेशन□भुगतान□वित्तीय स्थिरता और बेहतर मौद्रिक नीति संचरण। टिप्पण इसकी मौद्रिक नीति के लिए सीबीडीसी को शुरू करने की विवक्षाओं□प्रभुत्व राजस्व□सीबीडीसी और बैंक निक्षेपों के बीच प्रतिस्थापन के कारण बैंक चलाने की संभावना पर चर्चा करता है।

□.□प्रभुत्वधारक रेटिंग एजेंसियों द्वारा समीक्षा बैठकों के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण और टिप्पण। अप्रैल □□□□ से मार्च□□□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□प्रभुत्वधारक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान करना। वित्तीय वर्ष □□□□□□ के दौरान मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज□फिच रेटिंग्स□स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी) ग्लोबल रेटिंग्स और रेटिंग एंड इनवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन (आर एंड आई) इंक के साथ बैठक के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए थे:

- अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुति
- सचिव (ईए) के लिए वार्ता बिंदु
- रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रश्नावली/चर्चा के विषयों पर प्रतिक्रियाएं

□.□ वित्तीय स्थायित्व पर मासिक रिपोर्टें। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□मासिक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय बाजार के विकास□भारतीय वित्तीय बाजारों में हाल के घटनाक्रम जैसे मुद्रा बाजार की स्थिति□सरकारी बॉन्ड बाजार□कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार□ विदेशी मुद्रा बाजार और शेयर बाजार पर पकड़ बनाना है। यह टिप्पण यील्ड□स्प्रेड□स्टॉक मार्केट इंडेक्स मूवमेंट□विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई□और म्यूचुअल फंड (एएफ□निवेश जैसे परिवर्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बैंकिंग□गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)□बीमा और पेंशन क्षेत्रों में

विकास मासिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के कुछ अन्य खंड हैं। रिपोर्ट बाजार आधारित वित्तीय तनाव सूचकांक (एफएसआई) जैसे मुद्रा बाजार एफएसआई□बांड बाजार एफएसआई□इक्विटी बाजार एफएसआई और विदेशी मुद्रा बाजार एफएसआई का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है।

□.□ भारत में बैंकिंग क्षेत्र के आकार पर टिप्पण तथा आकार में वृद्धि के लिए उपाय। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□टिप्पण का उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र के आकार का अध्ययन करना है और यह पता लगाना है कि क्या बैंकिंग क्षेत्र के आकार को बढ़ाने की गुंजाइश है। पत्र में पाया गया है कि सूक्ष्म□मध्यम और लघु उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के समक्ष आने वाले संभावित रूप से निवारणयोग्य क्रेडिट अंतर को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के आकार को बढ़ाने की गुंजाइश है। बढ़ते गैर-वित्तीय क्षेत्र की ऋण मांग को पूरा करने के लिए भी बैंकों की आवश्यकता है। इसके उपरांत टिप्पण बैंकिंग क्षेत्र के आकार का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वीकार्य मानदंडों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में बैंकों की कुल संपत्ति□सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बैंकों का कुल राजस्व□ प्रति 100□000 व्यक्तियों पर शाखाओं की संख्या और क्रेडिट-जीडीपी अनुपात बैंकिंग क्षेत्र के आकार का आकलन करने के लिए कुछ संकेतक हैं। जबकि इस क्षेत्र के आकार की कई संकेतकों के माध्यम से बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है□टिप्पण से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय तुलना की सुविधा के लिए और बैंकिंग क्षेत्र के आकार को नीतिगत वातावरण से जोड़ने के लिए□बैंकों का क्रेडिट-जीडीपी अनुपात एक उचित उपाय प्रतीत होता है ।

यह टिप्पण ब्राजील□रूस□भारत□चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) अर्थव्यवस्थाओं□दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए बैंकों के क्रेडिट-जीडीपी अनुपात के प्रक्षेपवक्र की तुलना प्रस्तुत करता है। टिप्पण अंत में विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसके तहत एमएसएमई और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के क्रेडिट अंतर का निवारण किया जा सकता है।

□.□ □भारत के लिए वित्तीय तनाव संकेतकों पर टिप्पण। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□टिप्पण उन परिवर्तियों की चर्चा प्रस्तुत करता है जो वित्तीय प्रणाली में तनाव को जकड़ सकते हैं और वित्तीय तनाव सूचकांक के निर्माण के लिए एक पद्धति पर चर्चा करते हैं। भारत के लिए वित्तीय तनाव सूचकांक का निर्माण वित्तीय बाजार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मुद्रा बाजार□इक्विटी बाजार□बांड बाजार□विदेशी मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र से लेकर डेटा तक किया जाता है। परिवर्तियों का चयन वित्तीय तनाव सूचकांक पर साहित्य के अवलोकन और सार्वजनिक डोमेन में उच्च आवृत्ति डेटा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्रेडिट जोखिम को जकड़ने के प्रमुख संकेतकों में मुद्रा बाजार में प्रसार और सरकारी बांड बाजार में प्रसार (प्रतिफल वक्र की स्थिरता या सपाटता) शामिल हैं। इसके उपरांत ट्रिकप्पण इक्विटी

बाजार में अधिक मूल्यांकन और अस्थिरता और बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्रों और विदेशी मुद्रा बाजार में उत्तोलन और तनाव को जकड़ने के लिए संकेतकों की चर्चा प्रस्तुत करता है।

□.□ □मैक्रो-डैशबोर्ड : वित्तीय बाजारों में उभरते तनाव को जकड़ने वाले संकेतकों का दृश्य प्रतिनिधित्व्। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□मैक्रो-डैशबोर्ड उन प्रमुख परिवर्तियों की दृश्य प्रस्तुति है जो अर्थव्यवस्था में वित्तीय तनाव के आकलन में मदद करते हैं। ये परिवर्ती विभिन्न वित्तीय बाजारों जैसे बांड बाजार□मुद्रा बाजार□विदेशी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में स्थितियों को जकड़ते हैं। एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्रों में तनाव का आकलन करने के लिए संकेतक भी मैक्रो-डैशबोर्ड में शामिल हैं।

मैक्रो-डैशबोर्ड में प्रत्येक ग्राफ़ अपने 25वें शतमक□माध्यिका और 75वें शतमक मानों के साथ चरों की दीर्घकालीन समय श्रृंखला (10 वर्ष) दिखाता है। डैशबोर्ड में एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता को कम समय सीमा (एक वर्ष) या लंबी समय सीमा के लिए ग्राफ़ की कल्पना करने का विकल्प देती है।

□.□ □वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण और प्रतितोष एजेंसी पर टिप्पण। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ने 2013 में भारतीय वित्तीय संहिता (आईएफसी) का मसौदा तैयार किया - एक एकीकृत कोड जिसने वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रति सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया। आईएफसी ने भारत में वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को □विक्रेता-सावधान□दृष्टिकोण अपनाने वाले तंत्र की ओर रूपांतरित होने पर ध्यान केंद्रित किया। वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण (एफसीपी) विधेयक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सभी ग्राहकों के संबंध में बुनियादी उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों को शामिल करके और खुदरा ग्राहकों के संबंध में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा को मान्यता देकर एफएसएलआरसी की सिफारिशों का पालन करता है।

अन्य उत्पादों और सेवाओं की तुलना में वित्तीय उत्पाद और सेवाएं अद्वितीय चुनौतियां पेश करती हैं। इसके परिणामस्वरूप□उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम□2019 (सीपीए□2019) जैसी विधियां□जो व्यापक रूप से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं□और परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती हैं□और निजी एवं सरकारी दोनों ही के द्वारा संचालित गतिविधियों को कवर करती हैं□सार्वजनिक उद्यम□वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। उपर्युक्त मतभेदों को व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने के बावजूद□भारत में वर्तमान में कोई विशेष विधि नहीं है जो वित्तीय उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है।

इसे संबोधित करने के लिए□नवंबर 2018 में एफ़सीपी विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करने के बाद से वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उभरती घटनाओं और मुद्दों पर अनुसंधान करने के लिए टिप्पण तैयार किया

गया था। टिप्पण प्रासंगिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसने अब आवश्यक सीमा तक एफसीपी विधेयक को अद्यतन करने के लिए वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में स्थान ग्रहण कर लिया है।

□.□ वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक□2017 के संदर्भ में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए टिप्पण□ और उनका समाधान करने के लिए सुझाए गए उपाय। अप्रैल □□□□ से मार्च□□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□टिप्पण वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को वापस लेने के लिए उद्धृत तीन प्राथमिक कारणों पर प्रकाश डालता है□और 2018 के बाद से विकास के आलोक में उन चिंताओं के गुणों का विश्लेषण करता है। टिप्पण इसके संबंध में आवश्यक सीमा तक प्रस्तावित सिफारिशों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशों का विश्लेषण किया गया है: (i□बेल-इन□ii□निक्षेप बीमा□और (iii□सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ढांचे का क्रियान्वयन। टिप्पण में उन अन्य चिंताओं पर भी चर्चा की गई□जिनका विशेष रूप से निकासी के प्रस्ताव में उल्लेख नहीं किया गया था□लेकिन जिनके निराकरण से एफआरडीआई विधेयक को और अधिक कुशल और स्वीकार्य बनाने में मदद मिल सकती है।

□□.□केंद्रीय सरकार के ऋण के लिए आधारभूत ऋण संधारनीयता विश्लेषण (डीएसए)। अप्रैल □□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक□आर्थिक कार्य विभाग□वित्त मंत्रालय

दल: इला पटनायक और डीईए दल

उद्देश्य□ऋण संधारणीयता विश्लेषण (डीएसए) यह आकलन करता है कि क्या मौजूदा नीतियों के अंतर्गत कोई देश या सरकार मध्यम और लंबे समय में अपने ऋण को पुनर्निमित किए बिना या उसमें चूक किए बिना नीतिगत समायोजन करने में सक्षम होगी जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से बड़े पैमाने पर वृहद हैं। इस प्रकार□सार्वजनिक ऋण का एक स्थायी स्तर वह स्तर है जो मध्यम और लंबी अवधि में सेवा योग्य है।

यह टिप्पण किसी दिए गए वर्ष के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात में परिवर्तन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है□ जिसमें ऋण-जीडीपी अनुपात में परिवर्तन के प्रमुख कारकों जैसे ब्याज दर□विनिमय दर□वास्तविक विकास दर और प्राथमिक संतुलन के योगदान को दर्शाया गया है। अगले 10 वर्षों के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात (2021-22 से 2030-31 तक) ब्याज दरों की गणना के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके अनुमानित किया गया है: पहला□सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रचलित आय (वाईटीएम) पर प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करना जिसमें बाद के वर्षों के लिए गिरावट की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है और□दूसरा□नए और मौजूदा सरकारी सुरक्षा निर्गमों के लिए ब्याज दर के बीच विभेद किया जाता है। इन्हें प्रभावी ब्याज दर की गणना के लिए संयोजित किया जाता है।

□□.□राजस्व विभाग□वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखापरीक्षा। जून-दिसम्बर□□□□.□

प्रायोजक□केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट।

दल: सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 की धारा 4(1) में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उप-धारा (1) (ख) के अधीन सूचीबद्ध प्रकृति की जानकारी का स्वत: प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। विभागों को सूचना का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता होती है जो आरटीआई आवेदकों द्वारा सबसे अधिक बार मांगी जाती है और वे इसे अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रावधान के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय/लोक प्राधिकरण को प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/लोक प्राधिकरण के तहत संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से हर साल तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज की लेखापरीक्षा करानी चाहिए और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एनआईपीएफपी को सीआईसी द्वारा राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार (जीओआई) के तहत 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों के तीसरे पक्ष लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। अब तक एनआईपीएफपी ने 2019-20 के लिए असाइनमेंट पूरा कर लिया है और चूंकि यह एक वार्षिक मामला होगा एनआईपीएफपी आने वाले वर्षों के लिए काम करेगा। एनआईपीएफपी ने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान/शुल्क आदि के राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम किया है।

अन्य संस्थाओं/संगठनों के लिए पूर्ण किए गए अनुसंधान क्रियाकलाप

. भारत मे उप-राष्ट्रीय राजवित्तीय संधारणीयता विश्लेषन – ओडिशा और हिमाचल प्रदेश अप्रैल-सितम्बर

प्रायोजक: दि वर्ल्ड बैंक, नई दिल्ली

दल: पिनाकी चक्रवर्ती, मनीष गुप्ता और स्मृति मेहरा

उद्देश्य: अध्ययन का उद्देश्य दो भारतीय राज्यों - ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के लिए एक मध्यम अवधि का वित्तीय संधारणीयता विश्लेषण करना था। इसमें प्रत्येक राज्य की विशिष्ट नीतिगत प्राथमिकताओं और बाधाओं के आधार पर परिदृश्यों का निर्माण शामिल था। रिपोर्ट का हिमाचल भाग राज्य सरकार की ओर से डेटा की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

. अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास संबंधी दृष्टिकोण : ईएसी-पीएम के लिए टिप्पण - वर्ष के दौरान ईएसी-पीएम के लिए चार तिमाही रिपोर्टें पूरी की गईं।अक्तूबर से सितम्बर .

प्रायोजक: प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम)

दल: पिनाकी चक्रवर्ती, आर. कविता राव, लेखा चक्रवर्ती, प्रताप आर. जेना, मनीष गुप्ता, रुद्राणी भट्टाचार्य, अमय सपरे, श्रुति त्रिपाठी और दिनेश के. नायक

उद्देश्य: अर्थव्यवस्था का तिमाही मूल्यांकन और विकास दृष्टिकोण। चार त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं: (i जून-सितंबर iii अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च iii अप्रैल-जून और (i जुलाई-अगस्त

□.□ दो अध्ययन: (1) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस): पुनर्गठन और युक्तिकरण और (2) कोविड-उपरांत राजकोषीय ढांचा: वर्ष के दौरान ईएसी-पीएम के लिए मुद्दे और विकल्प पूरे किए गए। जुलाई-सितम्बर□□□□.□

प्रायोजक□ प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम)

दल□ए.एन. झा, यश जलुका और पिनाकी चक्रवर्ती

उद्देश्य□(1) अध्ययन ने सीएसएस में विभिन्न मुद्दों की पहचान की और उन डिजाइन और परिचालन परिवर्तनों का सुझाव दिया जो उन्हें बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं। यह तर्क□संवैधानिक पृष्ठभूमि□ मूल्यांकन□पिछली समितियों की सिफारिशों□मौजूदा ढांचे और मौजूदा मुद्दों और उनमें चुनौतियों को हल करने के सुझावों का व्यापक विश्लेषण था।

(2) अध्ययन ने कोविड के बाद के राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों पर विभिन्न सरकारों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया। अध्ययन ने विभिन्न मुद्दों और विकल्पों पर गौर किया और राजस्व घाटे के साथ-साथ राजकोषीय विचलन के उचित स्तर को लक्षित करने पर विशिष्ट सिफारिशें कीं।

□.□ राज्य वित्त में उभरते मुद्दे : राज्य बजट □□□□□□□ का विश्लेषण□ अप्रैल-सितम्बर□□□□.□

प्रायोजक□एनआईपीएफपी

दल□पिनाकी चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता

उद्देश्य□यह अध्ययन सभी □□राज्यों के नवीनतम बजट (अर्थात वित्तीय वर्ष □□□□□□□ के लिए बजट) के आंकड़ों का विश्लेषण करके राज्य के वित्त में उभरते मुद्दों और राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करता है।

□.□ न्याय चुनौती के लिए डेटा। दिसम्बर □□□□ से जून □□□□.□

प्रायोजक□ व्याम फोरम फॉर सिटिजनशिप

दल□इला पटनायक□देवेंद्र दामलेआउर करण गुलाटी

उद्देश्य□अध्ययन का उद्देश्य भारत की संविदा प्रवर्तन मशीनरी को समझने के लिए एक डेटासेट बनाना है। इसमें शामिल होंगे:

- संविदा प्रवर्तन परिवादों पर मामला-स्तर समय श्रृंखलाबद्ध डेटासेट□राज्यों के चुनिंदा जिलों और उच्च न्यायालयों में संविदाओं से संबंधित विवादों पर नज़र रखना। डेटा को समय-समय पर उत्पाद के रूप में जारी किया जाएगा।
- संविदा प्रवर्तन सूचकांक□जो उपरोक्त डेटा से उत्पन्न होगा। इस आधार पर विभिन्न न्यायालयों और राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी और तुलना करने के लिए समय-समय पर सूचकांक की गणना की जाएगी। तब उत्पन्न परिणामों का उपयोग नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता की निश्चितता□इसका उद्देश्य नियमित अभिव्यक्ति मिलान

या वर्गीकरण एल्गोरिथम के माध्यम से निर्णय/आदेश के असंरचित पाठ से संविदा प्रवर्तन से संबंधित जानकारी निकालने के लिए एक पाठ प्रक्रमण मॉड्यूल विकसित करना है।

□.□ भेषजिक औषधियों की सार्वजनिक अधिप्राप्ति और गुणवत्ता नियंत्रण पर अध्ययन। जून □□□□ से अप्रैल □□□□.□

प्रायोजक□ठाकुर फैमिली फाउंडेशन□इंक.

दल□इला पटनायक□हरलीन कौर□मधुर मेहता□आशिम कपूर और सिद्दार्थ श्रीवास्तव

उद्देश्य□इस अध्ययन का उद्देश्य है:

- सार्वजनिक अधिप्राप्ति पर केंद्र और राज्य सरकार के व्यय पर अनुसंधान□अधिप्राप्ति प्रक्रिया मूल्यांकन□निविदा प्रक्रिया□नीतियों को काली सूची में डालना□भारत दवा उद्योग में दवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रणाली का लाभ कैसे उठा सकता है□क्या दवाओं की खरीद के लिए विशिष्ट सार्वजनिक अधिप्राप्ति विधि की आवश्यकता है□राज्यों को दवाओं की आपूर्ति करने वाली राष्ट्रीय कंपनियों की रूपरेखा□अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सुगम पोर्टल पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रकाशित मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) न रखने वाली दवाओं के बारे में जानकारी की भूमिका□और बार-बार अपराधियों पर एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं।
- अध्ययन गुणवत्ता के दृष्टिकोण से केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक अधिप्राप्ति एजेंसियों का एक प्रतिनिधि क्रॉस-सेक्शन द्वारा सार्वजनिक खरीद पर शोध अध्ययन के लिए दो पत्र तैयार करेगा।

□.□ वैश्विक दक्षिण में राजवित्तीय संघवाद। अगस्त □□□□ से दिसम्बर □□□□.□

प्रायोजक□सार्वजनिक वित्त परियोजना के अंतर्गत बिल एंड मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)

दल: लेखा चौधरी□गुरलीन कौर□अमनदीप कौर□जेनेट फरीदा जैकब□अनंदिता घोष और दिव्य रंजन

उद्देश्य□वैश्विक दक्षिण में संघवाद सम्मेलन की कार्यवाही-वृत्तांत की तैयारी। इस परियोजना में केन्या□इथियोपिया□दक्षिण अफ्रीका□नेपाल और भारत के राजकोषीय संघवाद पर चर्चा की गई है जिसमें राजस्व असाइनमेंट□व्यय असाइनमेंट□अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण आदि शामिल है।

□.□ बालकों के लिए सार्वजनिक वित्त : गुजरात□ओडिशा□कर्नाटक और तेलंगाना का राज्य-स्तरीय विश्लेषण। अगस्त □□□□ से दिसम्बर□□□□.□

प्रायोजक□सार्वजनिक वित्त परियोजना मे अभिनवता के अंतर्गत बीएमजीएफ

दल□लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर (अनिंदिता घोष [दिसम्बर 2020 तक] और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)

उद्देश्य□स्कूली उम्र के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे अब □प्रभावी रूप से स्कूल से बाहर□की श्रेणी में हैं। वे □डिजिटल डिवाइड□इंटरनेट तक पहुंच की कमी) के कारण शिक्षा से वंचित हैं जो एक ऐसी स्थिति है□जो महामारी के कारण सामने आई है। इस अध्ययन में□हम कर्नाटक□गुजरात□ओडिशा और तेलंगाना राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए□महामारी के प्रति भारत की केंद्र और उप-राष्ट्रीय सरकार की प्रतिक्रियाओं के

विशिष्ट संदर्भ में बाल बजट का पता लगाते हैं। इन विशिष्ट राज्यों के बाल बजट पर हमारे अध्ययन से निष्कर्ष वित्त मंत्रालय को केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जवाबदेही के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन उपकरण के रूप में बाल बजट को मजबूत करने में मदद करेंगे।

□.□ पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय राजवित्तीय स्थानांतरण। अगस्त से अगस्त□□□□□ अगस्त□□□□□.□

प्रायोजक: स्व-प्रारंभ की गई

दल□लेखा चौधरी, अमनदीप कौर और रंजन मोहंती

उद्देश्य□कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के मद्देनजर□यह पत्र भारत में पारिस्थितिकीय वित्तीय क्षेत्र में फ्लाईपेपर प्रभावों के अनुभवजन्य साक्ष्य की पड़ताल करता है। पैनल डेटा मॉडल का उपयोग करते हुए हम विश्लेषण करते हैं कि क्या अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण या राज्य के अपने राजस्व का प्रभाव राज्य स्तर पर पारिस्थितिकी पर व्यय प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। अर्थमितीय विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य की अपनी आय के बजाय कुल अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण उप-राष्ट्रीय सरकार के स्तर पर पारिस्थितिक व्यय का निर्धारण करते हैं। फ्लाईपेपर प्रभावों की प्रभावकारिता के प्रमाण या तो नौकरशाही के वित्तीय व्यवहार या पारिस्थितिक वित्तीय स्थान की बहिर्जातता के बारे में आर्थिक एजेंटों के वित्तीय भ्रम से उपजे हैं। परिणाम तब स्थिर होते हैं जब मॉडल पारिस्थितिक परिणामों और जनसांख्यिकीय परिवर्तियों के लिए नियंत्रित होते हैं। तथापि□अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण के अलग-अलग स्तरों - अनुदान और कर हस्तांतरण - पर फ्लाईपेपर प्रभावों के साक्ष्य मिश्रित हैं। इस परिणाम की नीतिगत विवक्षाएं हैं और यह राज्य सरकार के स्तर पर पारिस्थितिक व्यय पर अंतर-सरकारी हस्तांतरण की प्रभावकारिता के बारे में वित्त मंत्रालय को अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है। यह पत्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस मीटिंग्स 2021□आइसलैंड विश्वविद्यालय□रेकजाविक (ऑनलाइन)□18 अगस्त 2021□और सार्वजनिक वित्त पर एनआईपीएफपी-आईआईपीएफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन□29 जून 2021 में प्रस्तुत किया गया था। यह पत्र जनवरी 2022 में लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□ न्यूयॉर्क में एक कार्यकारी पत्र रूप में प्रकाशित हुआ था।

□□.□असंदत्त देखरेख अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय नीति। फरवरी □□□□ से दिसम्बर□□□□□.□

प्रायोजक□स्व-प्रारंभ की गई (अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी के साथ शोध सहयोग) दल□लेखा चक्रवर्ती

उद्देश्य□देख-रेख अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय अदृश्यता चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा □□□□ में सभी राज्यों के लिए प्रकाशित समय उपयोग सर्वेक्षण□राष्ट्रीय लेखा प्रणाली□□99□के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए एक अभिनव डेटासेट है□जिसने अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों के घरेलू और सामाजिक स्तरों को शामिल करने के लिए उत्पादन सीमा का विस्तार किया। इन अनुमानों की जेंडर बजटिंग के लिए नीतिगत विवक्षाएं हैं। यह पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा चल रही जेंडर बजटिंग पहलों के लिए विश्लेषणात्मक बैकअप (देखभाल अर्थव्यवस्था पर) प्रदान करता है। यह पत्र □□ जून □□□□ को जिनेवा में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स (आईएएफएफई□की बैठक में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है।

□□.□शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक समानता और वित्तीय स्पेस में लैंगिक बजट की क्षेत्रीय व्यय प्रभावशीलता: एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन। सितम्बर □□□□ से दिसम्बर□□□□□.□

प्रायोजक□स्व-प्रारंभ की गई परियोजना (पूर्व संस्करण अटलांटा में अमेरिकी आर्थिक एसोसिएशन की बैठकों में प्रस्तुत किया गया था)। □

दल□लेखा चौधरी

उद्देश्य□यह पत्र एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था ढांचे के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में लिंग के समान रूप से वितरित समकक्ष□परिवर्तियों पर□विशेष रूप से लिंग बजट की प्रक्रियाओं और विश्लेषणात्मक ढांचे के संदर्भ में□राजकोषीय नीति प्रथाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। एनआईपीएफपी जेंडर बजटिंग में अग्रणी रहा है और इसने □□□□ में जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जेंडर बजटिंग की एनआईपीएफपी पद्धति अपरिवर्तित बनी हुई है□हम लैंगिक समानता परिणामों और वित्तीय स्थान पर जेंडर बजट के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए समय श्रृंखला डेटा का उपयोग कर सकते हैं। । इस अध्ययन के निष्कर्ष एशिया-प्रशांत के देशों में वित्त मंत्रालय के लिए स्पष्ट नीतिगत इनपुट के साथ लिंग बजट की एक अनुभवजन्य समीक्षा प्रदान करते हैं।

□□.□कोविड-19 और एशिया-प्रशांत में आर्थिक संवृद्धि पैकेजों का विश्लेषण। अगस्त □□□□ से मई □□□□.□

प्रायोजक□ लोक वित्त-पोषण परियोजना में नवाचार के अंतर्गत बीएमएफजी। □

दल□लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर, दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब

उद्देश्य□पत्र आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों के राजकोषीय और मौद्रिक नीति घटकों का विश्लेषण करता है□ जिसमें लिंग और मानवाधिकार मूल्यांकन शामिल हैं। चार विशिष्ट घटक हैं:

- खाद्य सुरक्षा
- सामाजिक सुरक्षा
- सामाजिक आधारभूत संरचना और सेवा प्रावधान और
- आर्थिक गतिविधि और रोजगार।

एशिया-प्रशांत देशों के अनुभवजन्य साक्ष्य महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज तैयार करने में वित्त मंत्रालय को अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अध्ययन को मई 2021 में एनआईपीएफपी मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके निष्कर्ष नवंबर 2021 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और आईएलओ की बैठक में प्रस्तुत किए गए थे।

□□.□राज्य वित्त पर कोविड-19 का 'प्रतिकूल प्रभाव' : व्यय पर उभरते साक्ष्य। अगस्त □□□□ से जनवरी □□□□.□

प्रायोजक□भारत मे स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण दृष्टिकोणों के अंतर्गत बीएमएफजी : भावी मार्ग□

दल□मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता

उद्देश्य□कोविड महामारी ने राज्य के वित्त पर दोहरा दबाव डाला। राजस्व में संकुचन के साथ-साथ सार्वजनिक खर्च के विस्तार के बढ़ते दबाव ने भी स्थिति को गंभीर बनाया। □□राज्यों के साक्ष्य बताते हैं

कि □□□□□□□□ में कुल राजस्व में लगभग □ प्रतिशत की गिरावट आई है। इस गिरावट के बावजूद □राज्यों ने कुल खर्च की औसत वृद्धि दर □ प्रतिशत बनाए रखी है। सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय आर्थिक सेवाओं की तुलना में काफी अधिक दर से बढ़ा। सामाजिक सेवाओं के भीतर □स्वास्थ्य व्यय में □□ प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि □स्वास्थ्य खर्च में हासिल की गई यह वृद्धि शिक्षा □पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय की कीमत पर आई है।

□□. □भारत में मृत्युदर और चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती होने की उभरती प्रवृत्तियां। जून □□□□ से जनवरी □□□□.□

प्रायोजक □भारत मे स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण दृष्टिकोणों के अंतर्गत बीएमएफजी : भावी मार्ग□

दल □जय देव दुबे

उद्देश्य □राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए स्वास्थ्य पर सामाजिक उपभोग पर □□वें सर्वेक्षण से पता चलता है कि □□□□ से □□□□□□□ की तीन साल की अवधि में भारत में रुग्णता दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस गिरावट की भयावहता न केवल उल्लेखनीय रूप से तेज है □बल्कि पिछले दो दशकों से देश में रुग्णता के स्तर में वृद्धि के रुझान के विपरीत भी है। यह पत्र उभरते हुए पैटर्न की विश्वसनीयता को समझने के लिए पद्धति संबंधी मुद्दों का गहराई से अध्ययन करता है। मूल्यांकन की प्रासंगिकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि सर्वेक्षण में स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए विवक्षाएं हैं।

□□. □प्रति रुपया अधिक स्वास्थ्य : लोक व्यय में कुशलता और संवितरण में विलंब। मई □□□□□ से फरवरी □□□□□.□

प्रायोजक □भारत मे स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के अंतर्गत बीएमएफजी : भावी मार्ग □

दल □दीपोबोती ब्रह्मा

उद्देश्य □यह पत्र भारत में स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय का दक्षता विश्लेषण करता है। बजट से संकलित सार्वजनिक व्यय पर राज्य-स्तरीय पैनल डेटा का उपयोग करके □हम भारत में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक व्यय की दक्षता का अनुमान लगाते हैं। हम राज्यों को उनकी तकनीकी दक्षता के आधार पर रैंक भी करते हैं। इसके अलावा □राज्य स्वास्थ्य समितियों को निधि वितरण में देरी और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में रिक्तियों पर प्रशासनिक डेटा का उपयोग करते हुए □हम तकनीकी दक्षता पर उनकी लोच का अनुमान लगाते हैं।

□□. □राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतनीकरण – डेवा बैंक। अप्रैल □□□□□ से मार्च □□□□.□

प्रायोजक □एनआईपीएफपी

दल □एच.के. अमरनाथ और रोहित दत्ता

उद्देश्य □बजट दस्तावेजों से राज्य वित्त जानकारी को अद्यतन बनाना। हमारे पास □9□□□□ से □□□□□□□ बी.ई. तक की जानकारी उपलब्ध है।

□□. □डेटा शासन नेटवर्क। □□ मार्च □□□□ को समाप्त। □

प्रायोजक □आईडीएफसी फाउंडेशन एंड ऑमिड्यार नेटवर्क्स

दल: रेणुका साने, रिषभ बेली, स्मृति पसरीचा, फैज़ा रहमान, वरुण सेन बहल और त्रिशी गोयल।

उद्देश्य डेटा शासन नेटवर्क के भाग के रूप में अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्र हैं:

- गोपनीयता नीतियों की समझ को संचालित करने वाले कारकों की पहचान करना - क्या उम्र शिक्षा बौद्धिक लब्धि अंग्रेजी के साथ सहजता शहरीकरण इंटरनेट-आधारित सेवाओं से परिचय जैसे सभी कारक इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि व्यक्ति किस तरह से प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है। यह भारत में गोपनीयता अधिकारों की विभिन्न अवधारणाओं और तौर-तरीकों (अभिव्यक्ति के) का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण का भी प्रस्ताव करता है।
- डेटा सुरक्षा प्राधिकरण के लिए एजेंसी का डिज़ाइन। भारत में एक नए डेटा सुरक्षा ढांचे के निर्माण की दिशा में चल रहे काम के साथ सरकार से एक विनियामक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण (डीपीए) स्थापित करने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के साथ डीपीए को सौंपे जाने की आशा है। इस अध्ययन में हम डीपीए के निर्माण के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं।
- भारत में वर्तमान निगरानी संबंधी विधियों नीतियों और तंत्रों का अध्ययन करना। अध्ययन में वर्तमान प्रणालियों में कमियों की पहचान करने और नीतिगत पहलों का सुझाव देने का प्रस्ताव है।
- ड्रोन सीसीटीवी चेहरे की पहचान सेल टावर ट्रैकिंग एन्क्रिप्शन उपकरण इत्यादि जैसी विशिष्ट तकनीकों/अनुप्रयोगों के उपयोग के आसपास गोपनीयता के मुद्दों का अध्ययन करना।

. सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जल्द छोड़ने की जांच। अप्रैल से सितम्बर .

प्रायोजक अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय शोध अनुदान 2018.

दल युक्ता बोस प्रियंत घोष मनोहर बोडा और अरविंद सरदाना (एकलव्य मध्य प्रदेश)

उद्देश्य यह अध्ययन सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़कर निकलने की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है जिसमें निचले स्तर पर ही स्कूलों से बाहर निकलने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कूलों से बाहर निकलने की घटनाओं को समझने के प्रयास में राज्य की दो प्राथमिक आर्थिक भूमिकाओं अर्थात सार्वजनिक प्रावधान और बाजार के विनियमन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन दिल्ली शहर में स्थित है। (i कम फीस वाले निजी स्कूल (एलएफपीएस) सरकारी स्कूलों के करीबी विकल्प के रूप में उभरे हैं तथापि स्कूली शिक्षा में इस अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। अध्ययन एलएफपीएस क्षेत्र के आकार को स्थापित करने की कोशिश करता है जो एक ऐसी जानकारी है जो किसी भी योजना के लिए महत्वपूर्ण है ii बढ़ते आकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र में संस्थापकों के प्रकार के साथ राज्य की नियामक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूली शिक्षा के निजी क्षेत्र के विनियमन को रेखांकित करने वाले विधिक क्षेत्र में वास्तविक प्रथाओं को किस प्रकार अनुपालित करते हैं iii अध्ययन मौजूदा घाटे और मांग के संभावित स्रोतों को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संसाधन की आवश्यकता के अनुमान प्रस्तुत करता है।

. भारत में शिक्षा के लिए अंतर्सरकारी राजकोषीय अंतरण। अप्रैल-अक्तूबर .

प्रायोजक□विश्व बैंक

दल□संयुक्ता बोस□नुपुर और श्री हरि नायडू ए.

उद्देश्य□यह अध्ययन तीन वित्त आयोग अवधियों (□□□□□□□□में शिक्षा - स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा - के लिए अंतर-सरकारी स्थानांतरणों के रुझानों और पैटर्न का विश्लेषण करता है जिसमें समग्र वित्तीय ढांचे में कई महत्वपूर्ण नीति-प्रेरित परिवर्तन देखे गए। विश्लेषण तीन विशेष श्रेणी के राज्यों सहित □□भारतीय राज्यों के लिए किया गया है।

□□.□डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियां□अप्रैल□□□□□से मार्च □□□□.□

प्रायोजक*:* स्व-प्रारंभ

दल: सुरांजलि टंडन

उद्देश्य: अध्ययन भारत के लिए सबसे व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए स्तंभ एक और दो प्रस्तावों की विस्तार से जांच करता है।

□□.□भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति तंत्र : एल1 के लिए विकल्पों का अन्वेषण□फरवरी□□□□□से □जून□□□□□

प्रायोजक: एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में स्व-वित्तपोषित □

दल: भावेश हजारिका और आयुषी जैन

उद्देश्य□अध्ययन भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति तंत्र पर केंद्रित है। न्यूनतम लागत चयन (एल1) भारत में कई दशकों से वस्तुओं□कार्यों और सेवाओं में सार्वजनिक खरीद के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। भारत से केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी□नीति आयोग□एफआईसीसीआई आदि जैसे विभिन्न संस्थानों ने पारंपरिक पद्धति को अधिक उपयुक्त तरीके से बदलने की आवश्यकता का सुझाव दिया है जो अधिप्राप्ति के तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं पर केंद्रित है। यह अध्ययन सार्वजनिक खरीद तंत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालता है और एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में गुणवत्ता और लागत-आधारित चयन (क्यूसीबीएस) का सुझाव देता है जो हर पहलू में अधिक कुशल है।

चल रहे अध्ययन

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चल रहे अध्ययन

. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन जीवीए और निवेश में योगदान। जून से मार्च तक।

प्रायोजक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

दल इला पटनायक प्रमोद सिन्हा और रचना शर्मा

उद्देश्य अध्ययन का प्रस्ताव है

- सकल मूल्य संवर्धन जीवीए के आधार पर विकास अनुमान उत्पन्न करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में फर्मों के वार्षिक वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करें आर्थिक विकास को मापने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक।
- फर्म के बैलेंस शीट के एसेट स्टेटमेंट का उपयोग करके विनिर्माण क्षेत्र द्वारा निर्मित अतिरिक्त क्षमताओं की स्थिति और पैटर्न का अध्ययन।
- उद्योग द्वारा प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विनिर्माण के भीतर उप क्षेत्रों का बारीक विश्लेषण करना।

. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई डिजाइन रूपरेखा उभरते पैटर्न और सरकार को लागत।
अक्टूबर से जून तक।

प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी एनएचए

दल मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता

उद्देश्य योजना के एमपैनलमेंट दावों और लागत पर उभरते सबूतों की जांच का अध्ययन।

. भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए नीति निर्माण को सक्षम करने के लिए इनपुट प्रदान करना। अक्टूबर से अक्टूबर .

प्रायोजक कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन रेलवे

दल रेणुका साने

उद्देश्य चल स्टॉक में निजी निवेश कानूनी अनुपालन और क्षेत्र में विभिन्न खिलाड़ियों के कार्यों के मामले में आवश्यक नियामक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर अध्ययन करेगा। इसमें शामिल होंगे

- रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा पालन की जाने वाली मौजूदा प्रथाओं और नियामक अनुपालन पर एक नीति पत्र।
- प्रमुख देशों में फ्रेट ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षण प्रणालियों और नियामक संरचनाओं के विश्लेषण पर एक पेपर।
- माल ढुलाई स्टॉक के रखरखाव के दौरान जोखिम मूल्यांकन आपदा प्रबंधन और दायित्व के दायरे पर एक नीति पत्र।

- यात्री चल स्टॉक के रखरखाव के दौरान जोखिम मूल्यांकन आपदा प्रबंधन और दायित्व के दायरे पर एक नीति पत्र।
- प्रमुख देशों में यात्री ऑपरेटरों द्वारा अनुरक्षण प्रणालियों और नियामक संरचनाओं के विश्लेषण पर एक पेपर।
- भारतीय रेलवे के डिब्बों और वैगनों में दोषों के मात्रात्मक विश्लेषण पर एक पेपर।
- इन गतिविधियों में निजी संस्थाओं की भागीदारी पर विचार करते हुए भारत में फ्रेट रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए नियामक ढांचे पर एक नीति पत्र।
- इन गतिविधियों में निजी संस्थाओं की भागीदारी पर विचार करते हुए भारत में यात्री रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के आसपास के नियामक ढांचे पर एक नीति पत्र।

. प्रौद्योगिकी नवाचार की सार्वजनिक खरीद। नवंबर से दिसंबर .

प्रायोजक डेटा प्रबंधन और विश्लेषण और नीति आयोग भारत सरकार के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज वर्टिकल द्वारा शुरू किया गया

दल अन्ना रॉय और भाबेश हजारिका

उद्देश्य अध्ययन विशिष्ट ड्रोन प्रौद्योगिकी के साथ एक सेवा पीटीएएस के रूप में प्रौद्योगिकी की खरीद की समझ प्रदान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट एक मॉडल दस्तावेज़ विकसित करने का प्रयास करती है जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं को वितरित करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा ड्रोन की खरीद के मार्गदर्शन में एक संदर्भ के रूप में किया जा सकता है।

. वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्र उत्तराखंड सरकार देहरादून को अनुसंधान और परामर्श सहयोग। जुलाई से अगस्त .

प्रायोजक वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्र पीडीयू सीटीआरएफए उत्तराखंड सरकार

दल प्रताप रंजन जेना दिनेश नायक भाबेश हजारिका और मनीष गुप्ता

उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। इसमे शामिल है

- पीएफएम के तहत प्रमुख संवैधानिक प्रावधान अधिनियम और नियम
- मध्यम अवधि का वित्तीय ढांचा
- बजट निष्पादन और प्रतिबद्धता
- सार्वजनिक निवेश प्रबंधन
- नकद और ऋण प्रबंधन

वित्त मंत्रालय के लिए चल रहे अध्ययन

१. एनआईपीएफपी डीईए अनुसंधान कार्यक्रम। अप्रैल २०२१ से मार्च २०२२ तक।

प्रायोजक आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय

दल इला पटनायक राधिका पांडे प्रमोद सिन्हा रचना शर्मा गणेश गोपालकृष्णन देवेंद्र दामले आशिम कपूर अरुमा खान उत्सव सक्सेना सिमरन कौर राम्या राजश्री कुमार कृति वट्टल रितिका सिंह और आनंदिता गुप्ता

उद्देश्य कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एफएसएलआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सहित वित्तीय बाजारों ऋण स्थिरता का अध्ययन क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित मामलों और भुगतान और निपटान प्रणाली पीएसएस से संबंधित मुद्दों पर विभाग को अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है। भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावना पर अनुसंधान संकल्प निगम आरसी के नियमों और विनियमों का निर्माण व्यापक विदेशी निवेश कानून और वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र की स्थापना पर स्थापना से संबंधित पहलुओं के लिए अनुसंधान सहायता।

२. भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के लिए टेम्पलेट और मैनुअल का संशोधन। अप्रैल २०२१ से जून २०२१ तक।

प्रायोजक आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय

दल एच.के. अमरनाथ मनीष गुप्ता और श्री हरि नायडू ए.

उद्देश्य राज्यों को केंद्रीय स्थानान्तरण में हाल के परिवर्तनों राज्यों के बजट को केंद्रीय समर्थन कर संरचना जीएसटी की शुरूआत और योजनाओं को बंद करने के मद्देनजर भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी आईपीएफएस की सामग्री में बदलाव की आवश्यकता है। कुछ वर्गों को बंद करने की आवश्यकता है जबकि अन्य को पुनर्गठन की आवश्यकता है। अध्ययन उन अध्यायों अनुभागों तालिकाओं की जांच करेगा जिन्हें बंद किया जा सकता है जहां हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी को शामिल करने की आवश्यकता है और मौजूदा तालिका प्रारूपों में जोड़ने या हटाने का सुझाव देगा और एक प्रारूप तैयार करेगा और दो साल के लिए डेटा भरेगा। यह मौजूदा दस्तावेज़ में किए गए समायोजन में बदलाव का भी सुझाव देगा।

अन्य संस्थानों संगठनों के लिए चल रहे अध्ययन

१. ईएसी पीएम भारतीय अर्थव्यवस्था पर त्रैमासिक रिपोर्ट और ईएसी पीएम दो रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए प्रासंगिक विषयों पर दो अध्ययन। फरवरी २०२२ के बाद।

प्रायोजक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम

दल□पिनाकी चक्रवर्ती□लेखा चक्रवर्ती□मनीष गुप्ता□डॉ रुद्रानी भट्टाचार्य और दिनेश के॰ नायक

प्रायोजक□अक्टूबर □□□□ से सितंबर □□□□ की अवधि के लिए ईएसी□पीएम के साथ पहले के समझौता ज्ञापन के क्रम में□फरवरी □□□□ में पुनर्गठित ईएसी□पीएम □अक्टूबर □□□□□के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रदान करना जारी रखा जा सके और परिषद द्वारा पहचाने गए प्रासंगिक विषयों पर दो केंद्रित शोध पत्र। अब तक अक्टूबर□दिसंबर □□□□ से जनवरी□मार्च □□□□ की अवधि के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

□.□कर□नीति□और□अनुपालन के□प्रति□दृष्टिकोण□का□आकलन।□जनवरी□□□□□से□दिसंबर□□□□□.□

प्रायोजक□स्वयं पहल

दल□आर. कविता राव

उद्देश्य□करदाताओं की धारणाओं से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर बढ़ाने के सवाल पर□अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या नागरिकों द्वारा कर अनुपालन के बारे में भारत में लोगों की धारणा एक तरफ निष्पक्षता और अनुपालन में आसानी के बारे में उनकी धारणाओं से संबंधित है और कथित तौर पर दूसरे पर सरकारी खर्च से लाभ। अध्ययन में विभिन्न पृष्ठभूमि के लगभग □□□□□□ व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धारणाओं में अंतर है या नहीं। इस अध्ययन को एक पायलट माना जा सकता है जिसे बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में विस्तारित किया जा सकता है□यदि प्रारंभिक परिणाम दिलचस्प पाए जाते हैं।

□.□भूमि□बाजार□को□बेहतर□बनाना।□□अप्रैल□□□□□से□□□मार्च□□□□□तक।□

प्रायोजक□ओमिडयार नेटवर्क

दल□इला पटनायक□देवेंद्र दामले□तुषार आनंद□करण गुलाटी□विराज जोशी□विशाल त्रेहान□सिद्धार्थ श्रीवास्तव□सारंग मोहरीर□गुंटास कौर उप्पल□नमिता गोयल और अंशी शर्मा

उद्देश्य□भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है और संभवतः भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कम से कम सुधारित कारकों में से एक है। पिछले दो दशकों में विकास की बढ़ी हुई गति और परिणामी शहरीकरण ने भूमि बाजारों में मांग□संचालित परिवर्तनों को जन्म दिया है। इस अध्ययन का उद्देश्य है□

- प्रशासनिक डिजाइन और क्षमता में सुधार के लिए भूमि प्रशासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करें।
- अक्षमताओं को कम करने□लेन□देन की लागत कम करने और भूमि बाजारों में बेहतर संपत्ति अधिकार बनाने के लिए भूमि पर अधिकारों और प्रतिबंधों की भूमिका को समझें।
- भूमि बाजारों में बाजार की विफलताओं और भूमि को नियंत्रित करने वाले नियमों की भूमिका और डिजाइन को समझें।

□.□राजकोषीय□संघवाद□और□लैंगिक□समानता।□जनवरी□□□□□से□दिसंबर□□□□□तक।□

प्रायोजक□संघों का मंच

दल लेखा चक्रवर्ती और दिव्य रंगन जून तक काम किया

उद्देश्य परियोजना कर हस्तांतरण व्यय असाइनमेंट और वित्तीय विकेंद्रीकरण पर विशेष जोर देने के साथ लिंग और संघवाद के बीच प्रशंसनीय संबंधों का विश्लेषण करती है।

. एशिया प्रशांत में सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति भारत में जेंडर बजटिंग। जनवरी से अक्टूबर तक।

प्रायोजक स्वयं पहल

दल लेखा चक्रवर्ती

उद्देश्य अध्ययन एशिया प्रशांत में लिंग बजट के अनुभवों का विश्लेषण करता है भारत के विशेष संदर्भ में शासन के राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तरों पर। इसे पालग्रेव मैकमिलन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

. पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य स्तर पर स्वास्थ्य व्यय के लिए निहितार्थ। सितंबर से मई तक।

प्रायोजक भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बीएमजीएफ आगे का रास्ता

दल मीता चौधरी और गरिमा नैन

उद्देश्य अध्ययन राज्य स्तर पर स्वास्थ्य व्यय के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के निहितार्थों का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है।

. स्वास्थ्य में सार्वजनिक प्रावधान को लागू करना क्या सार्वजनिक और निजी प्रदाता सह अस्तित्व में हैं अगस्त से जून तक।

प्रायोजक भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बीएमजीएफ आगे का रास्ता

दल मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता

उद्देश्य अध्ययन सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के प्रसार और उनके सह अस्तित्व यदि कोई हो का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच संभावित पूरकता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

. गुजरात में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का अंतर राज्य वितरण क्षैतिज और लंबवत इक्विटी। अगस्त से जून .

प्रायोजक भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्त पोषण के दृष्टिकोण के तहत बीएमजीएफ आगे का रास्ता

दल मीता चौधरी और जय देव दुबे

उद्देश्य अध्ययन गुजरात राज्य के भीतर स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च के वितरण का विश्लेषण करने के लिए राज्य के खजाने से निकासी की जानकारी का उपयोग करता है।

□.□ वित्त खातों से राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतन □डेटा बैंक। निरंतर।□

प्रायोजक□एनआईपीएफपी

दल□एच.के. अमरनाथ और रोहित दत्ता

उद्देश्य□वित्त लेखा□नियंत्रक और महालेखा परीक्षक □सीएजी□भारत सरकार से राज्य के वित्त की जानकारी का अद्यतन करना। हमारे पास सभी □9 राज्यों के लिए □9□□□□ से □□□9□□ तक की जानकारी है।

□□. जीआरएम तंत्र का आधारभूत अध्ययन□भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल□।□ नवंबर □□□□□ से मई □□□□□ तक।□

प्रायोजक□बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन□जीआरएम

दल□रेणुका साने□सृष्टि शर्मा□ऐश्वर्या गवली□मार्गी पांड्या और नैंसी गुप्ता

उद्देश्य□अध्ययन का उद्देश्य है□

- वित्तीय शिकायत का सामना करने पर परिवार क्या करते हैं □क्या वे जानते हैं कि इस शिकायत का समाधान कैसे किया जा सकता है और क्या वित्तीय संस्थानों और नियामकों द्वारा स्थापित जीआरएम तंत्र से संपर्क करने पर उन्हें संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलती है□
- वित्तीय बाजारों में भागीदारी पर परिवार के निर्णय लेने पर इन जीआरएमएस का प्रभाव और इस परिकल्पना का परीक्षण करें कि क्या औपचारिक वित्तीय उत्पादों के साथ पिछली शिकायतें भौतिक संपत्ति में अतिरिक्त प्रवाह से संबंधित हो सकती हैं।
- परिवारों की प्रतिक्रियाओं में उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर का मूल्यांकन करने के लिए □क्या उच्च आय वाले लोग कम आय वाले लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं□क्या गरीबों को अनुपातहीन कल्याण हानि का सामना करना पड़ता है□क्या उनकी प्रतिक्रियाएं जोखिम की भूख और समय वरीयता की दरों से भिन्न होती हैं। इसमें परिवारों की □जोखिम वरीयता□और □समय वरीयता□का मापन शामिल होगा। □गरीबों में सबसे गरीब□और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित□जिनके पास सामान्य रूप से कम एजेंसी होने की संभावना है□के अनुभवों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

□□. सीजीटीएमएसई के लिए गारंटी योजनाओं के लिए डेटा विश्लेषण। प्रारंभ तिथि □□□जुलाई □□□□.□

प्रायोजक□सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट □सीजीटीएमएसई□

दल□रेणुका साने□अनन्या गोयल और मिथिला ए॰ सारा

उद्देश्य□

- डेटा संग्रह और विश्लेषण जिसमें सीमा□अर्थमिति□आर्थिक और नीति अनुसंधान शामिल हैं।
- डेटा यूनिवर्स परिभाषा
- डेटा विश्लेषण
- नीति समीक्षा□रिपोर्टिंग और शासन

. भारतीय राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन। दिसंबर से मार्च तक।

प्रायोजक यूनिसेफ इंडिया

दल मनीष गुप्ता स्मृति बहल सोनल अग्रवाल देवयानी गुप्ता और प्रियांशी गर्ग

उद्देश्य अध्ययन का उद्देश्य भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने में एसएफसीएस के कामकाज और उनकी सिफारिशों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना है।

. भारत में वृद्धावस्था आय सहायता प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय सुधार पर पुसीफुटिंग। मई को पूरा होने की संभावना है।

प्रायोजक स्वयं पहल

दल मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

उद्देश्य पिछले संस्करण पर प्राप्त इनपुट के बाद एक उप खंड को शामिल करने के लिए पेपर में संशोधन किया जा रहा है जो पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत परिभाषित लाभों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव पर काम करता है। हम टर्मिनल बेनीफिट्स को कम करने का प्रस्ताव करते हैं अर्थात् i छुट्टी नकदीकरण और ii पेंशन का कम्यूटेशन। यह तर्क दिया जाता है कि ये टर्मिनल बेनीफिट अर्जित अवकाश के प्रावधान के उद्देश्य से कार्य जीवन संतुलन के औचित्य के खिलाफ काम करते हैं जबकि पेंशन का रूपान्तरण सशर्त भविष्य के लाभों की एक धारा को पूर्व खाली करने वाला एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार जारी किए गए संसाधनों का उपयोग वर्ष से कम आयु के सभी मौजूदा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना **एपीवाय** खातों में । R के वार्षिक सरकारी योगदान को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रस्तावित किया गया है कि वर्ष की आयु तक एपीवाई खाते वाले कार्यकर्ता के लिए यह अप्रतिदेय योगदान सरकार द्वारा जारी रखा जाना चाहिए साथ ही पात्र प्रवेशकों के लिए एपीवाई खातों में जो नए श्रम बल में शामिल होते हैं। व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटएस सुनिश्चित की जानी चाहिए।

. राजस्व व्यय की संरचना में परिवर्तन कुछ अंतर और अंतर पीढ़ी संबंधी चिंताएं। मई तक पूरा होने की संभावना है।

प्रायोजक स्वयं पहल

दल मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

उद्देश्य प्रस्तावित अध्ययन अध्याय भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए राजस्व व्यय के वस्तु वार वर्गीकरण का एक अलग विश्लेषण करेगा। सब्सिडी ब्याज भुगतान मजदूरी और पेंशन पर व्यय जनसंख्या में विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग प्रभाव डालता है। सार्वजनिक व्यय के कुछ वितरण अंतर और अंतर पीढ़ीगत पहलुओं पर इक्विटी और स्थिरता के निहितार्थ पर चर्चा की जाएगी।

□□. जीवाश्म ईंधन मूल्य परिवर्तन का प्रभाव। जून □□□□ तक पूरा होने की संभावना है।

प्रायोजक □स्वयं पहल

दल □मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

प्रायोजक □वर्ष □□□□□9 के लिए इनपुट□आउटपुट □**आइ ओ**□गुणांक का एक अद्यतन सेट उत्पन्न करने के लिए अंतिम उपभोग व्यय□अप्रत्यक्ष करों और मूल्यवर्धन पर राष्ट्रीय आय खातों से पूरक जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस अद्यतन के लिए **आरएएस** पद्धति दो प्रारंभिक समाधानों पर लागू होती है□जिनमें से प्रत्येक □99□99 और □□□□□□ के लिए **आइ ओ** लेन□देन तालिका का उपयोग करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि जीवाश्म ईंधन की कीमतों में वृद्धि के आगे संचरण से लागत□पुश मुद्रास्फीति की तीव्रता में थोड़ा बदलाव आया है।

□□. भारत में श्रम बल की भागीदारी में गिरावट□क्या कुछ नीतियां गलत हैं□ जुलाई □□□□ में पूरा होने की संभावना है।

प्रायोजक □स्वयं पहल

दल □मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

उद्देश्य □पेपर का तर्क है कि भारतीय श्रम बाजार से संबंधित टिप्पणीकारों द्वारा पेश किए गए कई कारणों का समर्थन करने के लिए कमजोर□नगण्य या अनुमानित सबूत हैं□उदाहरण के लिए□कम महिला श्रम□बल की भागीदारी के कारण□□i□घरेलू मांग में वृद्धि देखभाल के काम के लिए उपलब्ध समय पर □पानी लाने सहित□या □ii□पति□पत्नी की आय में सुधार। इसके अलावा□निष्पक्ष रूप से तैयार किए गए मेट्रिक्स के अभाव में□कौशल में बेमेल या तथाकथित कौशल□घाटे पर केवल वास्तविक सबूत हैं। पेपर का प्रस्ताव है कि□ए□ श्रम कानूनों के लिए सीमा केंद्रित दृष्टिकोण के कारण श्रम मांग कम है□जिसके परिणामस्वरूप श्रम की सीमांत लागत में भारी बदलाव होता है□और □ii□उच्च आवंटन को प्रेरित करने वाले कारकों को रिटर्न का असमान कर उपचार पूंजी में मूल्यवर्धन □किसी की कर देयता को कम करने के लिए□□जबकि □बी□श्रम आपूर्ति पर प्रतिकूल रूप से निर्भर अपेक्षाओं से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है□□i□खंडित श्रम बाजार□जो बदले में□ श्रम कानूनों में थ्रेसहोल्ड का परिणाम हैं□और □ii□□एक न्यूनतम वेतन निर्धारण प्रक्रिया जो एक प्रवेश स्तर के कार्यकर्ता के लिए नौकरी के विवरण और वांछित कार्यकर्ता प्रोफ़ाइल दोनों की उपेक्षा करती है।

□□. भारत में सामाजिक पेंशन□एक सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम के अग्रदूत। अगस्त □□□□ तक पूरा□ होने की संभावना है।

प्रायोजक □स्वयं पहल

दल □मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

उद्देश्य □पेपर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम □एनएसएपी□से दोनों□दक्षता और पर्याप्तता □i□पहचान और □ii□लाभ आकलन करने का प्रयास करता है। इसमें एनएसएपी के प्रशासन की सुविधा के लिए नागरिकों

के पहचानकर्ता आधार के उपयोग पर चर्चा शामिल है और क्या डिजाइन को अनुकूलित किया जा सकता है और एक सार्वभौमिक बुनियादी आय यूबीआई कार्यक्रम के अग्रदूत के रूप में कार्य किया जा सकता है। संशोधित पेपर एक अंतरराष्ट्रीय तुलना के साथ भारत पर चर्चा को संदर्भित करता है और भारतीय राज्यों में विश्लेषण के लिए कार्यक्रम डैशबोर्ड से जानकारी का उपयोग करता है।

. सार्वजनिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का निर्धारण क्यों नौकरी के विवरण और संबंधित कर्मचारी प्रोफाइल पर विचार करना चाहिए सितंबर तक पूरा होने की संभावना है।

प्रायोजक स्वयं पहल

दल मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती

प्रायोजक केंद्रीय वेतन आयोग तीन व्यक्ति खपत इकाइयों के लिए औसत वांछनीय खपत बास्केट पर विचार करके न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है। हालाँकि उनका दृष्टिकोण न्यूनतम आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है जैसा कि प्रवेश स्तर पर नौकरी के विवरण में दिया गया है ताकि निम्नतम स्तर की भर्ती की एक बुनियादी प्रोफ़ाइल तैयार की जा सके। तब सफल भर्ती का प्रोफाइल वास्तविक वेतन निर्धारण में उपयोग किए गए एक की ओर बढ़ने की संभावना है न कि नौकरी विवरण को पर्याप्त पर्याप्त मानता है। इस पत्र में न्यूनतम वेतन को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय से योग्यता और आवश्यकताओं के तहत विस्तृत निम्नतम स्तर के प्रवेशकर्ता की वांछित विशेषताओं और खपत व्यय डेटा का उपयोग किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रक्रियाओं में इस तरह का युक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रक्रियाएं वेतन अपेक्षाओं के निर्माण को प्रभावित करती हैं और बदले में श्रम बल की भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

. शिक्षा वित्तपोषण पर कोविड का प्रभाव। अक्टूबर से जून ।

प्रायोजक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन

दल सुकन्या बोस और हर्षिता शर्मा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन

उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा के लिए कोविड 9 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने बजट को कैसे प्रभावित किया है इस मुद्दे को केंद्र सरकार और दो राज्य सरकारों दिल्ली और बिहार के स्तर पर खोजा गया है। अध्ययन में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों का एक सेट तैयार करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि बढ़ी हुई और अच्छी तरह से लक्षित शिक्षा वित्तपोषण को लिंग उत्तरदायी न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में निवेश किया जाए।

. स्कूली शिक्षा पर जेंडर सेंसिटिव बजटिंग पर अध्ययन। दिसंबर से दिसंबर ।

प्रायोजक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन

दल सुकन्या बोस और अनुराधा डे सीओआरडी

उद्देश्य□जेंडर बजटिंग □जीबी□एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो सरकार के बजट की छानबीन करता है ताकि इसके लिंग□विभेदित प्रभाव को प्रकट किया जा सके और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग□आधारित नुकसान को दूर करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अधिक प्राथमिकताओं की वकालत की जा सके। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर बजटिंग की नीतियों और प्रथाओं को लागू करना है। क्या जेंडर बजट मौजूद हैं□यदि हाँ□तो लड़कियों की शिक्षा के नियोजन और प्राथमिकता के साधन के रूप में ये कितने अर्थपूर्ण हैं□ बजट में परिलक्षित लड़कियों पर शिक्षा खर्च का पैटर्न क्या है□ अधिक सार्थक जीबी अभ्यास के लिए डेटा में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है□

□□. भारतीय□अर्थव्यवस्था□के□लिए□मैक्रो□अर्थमितीय□मॉडलिंग□□निरंतर□□

प्रायोजक□स्वयं पहल

दल□सुकन्या बोस और एन.आर. भानुमूर्ति

उद्देश्य□नीति अनुकरण अभ्यासों के माध्यम से□विभिन्न बाहरी झटकों को देखते हुए□वर्तमान व्यापक आर्थिक नीति विकल्पों के उत्तर खोजने का उद्देश्य है। नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करते हुए एनआईपीएफपी मैक्रो□इकोनोमेट्रिक मॉडल के आधार पर विकास□मुद्रास्फीति□बाहरी और राजकोषीय संतुलन पर बाहरी झटकों के प्रभाव के सिमुलेशन पर काम किया जाएगा।

□□. भारत□में□राज्य□वित्त□के □मुद्दों□का□पुनरीक्षण □कुछ□अनुभवजन्य□जांच।□नवंबर□□□□□से□दिसंबर□□□□□.□

प्रायोजक□स्वयं पहल

दल□भावेश हजारिका और दिनेश कुमार नायक

उद्देश्य□अध्ययन का उद्देश्य राज्य के वित्त पर विभिन्न मुद्दों और निहितार्थों का विश्लेषण करना है।

□□. सतत□विकास□में□सार्वजनिक□खर्च□□शासन□और□क्षेत्रीय□असमानता□□असम□में□एक□जिला□स्तरीय□विश्लेषण।□मार्च□□□□□से□फरवरी□□□□□.□

प्रायोजक□भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

दल□भाबेश हजारिका

उद्देश्य□भारत में असमानताओं की विभिन्न कुल्हाड़ियों के बीच□हाल के दिनों में क्षेत्रीय असमानता को महत्व मिला है। अन्य मुख्यधारा के भारतीय राज्यों की तुलना में न केवल असम कम विकसित है□बल्कि राज्य के भीतर भी व्यापक असमानताएं हैं। असम सतत विकास लक्ष्यों □एसडीजीएस□के संदर्भ में एसडीजी□संरेखित विजन दस्तावेजों को विकसित करके□अनुकूलित राज्य संकेतक ढांचे को अपनाने और एसडीजी कोशिकाओं और समर्पित संस्थागत संरचनाओं का निर्माण करके सक्रिय रहा है। हालांकि□उत्तर पूर्वी क्षेत्र □एनईआर□जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड □□□□□□□ से पता चलता है कि असम के जिलों में एसडीजी की स्थिति में काफी असमानता है। इस प्रकार□यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के अंतर□जिला विचलन क्या हैं □यह जानने के लिए कि कुछ जिलों के बेहतर परिणाम क्यों हैं जबकि अन्य में खराब

एसडीजी उपलब्धियां हैं। क्या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि सीधे तौर पर एसडीजी परिणामों में सुधार को प्रभावित करती है खासकर जिला स्तर पर इस तरह के बदलाव को समझाने में सुशासन की क्या भूमिका है प्रस्तावित अध्ययन में जिलों में एसडीजी की उपलब्धि के विचलन की व्याख्या करने में सार्वजनिक व्यय और शासन की गुणवत्ता की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिसका नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सामाजिक क्षेत्र के खर्च की बात आती है तो जिला कार्यान्वयन इकाई है। इसके अलावा राजस्व में ठहराव के कारण असम का वित्तीय क्षेत्र कमजोर है। ऐसी स्थिति में बढ़ते विकास अंतराल को पाटने में सुशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक खर्च महत्वपूर्ण होगा।

शुरू की गईं नई परियोजनाएं

केंद्र और राज्य सरकारों के लिए शुरू की गई नई परियोजनाएं

1. आंध्र प्रदेश के राजस्व पर जीएसटी मुआवजे की वापसी का प्रभाव। फरवरी से अप्रैल तक।

प्रायोजक वाणिज्यिक कर विभाग आंध्र प्रदेश सरकार

दल आर कविता राव भाबेश हजारिका और अशोक भाकर

उद्देश्य आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व की कमी का सामना कर रहा है। इस प्रकार राजस्व संग्रह पर जीएसटी मुआवजे को वापस लेने के एवज में किसी भी झटके का राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह चूंकि संक्रमण अवधि प्रतिशत प्रति वर्ष पर निर्धारित के दौरान राज्य के लिए राजस्व की अनुमानित नाममात्र वृद्धि दर पर चर्चा हुई है यह संभावना नहीं है कि केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजे अवधि के विस्तार पर निर्णय लेने पर भी दर जारी रहेगी। इस पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान रिपोर्ट राज्य के राजस्व पर जीएसटी मुआवजे को वापस लेने के संभावित प्रभावों का समग्र मूल्यांकन करती है। यह जून से परे जीएसटी मुआवजे को जारी रखने के संभावित डिजाइनों पर भी प्रकाश डालता है जिससे राज्य के वित्त पर प्रभाव की गंभीरता को कम किया जा सकता है और केंद्र पर बोझ के साथ साथ आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।

2. मध्य प्रदेश में आर्थिक मूल्यांकन और उभरते वित्तीय परिदृश्य। मार्च को शुरू किया गया।

प्रायोजक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान एआईजीजीपीए भोपाल मध्य प्रदेश सरकार

दल पिनाकी चक्रवर्ती और अमेय स्प्रे

उद्देश्य यह नोट हाल के वर्षों में और विशेष रूप से कोविड 19 महामारी की शुरुआत के बाद मध्य प्रदेश के उभरते आर्थिक परिदृश्यों और वित्तीय प्रदर्शन का एक सारांश मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। नोट में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त मूल्यांकन राजस्व व्यय और ऋण के संदर्भ में राजकोषीय प्रदर्शन कोविड के बाद की स्थिति में उभरती राजकोषीय जगह और राजकोषीय समेकन के लिए आगे का रास्ता शामिल है।

3. राष्ट्रीय अनुकूलन संचार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफसीसी भारत सरकार। फरवरी से शुरू।

प्रायोजक मंत्रालय के लिए नीतिगत इनपुट कोई फंडिंग नहीं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

दल लेखा चक्रवर्ती अजय नारायण झा और अमनदीप कौर

उद्देश्य एनआईपीएफपी अध्ययन भारत में अनुकूलन के वित्तपोषण का विश्लेषण करता है। यह दस्तावेज़ अगस्त तक प्रस्तुत किए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय अनुकूलन संचार का हिस्सा होगा।

. उत्तराखंड के लिए सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही पीईएफए आकलन। अप्रैल से मार्च .

प्रायोजक उत्तराखंड सरकार

दल प्रताप रंजन जेना दिनेश नायक और भाबेश हजारिका

उद्देश्य एनआईपीएफपी उत्तराखंड राज्य के लिए परियोजना सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही पीईएफए मूल्यांकन करने का प्रस्ताव करता है। मूल्यांकन स्थापित **पीईएफए** मूल्यांकन पद्धति का पालन करेगा। अध्ययन उत्तराखंड में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पीएफएम प्रणाली की ताकत और कमजोरियों को दिखाएगा और इस प्रक्रिया में अधिकारियों को उचित नीतिगत उपाय करने में मदद करेगा।

. पुडुचेरी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आकलन का तृतीय पक्ष आकलन। मार्च को शुरू किया गया।

प्रायोजक पुडुचेरी सरकार

दल अमेय स्प्रे

उद्देश्य जीएसडीपी के आकलन के स्रोतों और तरीकों के आकलन और जीएसडीपी अनुमानों को संकलित करने के लिए सुधार के क्षेत्रों पर रिपोर्ट। मूल्यांकन में बुनियादी राष्ट्रीय खाता समुच्चय शामिल हैं जैसे कि क्षेत्रों द्वारा जीएसडीपी डेटा स्रोत और मूल्य वर्धित अनुमानों के आवंटन की विधि और जीएसडीपी के अग्रिम अनुमान तैयार करने की पद्धति।

वित्त मंत्रालय के लिए शुरू की गई नई परियोजनाएं

. एनआईपीएफपी डीईए अनुसंधान कार्यक्रम। अप्रैल से मार्च तक।

प्रायोजक आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय

दल आर कविता राव राधिका पांडे प्रमोद सिन्हा रचना शर्मा आशिम कपूर रितिका सिंह सिमरन कौर उत्सव सक्सेना कृति वट्टल राम्या आर कुमार और आनंदिता गुप्ता

उद्देश्य इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विभाग और संस्थान के बीच एक सहयोगी कार्य प्रक्रिया स्थापित करना है जो वित्तीय और मौद्रिक संस्थान निर्माण के कार्यों में विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एफएसएलआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विभाग को अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सहित वित्तीय बाजार ऋण स्थिरता का अध्ययन क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित मामले और भुगतान और निपटान प्रणाली पीएसएस अनुसंधान पर अनुसंधान भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावना संकल्प निगम आरसी के नियमों और

विनियमों का निर्माण□व्यापक विदेशी निवेश कानून□और वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के स्थापना□संबंधित पहलुओं के लिए अनुसंधान सहायता।

□. **राजस्व□विभाग□□वित्त□मंत्रालय□के□लिए□पारदर्शिता□ऑडिट। जून□□□□□□से□शुरू□होने□और□दिसंबर□□□□□□तक□पूरा□होने□की□संभावना□है।**□

प्रायोजक□केंद्रीय सूचना आयोग□भारत सरकार द्वारा सौंपा गया

दल□सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला

उद्देश्य□आरटीआई अधिनियम□□□□□□की धारा □□□□के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उप□धारा □□□□बी□के तहत सूचीबद्ध प्रकृति की जानकारी का स्वत□खुलासा करने की आवश्यकता है। विभागों को सूचना का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता होती है जो आरटीआई आवेदकों द्वारा सबसे अधिक बार मांगी जाती है और इसे अपनी वेबसाइट पर स्वतः प्रकटीकरण के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रावधान के अनुसरण में□ डीओपीटी ने आगे निर्देश दिया है कि प्रत्येक मंत्रालय□लोक प्राधिकरण को प्रत्येक मंत्रालय□विभाग□सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से प्रत्येक वर्ष एक तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का ऑडिट करवाना चाहिए और निष्कर्ष मुख्य सूचना आयोग □सीआईसी□को प्रस्तुत करना चाहिए। एनआईपीएफपी को सीआईसी द्वारा राजस्व विभाग□एमओएफ□भारत सरकार के तहत □□सार्वजनिक प्राधिकरणों के तीसरे पक्ष के ऑडिट करने के लिए सौंपा गया है। अब तक□ एनआईपीएफपी ने □□□9□□□ के लिए असाइनमेंट पूरा कर लिया है□और चूंकि यह एक वार्षिक मामला होगा□एनआईपीएफपी आने वाले वर्षों □□□□□□□ के लिए काम करेगा। एनआईपीएफपी ने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान□शुल्क आदि के राजस्व विभाग□एमओएफ□भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य किया है।

अन्य□संस्थानों□संगठनों□के□लिए□शुरू□की□गई□नई□परियोजनाएं□

□. **उप□राष्ट्रीय□राजकोषीय□स्थिरता□विश्लेषण□और□वित्तीय□जोखिम। अप्रैल□जून□□□□□.**□

प्रायोजक□विश्व बैंक

दल□आर. कविता राव□मनीष गुप्ता और सोनल अग्रवाल

उद्देश्य□अध्ययन का उद्देश्य असम राज्य के लिए एक मध्यम अवधि के वित्तीय स्थिरता विश्लेषण करना है। इसमें प्रत्येक राज्य की विशिष्ट नीति प्राथमिकताओं और बाधाओं के आधार पर परिदृश्यों में निर्माण शामिल है। यह अध्ययन भारत में उप□राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय जोखिमों की भी पड़ताल करता है।

□. **बाल□संरक्षण□सार्वजनिक□व्यय□समीक्षा□ओडिशा। फरवरी□□□□□□से□शुरू।**□

प्रायोजक□यूनिसेफ

दल□लेखा चक्रवर्ती और अमनदीप कौर

उद्देश्य यूनिसेफ परियोजना बाल संरक्षण योजनाओं की सार्वजनिक व्यय समीक्षा को देखती है और ओडिशा राज्य में बाल संरक्षण पर चयनित दो प्रमुख योजनाओं के मूल्यांकन में संलग्न है।

. **भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के वित्तीय बोझ का आकलन। अप्रैल से शुरू होने की संभावना है।**

प्रायोजक एनआईपीएफपी स्वयं की पहल

दल सच्चिदानंद मुखर्जी

उद्देश्य भारत सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये प्रोत्साहन मुख्य रूप से भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदों वाणिज्य मंत्रालय के तहत लगभग 9 परिषदों को प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के अलावा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन भी हैं उदाहरण के लिए सीमा शुल्क छूट उदाहरण के लिए इनपुट टैक्स न्यूट्रलाइजेशन या छूट योजनाओं के कारण राजस्व छोड़ दिया गया है निर्यात से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के कारण राजस्व छोड़ दिया गया है कॉर्पोरेट आयकर छूट सीआईटी एसईज़ेडएस में स्थित इकाइयों द्वारा निर्यात से अर्जित लाभ यू एस एए एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे यू एस आईए सेज के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम यू एस आईएबी। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकर और संघ उत्पाद शुल्क के तहत कई कर छूट भी प्रदान की जाती हैं। निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से योजनाओं प्रोत्साहनों के राजकोषीय बोझ पर अध्ययन भारत में कम हैं और इसलिए भारत के दोहरे घाटे व्यापार के साथ साथ बजटीय को कम करने पर इस तरह के प्रोत्साहनों के प्रभाव का समान रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की वित्तीय लागत का आकलन करना है।

. **भारत के लिए कार्बन रणनीति और निवेश पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव जनवरी से दिसंबर तक।**

प्रायोजक राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष

दल सुरंजलि टंडन

उद्देश्य परियोजना कार्बन मूल्य निर्धारण में वैश्विक प्रथाओं और भारत के लिए समान रणनीतियों को अपनाने की क्षमता की जांच करेगी। अध्ययन विशेष रूप से ऊर्जा संक्रमण के सार्वजनिक वित्त प्रभाव के साथ साथ कार्बन टैक्स की दर को भी देखेगा जिसे भारत में अपनाया जा सकता है। इसके बदले में निवेश को प्रभावित करने की उम्मीद है। अध्ययन प्रभाव का भी अनुमान लगाएगा।

. **राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतन डाटा बैंक। अप्रैल से मार्च तक।**

प्रायोजक एनआईपीएफपी

दल एच.के. अमरनाथ रोहित दत्ता और श्री हरि नायडू ए.

उद्देश्य□बजट दस्तावेजों से राज्य के वित्त की जानकारी को अद्यतन करना। हमारे पास □9□□□□□ से □□□□□ □□ **बीई** तक की जानकारी है।

□

कार्यशालाएं बैठकें और सम्मेलन

क्र.सं.	शीर्षक	द्वारा आयोजित	तिथि और स्थान
	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस म्यूनिख के साथ संयुक्त रूप से आयोजित सार्वजनिक वित्त में कागजात पर दो दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	एनआईपीएफपी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस म्यूनिख के साथ आयोजित समन्वयक डॉ लेखा चक्रवर्ती पिनाकी चक्रवर्ती अमनदीप कौर	9 जून ऑनलाइन
	माइकल कीन और जोएल स्लेमरोड की हालिया पुस्तक पर वेबिनार का शीर्षक रिबेलियन रास्कल्स एंड रेवेन्यू है।	एनआईपीएफपी समन्वयक डॉ लेखा चक्रवर्ती	9 जुलाई ऑनलाइन
	तमिलनाडु छठे वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे पर अर्ध दिवसीय कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्वयक डॉ मनीष गुप्ता	अगस्त ऑनलाइन
	पीएफएम रेडिनेस इंडेक्स पर ऑनलाइन आधे दिवसीय कार्यशाला	एनआईपीएफपी समन्वयक रत्नेश	अक्टूबर ऑनलाइन
	फ्रैजाइल फ्यूचर्स द अनसर्टेन इकोनॉमिक्स ऑफ डिजास्टर्स पैंडेमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज पर वेबिनार प्रोफेसर वीटो तंजी पूर्व निदेशक आईएमएफ फिस्कल अफेयर्स द्वारा	एनआईपीएफपी समन्वयक डॉ लेखा चक्रवर्ती	नवंबर वेबिनार
6	आपदा प्रबंधन पर पांचवें विश्व कांग्रेस डब्लूसीडीएम में कोविड 19 आर्थिक मंदी और लचीलेपन के निर्माण के लिए वित्तीय तनाव पर काबू पाने पर सत्र	डीएमआईसीएस हैदराबाद के सहयोग से एनआईपीएफपी एनडीएमए दिल्ली अन्य वैज्ञानिक तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एनआईडीएम दिल्ली	नवंबर आईआईटी दिल्ली

		समन्वयक□डॉ पिनाकी चक्रवर्ती	
7□	सोलहवां □पांच संस्थानों का बजट सेमिनार □□□□□ अनपेकिंग ऑफ यूनियन बजट □□□□□□□	पांच संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया□अर्थात्□सीपीआर□ आईसीआरआईईआर□ आईआईडीएफ□ एनसीएईआर और एनआईपीएफपी समन्वयक□डॉ पिनाकी चक्रवर्ती	□फरवरी □□□□ ऑनलाइन
8□	दिल्ली में स्कूली शिक्षा के संदर्भ में □एन इंक्वायरी इन एक्जिट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड□पर आधे दिन का वेबिनार	एनआईपीएफपी समन्वयक□डॉ सुकन्या बोस और प्रियंता घोष	□□मार्च □□□□ ऑनलाइन

□
□

□

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक	स्थान	कार्यक्रम समन्वयक
1	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए ग्रैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम।	जून	एनआईपीएफपी	डॉ अमेय स्प्रे ऑफलाइन
2	वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसई में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अगस्त– अक्टूबर	एनआईपीएफपी	डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती अमेय स्प्रे मनीष गुप्ता ऑनलाइन
3	वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसई में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	अक्टूबर दिसंबर	एनआईपीएफपी	डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती अमेय स्प्रे मनीष गुप्ता ऑनलाइन
4	वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक सप्ताह का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	मार्च– अप्रैल	एनआईपीएफपी नीति आयोग	डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती अमेय स्प्रे ऑफलाइन

प्रकाशन और संचार

संस्थान का द्विवार्षिक न्यूज़लेटर जनवरी और जुलाई में प्रकाशित हुआ था। इन न्यूज़लेटर्स में परियोजनाओं संकाय गतिविधियों और घटनाओं पर अपडेट शामिल थे। एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर सीरीज के तहत एनआईपीएफपी के शोध संकाय और उनके सहयोगियों द्वारा लिखित कुल वर्किंग पेपर प्रकाशित किए गए। रिपोर्टिंग वर्ष में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल सात ब्लॉग लेख प्रकाशित हुए। ब्लॉग ttp nip p.org.in log पर उपलब्ध है। प्रकाशन इकाई संस्थान की वेबसाइट ttp .nip p.org.in को नियमित रूप से अपडेट करने का कार्य भी करती है।

ट्विटर पर एनआईपीएफपी के सोशल मीडिया अकाउंट @nip p org का प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति मंडलों में अपने शोध कार्य और घटना की जानकारी प्रसारित करने के लिए उपयोग किया गया था।

संस्थान के प्रसार प्रयासों के एक हिस्से के रूप में वेबसाइट अपडेट और ई मेलर्स के माध्यम से अकादमिक पेपर व्यापक रूप से हितधारकों के बीच वितरित किए गए थे। एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर्स की सूची के लिए अनुलग्नक II मूल्य प्रकाशनों के लिए अनुलग्नक और संकाय प्रकाशित सामग्री के लिए अनुलग्नक I देखें

पुस्तकालय और सूचना केंद्र

एनआईपीएफपी पुस्तकालय और सूचना केंद्र सार्वजनिक वित्त और नीति के क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त राजकोषीय नीति सूक्ष्म और मैक्रोइकॉनॉमिक्स उद्योग अध्ययन योजना और विकास आर्थिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर्यावरण और प्राकृतिक अर्थशास्त्र शहरी अर्थशास्त्र और शहरी वित्त स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और संघवाद और विकेंद्रीकरण पर समृद्ध संसाधन सामग्री के साथ एक शोध पुस्तकालय है।

पुस्तकालय आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ तीन मंजिलों में फैला हुआ है। भूतल पर विशाल पाठकों का क्षेत्र लैपटॉप और वाई फाई कनेक्टिविटी के साथ पाठकों को समायोजित करता है। पुस्तकालय समारोह और सेवाओं के सभी परिचालन पहलुओं को एक एकीकृत जावाबीन्स ईजेबी आधारित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पैकेज यानी लिबसिस का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

पुस्तकालय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम बजे तक और शनिवार को सुबह 9. बजे से शाम बजे तक कार्यात्मक रहता है।

पुस्तकालय संग्रह

पुस्तकालय में से अधिक पुस्तकें और अन्य दस्तावेज हैं। वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने अपने संग्रह में नए दस्तावेज़ जोड़े हैं जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाजों अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों दोनों के प्रकाशनों के एक बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। पुस्तकालय को भारत की जनगणना पर चार सीडी रोम भी प्राप्त हुए हैं डेटा स्रोत आदि।

पुस्तकालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दस्तावेजीकरण ब्यूरो आईबीएफडी से विभिन्न प्रकाशनों तक पहुंच के लिए ई सदस्यता भी ली है। इस सदस्यता के माध्यम से संस्थान ने अपने संकायों और शोधकर्ताओं को ई पत्रिकाओं ई पुस्तकों ग्लोबल टैक्स एक्सप्लोरर कॉम्पैक्ट प्लस ऑनलाइन की एक आकाशगंगा के माध्यम से एक समृद्ध सुविधा प्रदान की है।

पत्रिकाएं

पुस्तकालय निम्नलिखित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता पत्रिकाओं डेटाबेस पत्रिकाओं और अन्य ऑनलाइन पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है प्राप्त करता है और रखता है।

विशिष्ट	कुल संख्या
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं	
राष्ट्रीय पत्रिकाएं	

पत्रिका	□□
अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता के तहत निम्नलिखित जर्नल□ □□ अमेरिकन इकनॉमिकअसोशिएशन □□ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एड्मिनिसट्रेशन □□ इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िस्कल स्टडीस □□ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस	□□
ऑनलाइन डेटाबेस के तहत निम्नलिखित जर्नल□ 1) साइंसडायरेक्ट□ एकोमिमिक्स□ एकोमोनेट्रिक्स और फ़ाइनेंस बंडल 2) ओयूपी ऑनलाइन एकोनोमी जर्नल बंडल कलेक्शन 3) एसटीओआर □बिजनेस कलेक्शन I और II□ 4) एकॉनलाइट विद फुल टेक्स्ट वर्शन 5) द स्टाटा जर्नल	□□□□

अखबार और पत्रिकाएं□

क्रमांक न.□	**राष्ट्रीय समाचार पत्र□**	**प्रिंट ऑनलाइन□**
1□	बिजनेस लाइन	प्रिंट
2□	बिजनेस स्टैंडर्ड	प्रिंट □ऑनलाइन
3□	द इकोनॉमिक टाइम्स	प्रिंट
4□	रोजगार समाचार	प्रिंट
5□	द फाइनेंसियल एक्सप्रेस	प्रिंट
6□	इंडियन एक्सप्रेस	प्रिंट
7□	मिंट	प्रिंट
8□	नवभारत टाइम्स □हिंदी□	प्रिंट
9□	द टेलीग्राफ □कोलकाता संस्करण□	प्रिंट
10□	द हिन्दू	ऑनलाइन
11□	हिंदुस्तान टाइम्स	प्रिंट
12□	द स्टेट्समैन	प्रिंट
13□	द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया	प्रिंट
□	**अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र□**	**प्रिंट ऑनलाइन□**
1□	फाइनेंसियल टाइम्स	ऑनलाइन

□

ई संसाधन

ई जर्नल्स डेटाबेस

क्रमांक न.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1	ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन आर्थिक जर्नल बंडल कलेक्शन	□ttp□□□□□□.o□ord□ournal□org	आईपी आधारित
2	जेएसटीओआर बिजनेस कलेक्शन I और II	□ttp□□□□□□.□tor.org	आईपी बी आधारित
3	एल्सेवियर साइंस डायरेक्ट जर्नल्स इकोनॉमिक्स एकोनोमेट्रिक और फ़ाइनेंस सब्जेक्ट बंडल	□ttp□□□□□□.□ci□nc□dir□ct.com	आईपी आधारित
4	एकॉनलाइट विद फुल टेक्स्ट	□ttp□□□□□□.□arc□.□□□co□o□t.com	आईपी बी आधारित

ई डेटाबेस

क्रमांक न.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1	ओईसीडी टेक्सेसन आईलाइब्रेरी	□ttp□□□□□□.o□cd□ ili□rar□org	आईपी आधारित
2	ओईसीडी इक्नोमिक्स आईलाइब्रेरी	□ttp□□□□□□.o□cd□ ili□rar□org	आईपी आधारित
3	ओईसीडी गवर्नेंस आईलाइब्रेरी	□ttp□□□□□□.o□cd□ ili□rar□org	आईपी आधारित
4	आईबीएफडी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन	□ttp□□□□□□.i□□d.org	यूज़र आईडी पासवर्ड आधारित पहुंच (अधिकतम उपयोगकर्ता)
5	आईएमएफ ई लाइब्रेरी	□ttp□□□□□□.□li□rar□.im□org	आईपी आधारित
6	द स्टाटा जर्नल	□ttp□□□□□□.□tata□ □ournal.com	पीडीएफ उपलब्ध
7	ईपीडब्लूआरएफ इंडिया टाइम सीरीज़	□ttp□□□□□□.□p□r□it□in	आईपी आधारित
8	सीईपीआर चर्चा पत्र	□ttp□□□□□□.c□pr.org	चयनित के लिए

			उपयोगकर्ता
9	इंटरनेशनल टेक्सेसन	http://www.internationaltaxation.taxmann.com	यूज़र आईडी पासवर्ड आधारित पहुंच

कॉर्पोरेट डेटाबेस

क्रमांक न.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1	सीएमआईई इकनॉमिक आउटलुक	http://www.economicoutlook.cmie.com	आईपी आधारित
2	सीएमआईई प्रोवेसआईक्यू	http://www.prowessiq.cmie.com	आईपी आधारित
3	सीएमआईई कैपेक्स	http://www.capex.cmie.com	आईपी आधारित

ई बुक्स डेटाबेस

क्रमांक न.	डेटाबेस का नाम	वेब लिंक	अभिगम्यता का तरीका
1	एडवर्ड एल्गर ई किताबें	http://www.elgaronline.com/browse?accessurl=parent	आईपी आधारित
2	अर्थशास्त्र पर स्प्रिंगर ई किताबें विषय बंडल	http://www.link.springer.com	आईपी बी आधारित

नोट एडवर्ड एल्गर ई बुक्स को से बंद कर दिया गया है और इसकी एक्सेस केवल 9 से उपलब्ध है।
यह स्प्रिंगर डेटाबेस से बंद कर दिया गया है और इसकी पहुंच से तक ही उपलब्ध है।

वर्तमान जागरूकता सेवा

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेज़ लेख समाचार पत्र लेख नियमित रूप से डेटाबेस में जोड़े जा रहे हैं और निम्नलिखित वर्तमान जागरूकता बुलेटिन के रूप में जारी किए जा रहे हैं

- लेख चेतावनी सेवा अखबार की कतरनों का नवीनतम परिवर्धन
- करंट अवेयरनेस सर्विस पुस्तकों का नवीनतम परिवर्धन
- वर्तमान सामग्री सेवा पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं की सामग्री पृष्ठों के लिए एक मासिक बुलेटिन
- बजट से पहले और बाद का विशेष बुलेटिन बजट से पहले और बाद के बजट से संबंधित समाचार और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों के विचारों का बुलेटिन

इसके अलावा पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता सेवा भी प्रदान करता है सभी संकाय सदस्यों के लिए ग्रंथ सूची सेवा और संदर्भ सेवा। यह एनआईपीएफपी संकाय सदस्यों को ई मेल के माध्यम से बुक अलर्ट और आर्टिकल अलर्ट भी प्रदान करता है।

एनआईपीएफपी पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब किए गए डेटाबेस ई संसाधनों की पहुंच बढ़ाने के लिए जुलाई अगस्त में एक सूचना साक्षरता कार्यक्रम उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन मोड आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना था। डेटाबेस और उसी के लिए संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के ज्ञान का उन्नयन।

संसाधन के बंटवारे

एनआइपीएफपी पुस्तकालय व्यापक संसाधन साझाकरण और दस्तावेज़ वितरण सेवा के लिए विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क डीईएलएनईटी के साथ सदस्यता रखता है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित पुस्तकालयों से दस्तावेज उधार लिए और दस्तावेज समान प्रतिष्ठित पुस्तकालयों को अंतर पुस्तकालय संसाधनों के व्यापक प्रसार के लिए उधार दिए। वर्ष के दौरान लगभग बाहरी शोधार्थियों और नीति निर्माताओं ने पुस्तकालय का दौरा किया और इस तरह के समृद्ध संसाधनों से लाभान्वित हुए।

आरईपीईसी अर्थशास्त्र में शोध पत्र

आरईपीईसी अर्थशास्त्र और संबंधित विज्ञान में अनुसंधान के प्रसार को बढ़ाने के लिए देशों में सैकड़ों वैश्विक स्वयंसेवकों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस परियोजना का केन्द्रीय वर्किंग पेपर्स जर्नल आर्टिकल्स बुक्स बुक्स चैप्टर्स का एक ऑनलाइन विकेन्द्रीकृत ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसका रखरखाव ऐसे स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। एनआईपीएफपी पुस्तकालय ने संस्थान के वर्किंग पेपर्स के मेटाडेटा को अपलोड करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विषय भंडार आरईपीईसी अर्थशास्त्र पर शोध पत्र में भी भाग लिया है। वर्ष के दौरान आरईपीईसी में वर्किंग पेपर अपलोड किए गए हैं। इन एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर्स को बार खोजा गया एक्सेस किया गया और डाउनलोड किया गया और सार को विश्व स्तर पर 9 बार देखा गया।

आरईपीईसी कार्यकारी पत्र श्रृंखला के अभिगम्य आंकड़े

डाउनलोड और उद्धरण व्यूज़ की संख्या		
अप्रैल – मार्च		
माह	**डाउनलोड**	**उद्धरण वियूज़**
		9
	9	99
	9	
	9	
	9	9

डाउनलोड और उद्धरण व्यूज़ की संख्या		
अप्रैल – मार्च		
माह	डाउनलोड	उद्धरण वियूज़
	9	9
	9	
		9
योग		

आरईपीईसी कार्यकारी पत्र श्रृंखला के अभिगम्य आंकड़े

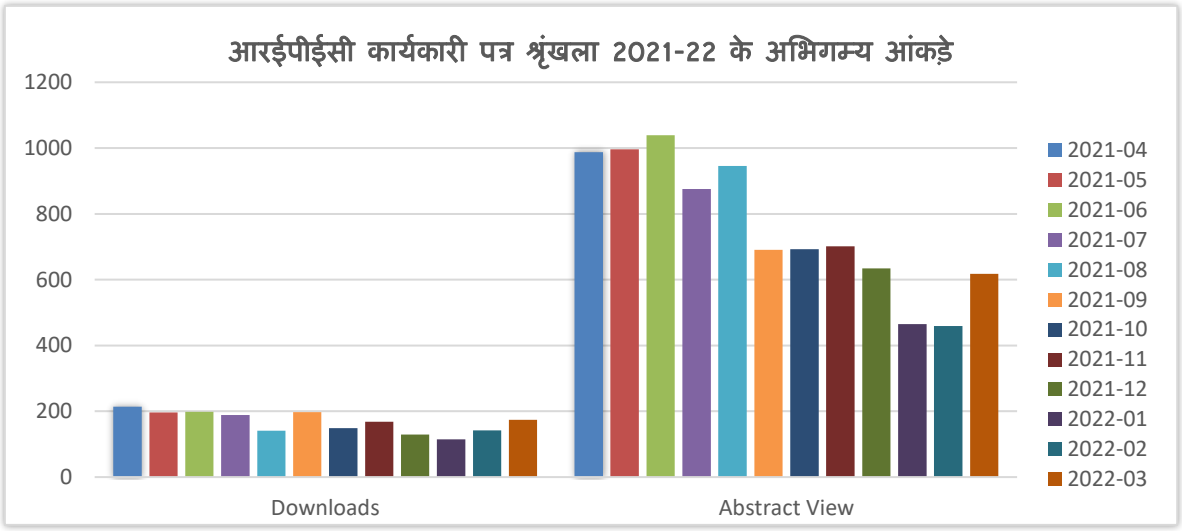

उपरोक्त तालिका और चार्ट से पता चलता है कि कार्यकारी पत्रों की अधिकतम संख्या अर्थात अप्रैल में डाउनलोड की गई थी और कार्यकारी पत्र उद्धरणों की अधिकतम संख्या अर्थात 9 जून में देखी गई थी। उपरोक्त आंकड़े सुस्पष्ट रूप से यह अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं कि वर्ष के दौरान कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी ने इस मंदी के दौर में भी सार्वजनिक वित्त नीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं में कमी नहीं की है।

रेप्रोग्राफिक सेवाएं

एनआईपीएफपी पुस्तकालय संकाय सदस्यों और बाहरी शोधार्थियों को पुस्तकालय संसाधन सामग्री की पारंपरिक रेप्रोग्राफिक सेवा प्रदान करता है। हमारे रेप्रोग्राफी रोस्टर की तत्परता की उपयोगकर्ताओं द्वारा सराहना की गई है। वर्ष के दौरान उपयोगकर्ताओं को उनके शोध कार्य के लिए लगभग 3260 पृष्ठों की फोटोकॉपी सामग्री प्रदान की गई। किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए एनआईपीएफपी पुस्तकालय में रेप्रोग्राफिक नयाचार का पालन किया जाता है।

पुस्तकालय स्टाफ के क्रियाकलाप

प्रकाशित/प्रस्तुत पत्र

- सिंह, सोनम, एट अल (2021). "उत्तर भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के गलियारों के माध्यम से आगे का सफर: संसाधनों और सेवाओं का संकलन"। लाइब्रेरी हेराल्ड, 59 (3), 272-83.
- मुक्त अभिगम्यता संसाधन (ओएआर) की सुविधा के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनएलडीआई) की भूमिका: कोविड-19 रिसर्च रिपोजिटरी, डिजिटल लाइब्रेरी पर्सपेक्टिव्स का अन्वेषण। http://doi.org/10.1108/DLP-08-2021-0072
- सिंह, सोनम ने कोविड-19 के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका पर अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'उत्तर भारत में विधि विश्वविद्यालयों द्वारा सदस्यता ग्रहण किए गए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी डेटाबेस का एक तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया। 29-30 जनवरी 2022.

संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सिंह, सोनम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बीएलआईएससी-पेपर बी) के छात्रों के लिए सप्ताहांत पर उनके पाठ्यक्रम के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में एक लाइब्रेरी इंटर्नशिप प्रोग्राम (ऑनलाइन मोड) आयोजित किया। जून-जुलाई .
- सिंह, सोनम ने डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट) की वीं वार्षिक आम सभा (ऑनलाइन मोड) में भाग लिया। अक्टूबर .

कम्प्यूटर केंद्र

एनआईपीएफपी का कंप्यूटर केंद्र अकादमिक समुदाय के साथ-साथ संस्थान के अन्य विभिन्न प्रभागों जैसे लेखा प्रशासन सभागार पुस्तकालय प्रकाशन और संचार को महत्वपूर्ण सहायता सेवा प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र संकाय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी प्राचीन प्रणालियों को निरंतर बदलता रहता है। एनआईपीएफपी परिसर पूरी तरह से वाई-फाई-सक्षम है। संस्थान की इंटरनेट सुविधा (nipfp.org.in राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा समर्थित है। वेबसाइट का प्रबंधन एक प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय और लेखा विभाग को नियमित संचालन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाता है। जबकि संस्थान के पुस्तकालय में एलआईबीएसवाईएस और कौशल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है लेखा विभाग के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए **टैली एवं** ईएक्स खाते और पेरोल सॉफ़्टवेयर प्रदान किए जाते हैं। कम्प्यूटर केन्द्र कम्प्यूटर समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये समग्र नीति मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है।

संकाय गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

पिनाकी चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए और वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया। जून .

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्सवीएफसी की सिफारिशें तमिलनाडु वित्त के लिए निहितार्थ पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी मे मार्च को वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारी बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्घाटन व्याख्यान दिया।

- एनआईपीएफपी मे मार्च को वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारी बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक ऋण बोझ और अंतर सरकारी इक्विटी पर एक व्याख्यान दिया।

आमंत्रित व्याख्यान

- एशियाई विकास बैंक एडीबी तथा टैक्स पर सहयोग के लिए मंच द्वारा आयोजित एशिया में मध्यम अवधि के राजस्व रणनीतियों पर एक पैनल में सतत राजनीतिक प्रतिबद्धता और पूरे सरकारी समर्थन के माध्यम से सरकार के नेतृत्व वाली कर प्रणाली सुधार पर एक सत्र में एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। मई .

- फ़ोरम ऑफ़ फ़ेडरेशन्स ओटावा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल डायलॉग सीरीज़ फ़ेडरलिज़्म ऑफ़ द फ़्यूचर द फ़्यूचर ऑफ़ फ़ेडरलिज़्म इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस फ़्यूचर ऑफ़ फ़ेडरलिज़्म में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। पैनलिस्ट चिकित्सक थे जो कनाडा और जर्मनी के अंतर सरकारी संबंधों के उप मंत्री इथियोपियाई हाउस ऑफ़ फ़ेडरेशन के अध्यक्ष और ब्राज़ील में सरकार के उप सचिव सहित कोविड के पुनर्निर्माण के बाद काम कर रहे थे। जून . मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

कोलकाता द्वारा आयोजित भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर दूसरी लहर का प्रभाव पर वेबिनार में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित। जुलाई .

- के.एन. राज स्मारक व्याख्यान अर्थशास्त्र विभाग केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित देने के लिए आमंत्रित किया ऑनलाइन। जुलाई .
- एमसीटीपी पाठ्यक्रम चरण । भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी एलबीएसएनएए मसूरी मे वें दौर के प्रतिभागियों को सार्वजनिक वित्त और व्यय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। ऑनलाइन। अगस्त .
- वित्तीय शासन पीएफएम सुधारों पर विश्व बैंक सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र सीएसईपी पूर्व में ब्रुकिंग्स इंडिया वेबिनार में पीएफएम सुधार का स्टॉक लेना आगे की राह पर एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। सितंबर .
- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन जीआईफटी केरल सरकार द्वारा आयोजित इंडियाज एक्सपीरियंस विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में जीएसटी आगे का रास्ता पर एक पैनल चर्चा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। नवंबर .
- प्रजा फाउंडेशन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली द्वारा आयोजित शहरी सरकारों के वित्तीय अधिकारिता पर एक ऑनलाइन परामर्श में भाग लिया। दिसंबर .
- सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी सीटीआरपीफपी कोलकाता द्वारा आयोजित सार्वजनिक वित्त और कराधान पर प्रशिक्षण कार्यशाला में एक ऑनलाइन सत्र में व्याख्यान दिया। दिसंबर .
- आर.एस. अर्थशास्त्र विभाग प्रतिष्ठित महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा आयोजित आर. एस. भट्ट स्मृति व्याख्यान ऑनलाइन। जनवरी .
- पुणे इंटरनेशनल सेंटर पीआईसी पुणे द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट पर एक पैनल चर्चा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी .
- अर्थशास्त्र विभाग प्रबंधन स्कूल पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट इसके आर्थिक प्रभाव पर एक रिसौर्स पर्सन के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। 9 फरवरी .
- इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में केंद्रीय बजट पर चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित। फरवरी .

- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआइएफटी) केरल सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी .

- शिव नादर विश्वविद्यालय दिल्ली एनसीआर द्वारा आयोजित द फर्स्ट एसएनयू बजट सेमिनार में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी .

- राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन पर एक पाठ्यक्रम में राजस्व उत्पादन के साथ राष्ट्रीय आय पर एक वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी .

- अर्थशास्त्र विभाग भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी नई दिल्ली द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए एक रोडमैप पर एक पैनल चर्चा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया ऑनलाइन। फरवरी .

- अहमदाबाद विश्वविद्यालय गुजरात द्वारा आयोजित अहमदाबाद विश्वविद्यालय के तीसरे वार्षिक अर्थशास्त्र सम्मेलन, "द रोड टु एन इंक्लूसिव रिकवरी पोस्ट पेंडेमिक एरा" पर उद्घाटन सत्र में कोविड 9 महामारी और वित्तीय जिम्मेदारी केंद्रीय बजट पर कुछ विचार पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ऑनलाइन। मार्च .

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

- वित्त विभाग तमिलनाडु सरकार और सार्वजनिक वित्त केंद्र मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तमिलनाडु बजट दस्तावेजों की प्रस्तुति में सुधार पर एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। 9 अप्रैल .

- नीति आयोग द्वारा आयोजित माननीय उपाध्यक्ष नीति आयोग की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर एक वेबिनार में भाग लिया। महामारी के बाद के युग में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। रिपोर्ट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ते सरकारी कर्ज से उत्पन्न जोखिम और उभरती बाजार सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली नीतिगत चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए के लिए वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नीति आयोग ने भारत विशेष के लिए आगे की चर्चा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वेबिनार की मेजबानी की। अप्रैल .

- नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित कोविड 9 महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव के खिलाफ लड़ाई पर प्रमुख थिंक टैंकों के साथ वर्चुअल चर्चा में भाग लिया। मई .

- माननीय उपाध्यक्ष□नीति आयोग की अध्यक्षता में अर्थशास्त्र और वित्त पर सलाहकार समूह की एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। सलाहकार समूह का उद्देश्य व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर अपने जुड़ाव और संवाद को मजबूत करना था। नीति आयोग ने इस समूह का गठन बैंकों और वित्तीय संस्थानों□थिंक टैंक और शिक्षाविदों के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के साथ किया है। पहली बैठक नीति आयोग□नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। □□ जुलाई □□□□.

- माननीय उपाध्यक्ष□नीति आयोग की अध्यक्षता में विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति □डीईएसी□की पहली ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। □□ जुलाई □□□□.

- माननीय उपाध्यक्ष□नीति आयोग की अध्यक्षता में प्रमुख थिंक टैंकों के साथ बैठक में भाग लिया। चर्चा के लिए प्रमुख एजेंडा आइटम थे□□□डॉ पिनाकी चक्रवर्ती□निदेशक□एनआईपीएफपी द्वारा □राज्य वित्त में उभरते मुद्दे□राज्य बजट □□□□□□□ का विश्लेषण□पर एक प्रस्तुति□□□सुश्री अन्ना रॉय□वरिष्ठ सलाहकार□ नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी मंच □एनडीएपी□पर प्रस्तुति। बैठक नीति आयोग□नई दिल्ली में वर्चुअल मोड□कम□फिजिकल मोड में आयोजित की गई थी। □□ अगस्त □□□□.

- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान □आइआइएफएम□□भोपाल द्वारा आयोजित □वानिकी क्षेत्र के लिए □□ वित्त आयोग के संसाधनों का लाभ उठाने□के संबंध में वरिष्ठ आइएफएस अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला में अध्यक्ष□सह□पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया □ऑनलाइन□ □□ अगस्त □□□□.

- यूएनइएससीएपी दक्षिण और दक्षिण□पश्चिम एशिया कार्यालय □यूएनइएससीएपी□एसएसवडब्लूए□द्वारा आयोजित कॉमन कंट्री एनालिसिस □सीसीए□पर वर्चुअल स्टेकहोल्डर परामर्श के लिए भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ अगस्त □□□□.

- यूनिसेफ द्वारा आयोजित इंडिया कंट्री प्रोग्राम इवैल्यूएशन रेफरेंस ग्रुप की पहली बैठक में भाग लिया □ऑनलाइन□ □□ अगस्त □□□□.

- योजना और सार्वजनिक निवेश प्रबंधन पर कार्य पर विश्व बैंक की बैठक में भाग लिया □ऑनलाइन□ □ अक्टूबर □□□□.

- बाल संरक्षण पर यूनिसेफ अध्ययन□ओडिशा में सार्वजनिक व्यय समीक्षा □पीईआर □□डब्ल्यू एंड सीडी विभाग□ओडिशा सरकार के साथ में भाग लिया और सहायता प्रदान की □ऑनलाइन□ □□ अक्टूबर □□□□.

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत कार्यालय को □भारत में वर्तमान जलवायु बजट परिदृश्य और हरित अर्थव्यवस्था □पीएजीइ□भारत पर कार्रवाई के लिए साझेदारी के साथ संभावित सहयोग के लिए समझ को और मजबूत करने की आवश्यकता□पर चर्चा में भाग लिया □ऑनलाइन□ □नवंबर □□□□.

- माननीय उपाध्यक्ष□नीति आयोग की अध्यक्षता में प्रमुख थिंक टैंक के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया □ऑफ़लाइन□ □□ नवंबर □□□□.
- केरल राज्य वित्त पर एक वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।□□ नवंबर □□□□.
- गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स □जीआईपीई□□पुणे□इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन □आइडीएफ□□गुरुग्राम□मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी □एमएसइपीपी□और पुणे इंटरनेशनल सेंटर □पीआइसी□□पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित □अंतर□क्षेत्रीय विकास असमानताएं□ अनुभव और नीति विकल्प□पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया □ऑनलाइन□ 9 दिसंबर □□□□.
- भारतीय आर्थिक संघ के □□□वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान □एआईजीजीपीए□□भोपाल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी□भोपाल में श्री शिवराज सिंह चौहान□माननीय मुख्यमंत्री□मध्य प्रदेश की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। □□□□ दिसंबर □□□□.
- माननीय उपाध्यक्ष□ नीति आयोग की अध्यक्षता में अग्रणी थिंक टैंकों के साथ हाइब्रिड □इन□ पर्सन□वर्चुअल□मोड में नीति आयोग में बैठक मे भाग लिया। □ फरवरी □□□□.
- माननीय उपाध्यक्ष□ नीति आयोग की अध्यक्षता में प्रमुख थिंक टैंकों के साथ हाइब्रिड □इन□ पर्सन□वर्चुअल□मोड में नीति आयोग में बैठक मे भाग लिया । □□ फरवरी □□□□.
- यूनिसेफ द्वारा आयोजित □केंद्रीय बजट □□□□□□□□पर वर्चुअल चर्चा सत्र में भाग लिया□सौमेन बागची। □ मार्च □□□□.

सरकार□और□अन्य□निकायों□पत्रिकाओं□में□सदस्यता□

- सदस्य□विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय □डीएमईओ□□ नीति आयोग। □□□□ से आगे।
- सदस्य□सार्वजनिक वित्त केंद्र के लिए सलाहकार परिषद□तमिलनाडु सरकार।
- सदस्य□भारत देश कार्यक्रम मूल्यांकन संदर्भ समूह□यूनिसेफ।
- सदस्य□आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय □एफसी और ईओडीबी डिवीजन□□भारत सरकार द्वारा गठित पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत नए शहरों के इंकुबेसन के लिए विशेषज्ञ समिति।

भारत□सरकार□□वित्त मंत्रालय □और□अन्य□संगठनों□के□लिए□की□गई□सलाहकार□गतिविधियाँ□

- □टीका विकास□वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड □9 का शमन□विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया □मीता चौधरी के साथ□ दिसंबर □□□□.

- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को दिसंबर को ड्यू राज्यसभा तारांकित प्रश्न कार्बन की सामाजिक लागत के संबंध में उत्तर के लिए इनपुट प्रदान किए गए सूरंजलि टंडन और अमेय सप्रे के साथ।

- सदस्य खोज सह चयन समिति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य आर्थिक एवं वाणिज्यिक के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित। जनवरी .

- माननीय वित्त मंत्री मप्र शासन की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश शासन प्रशासन अकादमी भोपाल में वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने के संबंध में बैठक चर्चा में इनपुट प्रदान किया। जनवरी .

आर कविता राव

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के ग्रुप ए अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत में कर नीति डिजाइन में चुनौतियां पर आठ व्याख्यान दिए। अगस्त से अक्टूबर .

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

- सार्वजनिक वित्त में कागजात नई दिल्ली वर्चुअल प्रारूप पर एनआईपीएफपी आईआईपीएफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर एक सत्र की अध्यक्षता की। 9 जून .

- तंबाकू कराधान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया। अक्टूबर .

- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन तिरुवनंतपुरम केरल द्वारा आयोजित इंडियाज एक्सपीरियंस विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में जीएसटी आगे का रास्ता पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। नवंबर .

- दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठकों में भाग लिया। मई और दिसंबर .

- इंडिया इन्वेंटरी रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और मैपिंग इंडियाज एनर्जी सपोर्ट एंड रेवेन्यू बजटिंग फॉर नेट जीरो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कनाडा पर टिप्पणी की। मार्च .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग राजकोषीय क्षमता और प्रबंधन बढ़ाने पर कार्यबल।
- सदस्य तंबाकू कराधान पर विशेषज्ञ समूह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
- सदस्य दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड।
- पीएचडी थीसिस के लिए बाहरी रेफरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।
- पीएचडी थीसिस के लिए बाहरी रेफरी जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता।

इला पटनायक

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारत यूरोपीय संघ संबंध बिल्डिंग रिसाइलेंस इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड 19 पर एक वेबिनार में भाग लिया। 9 अप्रैल .
- माननीय उपाध्यक्ष नीति आयोग की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर एक वेबिनार में भाग लिया। अप्रैल .
- एलएसई साउथ एशिया सेंटर तथा इंस्टीट्यूट फॉर न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग न्यूयॉर्क द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अर्थ विवाद भारत एस्पिरेशन्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन्स इन द एज ऑफ नेशनलिस्ट कैपिटल नामक वार्षिक गोलमेज सम्मेलन में वक्ता के रूप वर्चुअली भाग लिया। जून .
- अनंत केंद्र द्वारा आयोजित द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट आफ्टर द सेकेंड कोविड वेव टेकिंग स्टॉक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पर एक वेबिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया। जून .
- सार्वजनिक वित्त में कागजात नई दिल्ली वर्चुअल फ़ारमैट पर एनआईपीएफपी आईआईपीएफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राजकोषीय नीति ऋण घाटे और आर्थिक गतिविधि पर सत्र के अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। 9 जून .
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर द्वारा आयोजित वें भारत नीति फोरम में वर्चुअल रूप से भाग लिया और भारत की विनिमय दर व्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया। जुलाई .
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली आरआईएस द्वारा आयोजित ब्रिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी सत्र में वक्ता और ब्रिक्स अकादमिक फोरम में

□एसडीजीस के वित्तपोषण के लिए एनडीबी को जुटाने□पर सत्र में मे मॉडरेटर के रूप में भाग लिया। □□ अगस्त □□□□.

- पुणे इंटरनेशनल सेंटर □पीआईसी□ पुणे द्वारा आयोजित □कोविड महामारी और भारत में असमानता□पर सत्र के अध्यक्ष और वक्ता के रूप में वर्चुअली भाग लिया। □□ अगस्त □□□□□.
- आर्थिक नीति जर्नल द्वारा आयोजित □वित्त□धन और जलवायु परिवर्तन□पर □□वीं आर्थिक नीति पैनल की बैठक में वर्चुअली भाग लिया। □□ अक्टूबर □□□□.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अरब नीति संस्थान□कुवैत के सहयोग से वर्चुअली आयोजित □अरेबियन सी डायलॉग्स□में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। □□ अक्टूबर □□□□.
- नीति आयोग द्वारा आयोजित □□ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था□पर परामर्शदात्री समूह की बैठक में भाग लिया।□□ नवंबर □□□□.
- सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा आयोजित सीएसआईएस वाधवानी चेयर प्रोग्राम में □पिछले □.□ वर्षों में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का मध्यावधि आकलन□और अगले □.□ वर्षों के लिए एजेंडा□पर बोलने के लिए भाग लिया □वर्चुअल□। □ दिसंबर □□□□.
- जोखिम की सार्वजनिक समझ के लिए लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित □अंडरस्टैंडिंग रिस्क एशिया □□□□□नामक वर्चुअल सम्मेलन में □वित्तीय प्रणाली में लचीलापन को एकीकृत करना – प्रेक्टीस्नर पर्सपेक्टिव□पर सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- ईवाई इंडिया द्वारा आयोजित □इंडियाज ग्रोथ रिबाउंड□फ्रॉम एम्बिशन टू एक्शन□पर वर्चुअल पॉलिसी राउंडटेबल में पैनल स्पीकर के रूप में भाग लिया। □9 दिसंबर □□□□.
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित □ए सस्टेनेबल पार्टनरशिप□इंडिया□कनाडा एंड ग्रीन फाइनेंस□ पर वर्चुअल पैनल चर्चा में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। □□ जनवरी □□□□.
- जेपी मॉर्गन द्वारा आयोजित □भारत□बजट के बाद का जीवन और आरबीआई□पर वर्चुअल पैनल चर्चा में भाग लिया। □□ फरवरी □□□□.
- यूनाइटेड किंगडम सरकार लंदन□यूके के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित □जी□□ और ग्लोबल गवर्नेंस□विषय पर प्रतिनिधिमंडल की यात्रा में भाग लिया।□□□□ मार्च □□□□.

सरकार□और□अन्य□निकायों□पत्रिकाओं□में□सदस्यता□

- सदस्य□सीडीआरआई में अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन पहल के लिए मूल्यांकन और संचालन समिति।

- सदस्य सलाहकार परिषद के सदस्य आधिकारिक मौद्रिक और वित्तीय संस्थान फोरम ओएमएफआईएफ।
- सदस्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली की अकादमिक परिषद।
- सदस्य टास्क फोर्स आपदा रोधी अवसंरचना सीडीआरआई के लिए गठबंधन की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करेगा।

लेखा चक्रवर्ती

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत पर व्याख्यान दिया। जून .
- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत और विकासात्मक लक्ष्यों के लिए वित्त पर व्याख्यान दिया गया। और मार्च .

आमंत्रित व्याख्यान

- अध्यक्ष के रूप में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र छात्र संगोष्ठी इकोनविस्टा में कोविड 9 विश्व में भारत आर्थिक दृष्टिकोण और नीति चुनौतियां पर एक भाषण दिया। अप्रैल .
- हार्वर्ड लॉ स्कूल ह्यूमन राइट्स क्लिनिक आर्बर के विद्वानों को जलवायु परिवर्तन और पानी तक पहुंच विशेष रूप से महिलाओं और बजटीय प्रक्रियाओं पर व्याख्यान दिया। अप्रैल .
- वीं बी.आर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा आयोजित 'जेंडर इन गवर्नेंस" पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी मे 'फेमिनाइजेसन ऑफ गवर्नेंस एंड जेंडर बजटिंग' पर व्याखान देने के लिए आमंत्रित किया। अप्रैल .
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस रेकजाविक आइसलैंड द्वारा आयोजित वीं कांग्रेस में पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण और भारत में राज्य स्तरीय बजटीय खर्च फ्लाईपेपर प्रभाव का विश्लेषण पर एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। मई .

- अर्थशास्त्र विभाग□सेंट माइकल कॉलेज□केरल के छात्रों के लिए □जेंडर बजटिंग□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जून □□□□.
- भारतीय राजस्व सेवा □कस्टम और अप्रत्यक्ष कर□राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी□भारत सरकार के □□वें बैच के लिए □सार्वजनिक नीति और प्रशासन□पर आइआइपीए कार्यक्रम में □सरकारी बजट□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जून □□□□.
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान □एनआईआरडीपीआर□हैदराबाद और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान□केरल में ग्रामीण विकास प्रमुख कार्यक्रम के लिए □जेंडर बजटिंग□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जून □□□□.
- स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स□हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित □कोविड □□9 और राजकोषीय मौद्रिक नीतियों□पर एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □ जुलाई □□□□.
- देवी अहलिया विश्वविद्यालय□इंदौर द्वारा आयोजित यूजीसी□एचआरडीसी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम □गुरु दक्षता□के लिए □कोविड□□9 से निपटने के लिए वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जुलाई □□□□.
- अर्थशास्त्र□प्रबंधन और सामाजिक विकास में नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित □भारतीय अर्थव्यवस्था□पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में □कोविड □□9 प्रभाव और आर्थिक नीति प्रतिक्रिया□ पर एक वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया □ऑनलाइन□। □ अगस्त □□□□.
- शताब्दी व्याख्यान श्रृंखला□यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज□अलुवा के उद्घाटन भाषण में □संकट के समय के दौरान आर्थिक नीतियां□पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। □□ अगस्त □□□□.
- बिट्स पिलानी□राजस्थान में □भारत में कोविड □□9 महामारी के लिए राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया□पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। □□ सितंबर □□□□.
- प्रो. के.के. सुब्रमण्यम मेमोरियल व्याख्यान तहत प्रो. के.के. सी. अच्युता मेनन□स्टडी एंड रिसर्च सेंटर किला और कॉसफोर्ड□त्रिशूर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित □कोविड महामारी के लिए मैक्रोपॉलिसी रिस्पॉन्स□वैधानिक चेतावनी□मैक्रो इज़ नॉट ईज़ी टू डाइजेस्ट□पर एक व्याख्यान दिया। □□ सितंबर □□□□
- प्रो. के.के. सुब्रमण्यम मेमोरियल व्याख्यान तहत प्रो. के.के. सी. अच्युता मेनन□स्टडी एंड रिसर्च सेंटर किला और कॉसफोर्ड□त्रिशूर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित □नीति अनिश्चितता की ओर सामान्यीकरण□ वैश्विक प्रतिक्रियाएँ महामारी□पर एक व्याख्यान दिया। □□ अक्टूबर □□□□.

- मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्थशास्त्र□ भारतीय अर्थव्यवस्था□ पोस्ट□रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में एक राष्ट्रीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में □मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता और कोविड □□9□पर एक व्याख्यान दिया। □□ नवंबर □□□□.

- ला अल्फांसो मरीना□उत्तरी गोवा में आईआईपीए द्वारा आयोजित भारतीय राजस्व सेवा □सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर□चरण□III के मध्य□कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए □संघीय कर हस्तांतरण□पर एक व्याख्यान दिया। □□ नवंबर से □□ दिसंबर □□□□.

- प्रो. के. रामचंद्रन नायर स्मृति व्याख्यान □□□□ तहत अर्थशास्त्र विभाग□केरल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित □राजकोषीय प्रतिक्रियाएँ महामारी□पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ दिसंबर □□□□.

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन□जिनेवा में □कोविद □□9 मैक्रो□फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स एंड लेबर मार्केट रिस्पॉन्स□पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया □ऑनलाइन□ □ फरवरी □□□□.

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन□जिनेवा द्वारा आयोजित □कोविद □□9 मैक्रो□फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स एंड लेबर मार्केट रिस्पॉन्स□पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया □ऑनलाइन□ □ फरवरी □□□□.

- सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज□पुणे में को □डिमिस्टिफाइंग यूनियन बजट □□□□□पर एक भाषण दिया। □ फरवरी □□□□

- स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स□केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए □केंद्रीय बजट □□□□ का मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क□पर एक व्याख्यान दिया। □ फरवरी □□□□.

- मार्च इवनिओस कॉलेज□तिरुवनंतपुरम में □केंद्रीय बजट □□□□□पर एक वेबिनार में पूर्ण व्याख्यान दिया। □□ फरवरी □□□□.

- विक्टोरिया कॉलेज□पालघाट के छात्रों को □केंद्रीय बजट □□□□ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था□पर व्याख्यान दिया। □□ फरवरी □□□□.

- महाराजा कॉलेज फॉर विमेन□तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित □केंद्रीय बजट □□□□□□□पर राष्ट्रीय वेबिनार मे बोली। □□ फरवरी □□□□.

- एनआईटी□राउरकेला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग□भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित □भारत के एसडीजीस हासिल करने की दिशा में लैंगिक समानता□पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में □सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति□ जेंडर बजटिंग□ पर एक व्याख्यान दिया। □□ फरवरी □□□□. क्रिस्टू जयंती कॉलेज□बेंगलुरु में □केंद्रीय बजट □□□□□सार्वजनिक निवेश और क्रौडिंग□पर एक भाषण दिया। □□ फरवरी □□□□.

- बंगाल इकोनॉमिक एसोसिएशन □बीईए□में □वैश्विक मैक्रोइओनोमिक अनिश्चितताओं के लिए वित्तीय नीति प्रतिक्रिया□पर एक व्याख्यान दिया। □□ मार्च □□□□

भागीदारी□बैठकें□और□सम्मेलन□आयोजित□करना□

- टैक्स ग्रुप मेलबर्न लॉ स्कूल और ऑक्सफोर्ड लॉ फैकल्टी द्वारा आयोजित □टैक्स लॉ एंड डेवलपमेंट □ टैक्स□पब्लिक फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट□पर पैनल में भाग लिया □ऑनलाइन□। □□ मई □□□□.

- एआईआईएलएसएफ और सिटीनेट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित □एसडीजीस को स्थानीय बनाने और शहरों को आर्थिक रूप से लचीला बनाने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए शहरी आर्थिक विकास बनाना□पर एक वेबिनार में भाग लिया। □□ जुलाई □□□□.

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस□रेकजाविक□आइसलैंड की □□वीं कांग्रेस में □कोविड □9 स्टिमुलस पैकेज और राजकोषीय□मौद्रिक नीति लिंकेज□पर एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। □□□□□ अगस्त □□□□.

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस□आइसलैंड विश्वविद्यालय□रेकजाविक की □□वीं कांग्रेस में □पारिस्थितिकीय वित्तीय हस्तांतरण और फ्लाईपेपर प्रभाव□पर पेपर □अमनदीप कौर□आर. मोहंती और दिव्य रंगन के साथ□प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया □ऑनलाइन□। □□□□□ अगस्त □□□□.

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस□आइसलैंड विश्वविद्यालय□रेकजाविक की □□ वीं कांग्रेस में □कोविड □9 और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज□वित्तीय और मौद्रिक नीति लिंकेज□पर पेपर प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया □ऑनलाइन□। □□□□□ अगस्त □□□□.

- इकोनॉमिक्स सोसाइटी ऑफ दौलत राम कॉलेज□दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित □कोविड □9 महामारी के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया□पर पैनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। □□ नवंबर □□□□.

- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन □जीआइएफटी□□केरल द्वारा आयोजित □जीएसटी□पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में □जीएसटी और अर्थव्यवस्था□पर एक सत्र की अध्यक्षता की। □□ नवंबर □□□□.

- आइएलओ□जिनेवा द्वारा आयोजित □नौकरी से समृद्ध और निष्पक्ष वसूली के लिए लिंग उत्तरदायी रोजगार नीतियों□पर पैनल चर्चा में भाग लिया □ऑनलाइन□। □ फरवरी □□□□.

- डी□स्ट्रीट एसआरसीसी □श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स□□दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बजट □□□□ के महत्वपूर्ण पहलुओं और अर्थव्यवस्था पर इसके असर पर चर्चा करने के लिए □ब्रेकिंग डाउन द बजट□ पर एक विशेषज्ञ पैनल चर्चा में भाग लिया। □ फरवरी □□□□.

- भारतीय प्रबंधन संस्थान□रांची द्वारा आयोजित □केंद्रीय बजट □□□□□पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया। □□ फरवरी □□□□.

- आईआईटी तिरुपति द्वारा आयोजित पोस्ट महामारी युग के लिए सार्वजनिक नीतियां पर एक पैनल में भाग लिया। फरवरी .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- बोर्ड सदस्य गवर्निंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस आईआईपीएफ म्यूनिख।

- बाहरी मूल्यांकनकर्ता पीएचडी थीसिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तीन शोध और मद्रास विश्वविद्यालय एक थीसिस।

प्रताप रंजन जेना

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी मे राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर व्याख्यान दिया ऑनलाइन। जून .

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित जीटीएन के ग्रुप ए अधिकारियों और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमिलनाडु वित्त पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी मे वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही पर एक व्याख्यान दिया।

आमंत्रित व्याख्यान

- संसदीय समिति सचिवालय संसदीय अनुसंधान और लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान पीआरआइडीइ लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मुद्दे पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। जून .

- सरकारी लेखा और वित्त संस्थान □आईएनजीएएफ□□लेखा महानियंत्रक□व्यय विभाग□भारत सरकार द्वारा आयोजित □पीएफएम प्रदर्शन मापन फ्रेमवर्क□□सार्वजनिक व्यय प्रबंधन□पर आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ सितंबर □□□□.

- आईएनजीएएफ□लेखा महानियंत्रक□व्यय विभाग□भारत सरकार द्वारा आयोजित □सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही□□सार्वजनिक व्यय प्रबंधन□पर आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □अक्टूबर □□□□.

- आईएनजीएएफ□लेखा महानियंत्रक□व्यय विभाग□भारत सरकार द्वारा आयोजित □सार्वजनिक व्यय प्रबंधन□पर □सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में राजकोषीय संघवाद और समकालीन मुद्दों□पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ अक्टूबर □□□□.

भागीदारी□बैठकें□और□सम्मेलन□आयोजित□करना□

- □विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के निर्धारकों पर व्यवस्थित साहित्य समीक्षा और ग्रंथ सूची विश्लेषण□□वां वैश्विक नेतृत्व अनुसंधान सम्मेलन□□□□□□एमिटी बिजनेस स्कूल□नोएडा□उत्तर प्रदेश □ऑनलाइन□। □□□□ फरवरी □□□□.

सरकार□और□अन्य□निकायों□पत्रिकाओं□में□सदस्यता□

- □नीति निर्माण□समन्वय और संवर्ग प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन व्यवस्था पर समिति□□लेखा महानियंत्रक□व्यय विभाग□वित्त मंत्रालय।

- सदस्य□□लोक सेवाओं में नवाचार पर समिति□□रक्षा मंत्रालय□भारत सरकार।

- भारत सरकार□एमओएफ और अन्य संगठनों के लिए की गई सलाहकार गतिविधियाँ

- भारत सरकार की व्यापक नीतियों के तहत सीजीए कार्यालय की संवर्ग प्रशिक्षण योजनाओं का निर्धारण करने के लिए □नीति निर्माण□समन्वय और संवर्ग प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन व्यवस्था□□लेखा महानियंत्रक□व्यय विभाग□वित्त मंत्रालय पर बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में प्रशिक्षण योजनाओं□ विषयों और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं पर चर्चा की गई।

- लोक सेवाओं में नवाचार पर समिति के सदस्य के रूप में□रक्षा मंत्रालय□भारत सरकार□इस उद्देश्य के लिए विकसित एक प्रारूप के बाद दर्ज सार्वजनिक सेवाओं में नवाचारों के साक्ष्य में शामिल है और विभिन्न छावनी बोर्डों द्वारा प्रस्तुत की गई बैठकों में पुरस्कार तय करने के लिए जांच की गई थी विजेता। यह अभ्यास छावनी बोर्डों में सार्वजनिक सेवाओं की भावना पैदा करने में मदद करता है।

मीता चौधरी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत में सार्वजनिक वित्त पोषण स्वास्थ्य पर आठ व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण पर एक व्याख्यान दिया। मार्च

आमंत्रित व्याख्यान

- एक्सेस हेल्थ इंटरनेशनल एंड हेल्थ सिस्टम्स कोलैबोरेटिव के सहयोग से पी एच और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डब्ल्यूएचओ इंडिया द्वारा आयोजित महामारी के समय में भारत में स्वास्थ्य वित्तपोषण पर एक पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 9 अक्टूबर .

भागीदारी बैठक और सम्मेलन आयोजित करना

- नेशनल हेल्थ अकाउंटिंग पर विशेषज्ञ समूह समिति के सदस्य के रूप में 9 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

- अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी विद्वान के लिए एसआरएफ समिति की बैठक के बाहरी विशेषज्ञ। 9 मई .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों पर विशेषज्ञ समूह।

- भारत सरकार एमओएफ और अन्य संगठनों के लिए की गई सलाहकार गतिविधियाँ

- वैक्सीन विकास वितरण प्रबंधन और महामारी कोविड 9 के शमन विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संबंधित पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब प्रस्तुत किए पिनाकी चक्रवर्ती के साथ दिसंबर .

सच्चिदानंद मुखर्जी

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार विभाग के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीएसटी मुद्दे और चुनौतियां पर एक व्याख्यान दिया। ऑनलाइन। जून .

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कराधान के सिद्धांत पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यम अवधि राजस्व रणनीति पर एक व्याख्यान दिया। मार्च .

भागीदारी बैठक और सम्मेलन आयोजित करना

- जर्मन विकास संस्थान आर्थिक नीतियों पर परिषद सीईपी और अदीस टैक्स इनिसिएटिव एटीआइ द्वारा आयोजित कर व्यय और घरेलू राजस्व संग्रहण पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय डीआरएम कार्यशाला में भारत में केंद्रीय करों पर कर व्यय के रुझान और पैटर्न पर एक पेपर प्रस्तुत किया ऑनलाइन। 9 नवंबर .

एच.के. अमरनाथ

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत में सार्वजनिक वित्त डेटाबेस संकल्पनात्मक मुद्दे और वर्गीकरण समायोजन पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी मे वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत बजट प्रणाली पर एक व्याख्यान दिया। मार्च .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने विभिन्न राज्य योजना योजनाओं और राज्य की जीएसडीपी को युक्तिसंगत बनाने वित्तीय क्षमता वित्तीय संसाधनों का विस्तार राजस्व और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के लिए राज्य योजना बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई अब तक।

- अध्यक्ष कार्यकारी समूह हाई पावर्ड टास्क फोर्स राज्य योजना बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार के तहत विभिन्न राज्य योजना योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के उपायों के सुझाव के लिए। जुलाई अब तक।

रेणुका साने

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी मे राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाजार विफलताओं और विनियमन और भारतीय दिवालियापन संहिता का परिचय पर व्याख्यान दिया। जून में।

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विनियमन और बाजार विफलता और विनिवेश प्रक्रियाएं और अनुभव पर व्याख्यान दिया। 9 मार्च .

आमंत्रित व्याख्यान

- ओपन इंटरऑपरेबल इनक्लूसिव और डिवाइस अगनोस्टिक पेमेंट शीर्षक वाले सत्र में पैनलिस्ट। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आर्किटेक्टिंग अप्रैल .

- वित्त प्रौद्योगिकी और कानून में अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र सीआरएएफटी और कानून द्वारा आयोजित लिंग और वित्त और पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद विशाल अंतर पर एक सत्र में पैनलिस्ट। अप्रैल .

- ड्वारा रिसर्च द्वारा सह□आयोजित भारत में डिजिटल ऋण क्षेत्र□और उभरते ग्राहक जोखिम□पर एक वर्चुअल चर्चा में पैनलिस्ट। □□ अप्रैल □□□□।

- लॉ एंड सोसाइटी एसोसिएशन □□□□ की वार्षिक बैठक में □उपभोक्ता वित्त विवादों में न्यायालयों द्वारा शिकायत निवारण□□करण गुलाटी के साथ□पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

□9 मई □□□□

- □वें ड्वारा अनुसंधान सम्मेलन में घरेलू वित्त□पर सत्र के लिए भारत में एक संपत्ति वर्ग के रूप में सोने को समझना□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □ जून □□□□.

- अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान □एजेएनआइफएम□द्वारा आयोजित डीइए□एजेएनआइफएम अनुसंधान कार्यक्रम के तत्वावधान में निवेशक चार्टर□पर एक वेबिनार में पैनल स्पीकर। □□ अगस्त □□□□.

- फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स के सहयोग से स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ एंड मार्केट रेगुलेशन□ आइआइसीए द्वारा आयोजित इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन□पर रेगुलेटरी गवर्नेंस कोर्स के तीसरे बैच के ऑनलाइन सत्र के दौरान व्याख्यान दिया।□□ नवंबर □□□□.

- इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट □आईएमपीआरआई इंडिया□द्वारा आयोजित द स्टेट ऑफ जेंडर इक्वलिटी □ □ जेंडरगैप्स□श्रृंखला के हिस्से के रूप में एसिमेट्रिक क्राइम डायनेमिक्स एंड सोशल इंटरेक्शन□पर डॉ रूबेन पोबलेट□कैज़नेव द्वारा एक विशेष वार्ता के लिए चर्चा। □□ नवंबर □□□□.

- इवाइ रिस्ट्रक्चरिंग एलएलपी और इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया □आइपीए □आइसीएआइ□द्वारा आयोजित इंडिविजुअल इन्सॉल्वेंसी□सत्र में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। □ दिसंबर □□□□.

- एक्सकेडीआर फोरम□सीएफएस□एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च और वेंडरबिल्ट लॉ स्कूल द्वारा आयोजित □कंज्यूमर क्रेडिट स्टीयरिंग□ए टेल ऑफ टू मार्केट्स□पर □□वें उभरते बाजार सम्मेलन में पैनलिस्ट। □□ दिसंबर □□□□.

- एक्सकेडीआर फोरम□सीएफएस□एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च□वेंडरबिल्ट लॉ स्कूल द्वारा आयोजित □ऋण अनुबंध प्रवर्तन और उत्पाद नवाचार□भारत में एक कानूनी सुधार से साक्ष्य□पर □□वें उभरते बाजार सम्मेलन में चर्चा। □□ दिसंबर □□□□.

- मीडियानामा के डिकोडिंग आफ डेटा प्रोटेक्सन बिल□कार्यक्रम द्वारा आयोजित डेटा संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां□कार्यक्रम पर एक पैनल में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जनवरी □□□□.

- फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटर्स एफओआईआर सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित एफओआईआर सदस्य संगठनों के नियामक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में विनियमन और उसके प्रबंधन के डिजाइन और प्रारूपण पर एक ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी .

- क्वांटम एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड मुंबई द्वारा आयोजित क्वांटम ग्रुप ऑफसाइट मे "बीहोल्ड द इंडियन सेवर – अपोर्चूनिटीज इन इंडियन एसेट मेनेजमेंट' सत्र पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। 9 मार्च .

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित विनियमन के अर्थशास्त्र पर व्याख्यान दिया। मार्च .

- 9वें एसकेओसीएच शिखर सम्मेलन में इंडिया इकोनॉमिक फोरम और एलआइटीएफएस्ट द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था और विनियमन पर पैनल चर्चाकर्ता। मार्च .

- इंडिकस फाउंडेशन द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन के लिए केवाईसी चुनौती को दरकिनार करने पर आईसीएफआई गोलमेज सम्मेलन पर एक ऑनलाइन सत्र में चर्चा करते हुए। मार्च .

- यूजीसी सीएएस ।के तहत मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर पब्लिक पॉलिसी पर एक सम्मेलन में भाग लिया। मार्च .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य पेंशन सलाहकार समिति पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए

- सदस्य समिति व्यक्तिगत दिवाला के कामकाज पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई

मनीष गुप्ता

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार विभाग डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा आईटीएस अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पर एक व्याख्यान दिया। जून .

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य बजट में मुद्दे पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारियों बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय निकायों और वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक व्याख्यान दिया। मार्च .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- सदस्य कार्य दल राज्य की जीएसडीपी वित्तीय क्षमता वित्तीय संसाधनों का विस्तार राजस्व और वित्तीय अनुशासन राज्य योजना बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ाने के उपायों के सुझाव के लिए। जुलाई अब तक।

रुद्राणी भट्टाचार्य

आमंत्रित व्याख्यान

- हंसराज कॉलेज नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम एफडीपी में प्रोबिंग द फ्रंटियर्स कंटेम्परारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन इकोनॉमिक्स पर व्याख्यान श्रृंखला के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। दिसंबर .

भागीदारी बैठक और सम्मेलनों का आयोजन

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित उत्पादकता प्रतिस्पर्धात्मकता और मुद्रास्फीति पर अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग डीईपीआर अनुसंधान संगोष्ठी में एक चर्चाकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। जून .

- पॉलिसी वॉच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित एमएसएमई के डिजिटलीकरण पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया। फरवरी .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- पीयर समीक्षक ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक समीक्षा के लिए पांडुलिपियां।

- पीयर समीक्षक इंडियन जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट।

- पीयर समीक्षक□आरबीआई ओकेसनल पेपर।
- पीयर समीक्षक□सेज इंडियन इकोनॉमिक जर्नल।
- पीयर समीक्षक□रूटलेज।

अमेय□सप्रे□

एनआईपीएफपी□प्रशिक्षण□कार्यक्रमों□में□व्याख्यान□

- एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान□नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान□एनटीआईपीआरआईटी□□दूरसंचार विभाग□डीओटी□□संचार मंत्रालय□भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवा□आईटीएस□अधिकारियों के लिए□गैर□वित्त अधिकारियों के लिए वित्त□पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में□डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन□और□राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल बातें□पर व्याख्यान दिया। □□ जून □□□□.
- वित्त विभाग जीओटीएन□चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स□एमएसइ□में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह□ए□अधिकारियों और समूह□बी□अधिकारियों के लिए□सार्वजनिक वित्त□पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में□बाजार की विफलताओं और विनियमन□पर □□ व्याख्यान दिए गए। □□ अगस्त □□□□ से □ अक्टूबर □□□□ और □□ अक्टूबर □□□□ से □□ दिसंबर □□□□.
- एनआईपीएफपी मे वित्त मंत्रालय□ईआरडी अधिकारियों□□बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए□सार्वजनिक वित्त□पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में□नीली अर्थव्यवस्था के अनुमान का परिचय□पर एक व्याख्यान दिया। □□ मार्च □□□□

आमंत्रित□व्याख्यान□

- भारतीय सांख्यिकी सेवा□राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी□एनएसएसटीए□□सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिवीक्षाधीनों के लिए□राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुसंधान क्षेत्र□ परियोजना चर्चा□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ जून □□□□.
- एनएसएसटीए□सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में□आधिकारिक सांख्यिकी में आईआईपी और प्रशासनिक डेटा का उपयोग□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। □□ फरवरी □□□□.
- एनएसएसटीए□सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में□व्यय पक्ष अनुमान और उपभोग व्यय के आकलन में मुद्दे□पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।□□ जनवरी □□□□.

भागीदारी□बैठकें□और□सम्मेलन□आयोजित□करना□

- भारतीय सांख्यिकी सेवा□ एनएसएसटीए□ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिवीक्षाधीनों का परियोजना मूल्यांकन। □ सितंबर □□□□.
- भारतीय सांख्यिकी सेवा□ एनएसएसटीए□ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिवीक्षाधीनों का परियोजना मूल्यांकन। □ अप्रैल □□□□.
- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स □एमएसई□ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से तमिलनाडु सरकार के लिए समूह □ए□ और समूह □बी□ अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन □ऑनलाइन□□ पिनाकी चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता के साथ□ □□ अगस्त □□□□ से □ अक्टूबर □□□□ और □□ अक्टूबर □□□□ से □□ दिसंबर □□□□ तक।
- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय □ईआरडी अधिकारियों□□ बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□ पर एक सप्ताह के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया □पिनाकी चक्रवर्ती के साथ□ □□ मार्च से □ अप्रैल □□□□.
- राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान□नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान □एनटीआईपीआरआईटी□□ दूरसंचार विभाग □डीओटी□□ संचार मंत्रालय के भारतीय दूरसंचार सेवा □आईटीएस□ अधिकारियों के लिए □गैर□ वित्त अधिकारियों के लिए वित्त□ पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। □भारत सरकार. □□□ □□ जून □□□□.

भारत□ सरकार□□ एमओएफ□ और□ अन्य□ संगठनों□ के□ लिए□ की□ गई□ सलाहकार□ गतिविधियाँ□

- पर्यावरण□ वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय□ भारत सरकार को □□ दिसंबर □□□□ को ड्यू राज्य सभा तारांकित प्रश्न □□□ □कार्बन की सामाजिक लागत□ के संबंध में उत्तर के लिए इनपुट प्रदान किए गए □सूरंजलि टंडन और पिनाकी चक्रवर्ती के साथ□

□

मुकेश□ आनंद□

□

एनआईपीएफपी□ प्रशिक्षण□ कार्यक्रमों□ में□ व्याख्यान□

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय □ईआरडी अधिकारियों□□ बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए □सार्वजनिक वित्त□ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में □लागत□लाभ विश्लेषण □ परियोजनाओं□सार्वजनिक व्यय□नीतियों के मूल्यांकन के लिए आवेदन□ और □जीवाश्म ईंधन की कीमतें□ एक विकासशील अर्थव्यवस्था की सुधार दुविधा□ पर व्याख्यान दिया गया। □□□□ मार्च □□□□.

- वित्त विभाग जीओटीएन चेन्नई द्वारा वित्तपोषित मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएसइ में सार्वजनिक वित्त केंद्र के सहयोग से आयोजित तमिलनाडु सरकार के समूह ए अधिकारियों और समूह बी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यय में सब्सिडी और पेंशन पर व्याख्यान दिए गए। अगस्त से अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर तक।

सरकार और अन्य निकायों में सदस्यता

- सदस्य कार्य समूह संस्थानों की पहचान करने और आईसीएएस अधिकारियों के डोमेन केंद्रित क्षमता निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए। कार्य समूह ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। 9 मई .

- इंडियन इकोनॉमिक जर्नल को प्रस्तुत लेखों के लिए रेफरी।

सुकन्या बोस

आमंत्रित व्याख्यान

- आरटीई फोरम द्वारा आयोजित बजट संगोष्ठी में केंद्रीय बजट और शिक्षा का अधिकार पर एक भाषण दिया वर्चुअल। फरवरी .

- शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा आयोजित एसडीजीजी पर राष्ट्रीय परामर्श में कोविड 9 के संदर्भ में एसडीजीजी का वित्तपोषण पर एक भाषण दिया वर्चुअल। दिसंबर .

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

- एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित शोध संगोष्ठी में एन इंक्वायरी इन एक्जिट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड रिसर्च बेस्ड अर्बन फ्रिंजेस ऑफ डेल्ही शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया वर्चुअल। मार्च .

- तुलनात्मक शिक्षा सोसाइटी ऑफ इंडिया सीईएसआई के वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शैक्षिक अवसर निजी आय और राज्य नीति एक शहरी फ्रिंज क्षेत्र में महामारी पर बातचीत शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया वर्चुअल। 9 दिसंबर .

- विश्व बैंक में भारत में शिक्षा के लिए अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया वर्चुअल। फरवरी .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- जर्नल ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के लिए रेफरी

- डॉक्टरेट रिसर्च फेलो के लिए सह-पर्यवेक्षक-बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग-साउथ कैंपस-दिल्ली विश्वविद्यालय।

सुरंजलि टंडन

एनआईपीएफपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान

- एनआईपीएफपी में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी दूरसंचार डीओटी संचार मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय दूरसंचार सेवाओं आईटीएस के अधिकारियों के लिए गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर पर व्याख्यान दिया। जून .

- एनआईपीएफपी में वित्त मंत्रालय ईआरडी अधिकारी बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्त पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर एक व्याख्यान दिया। मार्च .

आमंत्रित व्याख्यान

- एनएएलएसएआर विश्वविद्यालय हैदराबाद में कर संधियों के दायरे से बाहर करों के साथ स्कोप इशूस पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ऑनलाइन। दिसंबर .

- राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में समष्टि अर्थशास्त्र और वित्त पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ऑनलाइन। फरवरी .

भागीदारी बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन ऑनलाइन

- ग्लोबल टैक्स गवर्नेंस यूनिवर्सिटी ऑफ लीडेन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एंड डेवलपमेंट पर रिसर्च कॉलोक्वियम में चर्चा की। अप्रैल .

- लीडेन यूनिवर्सिटी में मिनिमम टैक्सेशन द यूएस प्रपोजल एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर राउंडटेबल प्रस्तुत किया। जून.

- एनआईपीएफपी आईआईपीएफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सार्वजनिक वित्त में कागजात नई दिल्ली में भारत में फर्म पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण पर एक पेपर प्रस्तुत किया। 9 जून .

- लीडेन यूनिवर्सिटी काउंसिल ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज एशिया पैसिफिक एफडीआई नेटवर्क और हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कराधान व्यापार और निवेश के बीच अंतर्संबंध पर कर प्रोत्साहन पर काम प्रस्तुत किया। जुलाई .

- ऑस्ट्रिया के रस्ट सम्मेलन में भारत में अनिवार्य प्रकटीकरण नियम पर एक पेपर प्रस्तुत किया। जुलाई .

- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में युद्ध और संकट के दौरान कर पर एक पेपर प्रस्तुत किया। जुलाई .

- कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल टैक्स कॉलोक्वियम में कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस एंड शेयरहोल्डिंग पैटर्न एविडेंस फ्रॉम इंडिया पर पेपर प्रस्तुत किया। अगस्त .

- लीडेन विश्वविद्यालय में पीएचडी कर संगोष्ठी पर पत्रों की चर्चा की। सितंबर .

- रीथिंकिंग इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित वैश्विक कर समझौते पर पैनलिस्ट। अक्टूबर .

- केयर और ऑक्टस ईएसजी द्वारा आयोजित इंडिया इंकस. ट्रिस्ट विद ईएसजी पर वेबिनार में पैनलिस्ट। अक्टूबर .

- पिलर पर इंटरनेशनल फिस्कल एसोसिएशन इंडिया वेबिनार में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। अक्टूबर .

- कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के वें तकनीकी सत्र में वैश्विक कर सुधार पर एक पेपर प्रस्तुत किया। 9 नवंबर .

- मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स बनाम टैक्स पॉलिसी द ग्रे एरिया इन इंटरनेशनल लॉ स्पीगल सोहमर टैक्स पॉलिसी कोलोक्विम पर एक पेपर प्रस्तुत किया। नवंबर .

- जर्मन विकास संस्थान आर्थिक नीतियों पर परिषद और अदीस टैक्स इनिसिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित घरेलू राजस्व संग्रहण पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एजेंडा और कर प्रोत्साहन के भविष्य पर इसके प्रभाव पर एक पेपर प्रस्तुत किया। नवंबर .

- वैश्विक वित्त सम्मेलन जिंदल विश्वविद्यालय में कानून नीतियां और विनियम अंतर्राष्ट्रीय कर संधि पर पैनलिस्ट। नवंबर .

- नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया कोयला ट्रांजिशन रिपोर्ट लॉन्च में पैनलिस्ट। नवंबर .

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एंड डेवलपमेंट यू.के. द्वारा आयोजित टैक्स ट्रीटीज एंड लोअर इनकम कंट्रीज डिफाइनिंग ए रिसर्च एजेंडा पर गोलमेज सम्मेलन में वक्ता। नवंबर

- ग्लोबल टैक्स सिम्पोजियम लीडेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स में लीड फॉर पिलर टू रिफॉर्म पर एक पेपर प्रस्तुत किया। दिसंबर .

- इंटरनेशनल टैक्स एंड रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन□बैंगलोर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में □वित्तीय नवाचारों से कर चुनौतियां□एसपीएसी□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□ दिसंबर □□□□.

- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन□नई दिल्ली द्वारा आयोजित □जी□□□ पर विशेषज्ञ गोलमेज सम्मेलन□में भाग लेने के लिए आमंत्रित।□□ जनवरी □□□□.

- □फाइनेंसिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी□पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन□नई दिल्ली द्वारा आयोजित □वें गोलमेज सम्मेलन में पैनलिस्ट। □□ फरवरी □□□□

- भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद□नई दिल्ली द्वारा आयोजित □क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन□क्या यह अच्छा है□□पर चर्चा में पैनलिस्ट। □ मार्च □□□□.

- टैक्ससूत्रा द्वारा आयोजित □जीएलओबीइ रूल्स□पर चर्चा में पैनलिस्ट। □□ मार्च□□□□.

- कैलिफोर्निया के चौथे वार्षिक विश्वविद्यालय□इरविन□ए लावर टेलर टैक्स संगोष्ठी में □द नीड फॉर ग्लोबल मिनिमम टैक्स□एसेसिंग पिलर टू रिफॉर्म□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□ मार्च □□□□.

सरकार□और□अन्य□निकायों□पत्रिकाओं□में□सदस्यता□

- वित्तीय विनियमन पर उप□समूह के लिए विशेष आमंत्रित□सतत वित्त पर टास्क फोर्स□आर्थिक मामलों के विभाग□वित्त मंत्रालय।

- प्रकटीकरण विवरण पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कार्य समूह में विशेषज्ञ आमंत्रित।

भारत□सरकार□□एमओएफ□और□अन्य□संगठनों□के□लिए□की□गई□सलाहकार□गतिविधियाँ□

- □सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन□के संबंध में □□ दिसंबर □□□□ को ड्यू राज्य सभा तारांकित प्रश्न □□□ के उत्तर के लिए पर्यावरण□वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय□भारत सरकार को इनपुट प्रदान किए गए □पिनाकी चक्रवर्ती और अमेय सप्रे के साथ□

□

दिनेश कुमार नायक

आमंत्रित व्याख्यान

- सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान कोलकाता में पूर्वोदय अवसरों का उदय पर द्विभाषी द्वि मासिक बुलेटिन के शुभारंभ पर एक्ट ईस्ट पूर्वोदय नीति के माध्यम से इकोनोमी रिजेनेरेशन पर एक वार्ता दी। नवंबर .

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

- भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी दक्षिण एशिया सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी की कार्यवाही में महिलाओं के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मध्य प्रदेश में दूसरी पीढ़ी के नकद हस्तांतरण कार्यक्रम से सीखे गए सबक बी हजारिका एन.आर. भानुमूर्ति और डी.के. नायक के साथ सह लेखाक पर एक पेपर प्रस्तुत किया। जनवरी .

- भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी साउथ एशिया सम्मेलन की कार्यवाही में द्वितीय पीढ़ी पैनल सह एकीकरण तकनीकों का उपयोग कर भारतीय उप राष्ट्रीय के लिए वैगनर के कानून की वैधता की पुन जांच डी.के. नायक और बी हजारिका के साथ सह लेखाक पर एक पेपर प्रस्तुत किया। जनवरी .

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी एआईबी

श्री हरि नायडू ए.

आमंत्रित व्याख्यान

- पीईएस विश्वविद्यालय बंगलौर में कॉर्पोरेट कराधान पर व्याख्यान दिया। 9 जून .

- पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कोविड और वित्तीय नीति पर व्याख्यान दिया। फरवरी .

- पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर व्याख्यान दिया। फरवरी .

- एसआरएम विश्वविद्यालय अमरावती आंध्र प्रदेश में भारतीय बजट पर व्याख्यान दिया। 9 फरवरी .

- अम्बेडकर विश्वविद्यालय□दिल्ली में □महामारी के समय में राजकोषीय नीति□पर व्याख्यान दिया। □□ मार्च □□□□.

- अम्बेडकर विश्वविद्यालय□दिल्ली में □वस्तु एवं सेवा कर□पर व्याख्यान दिया। □□ मार्च□□□□□.

सरकार□और□अन्य□निकायों□पत्रिकाओं□में□सदस्यता□

- जर्नल ऑफ़ मिलेनियल एशिया के लिए समीक्षक□सेज प्रकाशन।

भाबेश□हजारिका□

□

आमंत्रित□व्याख्यान□

- आईक्यूएसी□गुरुचरण कॉलेज□सिलचर के सहयोग से अर्थशास्त्र विभाग में □बजट □□□□□□□□एक स्नैपशॉट□पर व्याख्यान दिया। □□ फरवरी □□□□.

भागीदारी□बैठकें□और□सम्मेलन□आयोजित□करना□

- दक्षिण एशिया के लिए अनुसंधान कौशल पर आईज़ेडए □एफसीडीओ लघु पाठ्यक्रम□आईज़ेडए श्रम अर्थशास्त्र संस्थान □ऑनलाइन□। □□□□ सितंबर □□□□.

- एक अंतर्राष्ट्रीय खरीद सम्मेलन □□□□□आपूर्ति प्रबंधन संस्थान में भाग लिया □ऑनलाइन□। □□□□ सितंबर □□□□.

- भारतीय प्रबंधन संस्थान□विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी□दक्षिण एशिया सम्मेलन □□□□ की कार्यवाही में □भारतीय सार्वजनिक खरीद में एक मूल्यांकन पैरामीटर के रूप में गुणवत्ता□एल□ के लिए वैकल्पिक रणनीतियों की खोज□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□□□ जनवरी □□□□.

- भारतीय प्रबंधन संस्थान□विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी□दक्षिण एशिया सम्मेलन □□□□ की कार्यवाही में □सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम में हस्तक्षेप और महिलाओं की भागीदारी□एक फील्ड प्रयोग से साक्ष्य□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□□□ जनवरी □□□□.

- भारतीय प्रबंधन संस्थान□विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी□दक्षिण एशिया सम्मेलन □□□□ की कार्यवाही में □महिलाओं के बीच स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन□मध्य प्रदेश में दूसरी पीढ़ी के नकद हस्तांतरण कार्यक्रम से सीखे गए सबक□पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□□ □□ जनवरी □□□□.

- भारतीय प्रबंधन संस्थान□विशाखापत्तनम द्वारा आयोजित एआईबी□दक्षिण एशिया सम्मेलन □□□□ की कार्यवाही में दूसरी पीढ़ी के पैनल सह□एकीकरण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय उप□राष्ट्रीय के लिए वैगनर के कानून की वैधता की पुन□जांच पर एक पेपर प्रस्तुत किया। □□□□ जनवरी □□□□.

सरकार और अन्य निकायों पत्रिकाओं में सदस्यता

● अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी

अमनदीप कौर

भागीदारी बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना

• एनआईपीएफपी आईआईपीएफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सार्वजनिक वित्त में कागजात नई दिल्ली पर पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण और भारत में राज्य स्तरीय बजटीय खर्च फ्लाई पेपर प्रभावों का विश्लेषण पर एक पेपर प्रस्तुत किया ऑनलाइन 9 जून .

• इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की वीं वार्षिक कांग्रेस में पारिस्थितिक वित्तीय हस्तांतरण और स्थानीय सरकार खर्च महामारी के युग में फ्लाईपेपर प्रभाव पर एक पेपर प्रस्तुत किया ऑनलाइन अगस्त .

अनुबंध

अनुबंध अध्ययन की सूची

पूर्ण अध्ययन

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	मध्य प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम और 9 के प्रावधानों के अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा दिसंबर से सितंबर	मध्य प्रदेश सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
	सिक्किम सरकार द्वारा राज्य एफआरबीएम अधिनियम वर्ष 9 के अनुपालन की समीक्षा अगस्त से मार्च	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
	हरियाणा में राज्य वित्त आयोगों के तहत शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण पर एक अध्ययन एक महत्वपूर्ण समीक्षा जून से दिसंबर	छठा हरियाणा राज्य वित्त आयोग	मनीष गुप्ता स्मृति बहल और संप्रीत कौर
	गर्भवती महिला मजदूरों के बीच बेहतर स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर सशर्त नकद हस्तांतरण का प्रभाव मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश से साक्ष्य फरवरी से नवंबर	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश	भावेश हजारिका दिनेश कुमार नायक एन.आर. भानुमूर्ति कनिका गुप्ता और मनीष प्रसाद
	सिक्किम के लिए मध्यम अवधि की वित्तीय योजना से जून से अगस्त	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना
	राजस्थान की कोविड महामारी और वित्त मुद्दे और विकल्प सितंबर से मार्च	मुख्यमंत्री राजस्थान की आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद सीएमआरईटीएसी	पिनाकी चक्रवर्ती मनीष गुप्ता और स्मृति मेहरा
	केंद्र सरकार के लिए एक आधारभूत ऋण स्थिरता विश्लेषण डीएसए अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	मैक्रो डैशबोर्ड वित्तीय बाजारों में उभरते तनाव को पकड़ने वाले संकेतकों का दृश्य प्रतिनिधित्व अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
9	वित्तीय स्थिरता पर मासिक रिपोर्ट अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक	आर्थिक मामलों का	इला पटनायक और

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	के संबंध में उठाए गए मुद्दों की जांच पर टिप्पणी और उनके समाधान के लिए प्रस्तावित उपाय अप्रैल से मार्च	विभाग वित्त मंत्रालय	डीईए दल
	भारत के लिए वित्तीय तनाव संकेतकों पर नोट अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	भारत में बैंकिंग क्षेत्र के आकार और आकार बढ़ाने के उपायों पर नोट अप्रैल से मार्च	आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं सीबीडीसी और दुनिया भर में हाल के विकास पर नोट्स अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण और निवारण एजेंसी पर नोट्स अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	उभरती निजी क्रिप्टो मुद्राओं और स्थिर सिक्कों के वित्तीय कानूनी और सुरक्षा प्रभावों पर नोट्स अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठकों के लिए प्रस्तुति और नोट्स अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक और डीईए दल
	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के लिए ट्रान्स्पेरंसी आडिट जुलाई से दिसंबर	केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सौंपा गया	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
	भारत में शिक्षा के लिए अंतर सरकारी वित्तीय स्थानान्तरण अप्रैल अक्टूबर	विश्व बैंक	सुकन्या बोस नूपुर और श्री हरि नायडू ए
9	सरकारी स्कूलों को छोड़ने की जांच अप्रैल 9 से सितंबर	अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट	सुकन्या बोस प्रियंता घोष मनोहर बोड़ा और अरविंद सरदाना एकलव्य मध्य प्रदेश
	एशिया प्रशांत में कोविड 9 और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का विश्लेषण अगस्त से मई	बीएमजीएफ के तहत सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार	लेखा चक्रवर्ती अमनदीप कौर दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
1	न्याय चुनौती के लिए डेटा दिसंबर 2020 से जून 2021	वयम फोरम फॉर सिटिजनशिप	इला पटनायक, देवेंद्र दामले, तुषार आनंद और करण गुलाटी
2	डेटा गवर्नेंस नेटवर्क 31 मार्च 2021 को पूरा हुआ	आईडीएफसी फाउंडेशन और ओमिडयार नेटवर्क्स	ऋषभ बेली, स्मृति परशीरा, फैजा रहमान, वरुण सेन बहल और त्रिशी गोयल
3	राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतन डाटा बैंक अप्रैल 2020 से मार्च 2021	एनआईपीएफपी	एच.के. अमरनाथ, रोहित दत्ता और श्री हरि नायडू ए.
4	राज्य वित्त में उभरते मुद्दे, राज्य बजट 2020-21 का विश्लेषण अप्रैल, सितंबर 2020	एनआईपीएफपी	पिनाकी चक्रवर्ती और मनीष गुप्ता
5	भारत में रुग्णता और अस्पताल में भर्ती के उभरते रुझान, एक महत्वपूर्ण आकलन जून 2019 से जनवरी 2020	बीएमजीएफ के तहत भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण, आगे का रास्ता	मीता चौधरी और जय देव दुबे
6	पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय वित्तीय स्थानान्तरण अगस्त 2019 से अगस्त 2020	स्वयं की पहल	लेखा चक्रवर्ती, अमनदीप कौर और रंजन मोहंती
7	वैश्विक दक्षिण में राजकोषीय संघवाद अगस्त 2019 से दिसंबर 2020	बीएमजीएफ के तहत सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार	लेखा चक्रवर्ती, गुरलीन कौर, अमनदीप कौर, जेनेट फरीदा जैकब, अनिंदिता घोष और दिव्य रंगन
8	अनपैड केयर इकॉनमी के लिए राजकोषीय नीति फरवरी 2019 से दिसंबर 2020	स्वयं की पहल, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी के साथ अनुसंधान सहयोग	लेखा चक्रवर्ती
9	प्रति रुपया अधिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक खर्च की	बीएमजीएफ के तहत	मीता चौधरी,

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	दक्षता और वितरण में देरी मई से फरवरी	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण आगे का रास्ता	द्वीपोबोटी ब्रह्मा
	बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त गुजरात ओडिशा कर्नाटक और तेलंगाना का राज्य स्तरीय विश्लेषण अगस्त 9 से दिसंबर	बीएमजीएफ के तहत सार्वजनिक वित्त परियोजना में नवाचार	लेखा चक्रवर्ती अमनदीप कौर दिसंबर तक अनिंदिता घोष के साथ और जेनेट फरीदा जैकब
	भारत में सार्वजनिक खरीद तंत्र एल के लिए विकल्पों की खोज फरवरी से जून	एनआईपीएफपी में स्व वित्तपोषित	भाबेश हजारिका और आयुषी जैन
	शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक समानता और वित्तीय स्पेस पर लैंगिक बजट की क्षेत्रीय खर्च प्रभावशीलता एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अध्ययन सितंबर 9 से दिसंबर	स्व आरंभ की गई परियोजना पहले संस्करण को अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन अटलांटा की बैठकों में प्रस्तुत किया गया	लेखा चक्रवर्ती
	अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास आउटलुक ईएसी पीएम के लिए नोट वर्ष के दौरान ईएसी पीएम के लिए चार त्रैमासिक रिपोर्टें पूरी की गईं अक्टूबर से सितंबर	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	पिनाकी चक्रवर्ती आर. कविता राव लेखा चक्रवर्ती प्रताप आर. जेना मनीष गुप्ता रुद्रानी भट्टाचार्य अमेय सप्रे श्रुति त्रिपाठी और दिनेश के. नायक
	फार्मास्युटिकल दवाओं की सार्वजनिक खरीद और गुणवत्ता नियंत्रण पर अध्ययन जून से अप्रैल	ठाकुर फैमिली फाउंडेशन	इंक. इला पटनायक हरलीन कौर मधुर मेहता आशिम कपूर और सिद्धार्थ श्रीवास्तव

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	भारत में उप राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता विश्लेषण ओडिशा और हिमाचल प्रदेश अप्रैल से सितंबर	विश्व बैंक नई दिल्ली	पिनाकी चक्रवर्ती मनीष गुप्ता और स्मृति मेहरा
	डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियां अप्रैल से मार्च	स्वयं की पहल	सुरंजलि टंडन
	राज्य के वित्त पर कोविड 19 महामारी का सीज़र्स इफ़ेक्ट व्यय पर उभरते साक्ष्य अगस्त से जनवरी	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण के तहत बीएमजीएफ आगे का रास्ता	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
	दो अध्ययन केंद्र प्रायोजित योजनाएं सीएसएस पुनर्गठन और युक्तिकरण तथा पोस्ट कोविड वित्तीय ढांचा वर्ष के दौरान ईएसी पीएम के लिए मुद्दे और विकल्प पूरे किए गए थे जुलाई से सितंबर	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	ए.एन. झा यश जालुका और पिनाकी चक्रवर्ती

जारी अध्ययन

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन जीवीए और निवेश में योगदान जून से मार्च	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय	इला पटनायक प्रमोद सिन्हा और रचना शर्मा
	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई डिजाइन रूपरेखा उभरते पैटर्न और सरकार को लागत अक्टूबर से जून	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी एनएचए	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
	भारतीय रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक रखरखाव के लिए नीति निर्माण को सक्षम करने के लिए इनपुट प्रदान करना अक्टूबर से अक्टूबर	कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय संगठन रेलवे	रेणुका साने
	प्रौद्योगिकी नवाचार की सार्वजनिक खरीद नवंबर से दिसंबर	नीति आयोग के डेटा प्रबंधन और विश्लेषण और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज वर्टिकल द्वारा शुरू किया गया	अन्ना रॉय और भाबेश हजारिका
	वित्तीय प्रशासन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड सरकार देहरादून को अनुसंधान और परामर्श सहायता जुलाई से अगस्त	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र पीडीयू सीटीआरएफए उत्तराखंड सरकार	प्रताप रंजन जेना दिनेश नायक भाबेश हजारिका और मनीष गुप्ता
	एनआईपीएफपी डीईए अनुसंधान कार्यक्रम अप्रैल से मार्च	आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय	इला पटनायक राधिका पांडे प्रमोद सिन्हा रचना शर्मा गणेश गोपालकृष्णन देवेंद्र दामले आशिम कपूर अरुमा खान उत्सव सक्सेना सिमरन कौर राम्या राजश्री कुमार कृति

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
			वट्टल रितिका सिंह और आनंदिता गुप्ता
	भारतीय सार्वजनिक वित्त सांख्यिकी के लिए टेम्पलेट और मैनुअल मे संशोधन अप्रैल से जून	आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय	एच.के. अमरनाथ मनीष गुप्ता और श्री हरि नायडू ए.
	कर नीति और अनुपालन के प्रति व्यवहार का आकलन जनवरी से दिसंबर	स्वयं की पहल	आर. कविता राव
9	जीआरएम तंत्र का आधारभूत अध्ययन भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल नवंबर से मई	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बीएमजीएफ जीआरएम	रेणुका साने सृष्टि शर्मा ऐश्वर्या गवली मार्गी पांड्या और नैंसी गुप्ता
	स्वास्थ्य में सार्वजनिक प्रावधान को कोम्प्लेमेंटिंग करना क्या सार्वजनिक और निजी प्रदाता सह अस्तित्व में हैं अगस्त से जून	बीएमजीएफ के तहत भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण आगे का रास्ता	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
	वित्त खातों से राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतन डेटा बैंक सतत	एनआईपीएफपी	एच.के. अमरनाथ और रोहित दत्ता
	एशिया प्रशांत में सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति भारत में जेंडर बजटिंग जनवरी से अक्टूबर	स्वयं की पहल	लेखा चक्रवर्ती
	शिक्षा वित्तपोषण पर कोविड 9 का प्रभाव अक्टूबर से जून	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन	सुकन्या बोस और हर्षिता शर्मा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन
	गुजरात में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का अंतर राज्य वितरण क्षैतिज और लंबवत इक्विटी अगस्त से जून	बीएमजीएफ के तहत भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण आगे का रास्ता	मीता चौधरी और जय देव दुबे
	भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रोइकोनोमेट्रिक मॉडलिंग सतत	स्वयं की पहल	सुकन्या बोस और एन. आर. भानुमूर्ति

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
	भूमि बाजार को काम के लिए बेहतर बनाना अप्रैल 9 से मार्च	ओमिडयार नेटवर्क	इला पटनायक देवेंद्र दामले तुषार आनंद करण गुलाटी विराज जोशी विशाल त्रेहन सिद्धार्थ श्रीवास्तव सारंग मोहरीर गुंटास कौर उप्पल नमिता गोयल और आंशी शर्मा
	ईएसी पीएम भारतीय अर्थव्यवस्था पर त्रैमासिक रिपोर्टस और ईएसी पीएम द्वारा सुझाए गए प्रासंगिक विषयों पर दो अध्ययन फरवरी	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	पिनाकी चक्रवर्ती लेखा चक्रवर्ती मनीष गुप्ता रुद्रानी भट्टाचार्य और दिनेश के. नायक
	सतत विकास में सार्वजनिक खर्च शासन और क्षेत्रीय असमानता असम में एक जिला स्तरीय विश्लेषण मार्च से फरवरी	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	भाबेश हजारिका
9	पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य स्तर पर स्वास्थ्य खर्च के लिए निहितार्थ सितंबर से मई	भारत में स्वास्थ्य के सार्वजनिक वित्तपोषण के दृष्टिकोण के तहत बीएमजीएफ आगे का रास्ता	मीता चौधरी और गरिमा नैन
	भारत में राज्य वित्त आयोगों के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन दिसंबर से मार्च	यूनिसेफ इंडिया	मनीष गुप्ता स्मृति बहल सोनल अग्रवाल देवयानी गुप्ता और प्रियांशी गर्ग
	भारत में राज्य वित्त के मुद्दों की समीक्षा कुछ एम्पेरिकल इंवेस्टिगेश्न्स नवंबर से दिसंबर	स्वयं की पहल	भाबेश हजारिका और दिनेश कुमार नायक
	स्कूली शिक्षा पर जेंडर सेंसिटिव बजटिंग पर अध्ययन दिसंबर 9 से दिसंबर	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय गठबंधन	सुकन्या बोस और अनुराधा डे क्रॉर्ड
	राजकोषीय संघवाद और लैंगिक समानता जनवरी से दिसंबर	फोरम ऑफ फेडरेशन	लेखा चक्रवर्ती और दिव्य रंगन जून

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	अनुसंधान दल
			तक
	भारत में वृद्धावस्था आय सहायता प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय सुधार पर पुसीफुटिंग संभावित समापन – मई	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
	राजस्व व्यय की संरचना में परिवर्तन कुछ अंतर और अंतर पीढ़ीगत सरोकार संभावित समापन– मई	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
	जीवाश्म ईंधन के मूल्य परिवर्तन का प्रभाव संभावित समापन जून	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
	भारत में श्रम बल की भागीदारी में गिरावट क्या कुछ नीतियां मिसअलीगनेड हैं संभावित समापन जुलाई	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
	भारत में सामाजिक पेंशन एक सार्वभौमिक बुनियादी आय कार्यक्रम के अग्रगामी संभावित समापन अगस्त	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
9	सार्वजनिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का निर्धारण नौकरी विवरण और संबंधित कर्मचारी प्रोफ़ाइल पर क्यों विचार करना चाहिए संभावित समापन सितंबर	स्वयं की पहल	मुकेश कुमार आनंद और राहुल चक्रवर्ती
	सीजीटीएमएसई के लिए गारंटी योजनाओं के लिए डेटा विश्लेषण जुलाई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTM	अनन्या गोयल और मिथिला ए. सारा

शुरू किए गए नए अध्ययन

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	टीम के सदस्य
	आंध्र प्रदेश राज्य के राजस्व पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की वापसी का प्रभाव फरवरी से अप्रैल	वाणिज्यिक कर विभाग एपी सरकार	आर कविता राव भाबेश हजारिका और अशोक भाकर
	सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही पीईएफए उत्तराखंड राज्य के लिए आकलन अप्रैल से मार्च	उत्तराखंड सरकार	प्रताप रंजन जेना दिनेश नायक और भाबेश हजारिका
	मध्य प्रदेश में आर्थिक मूल्यांकन और उभरते वित्तीय परिदृश्य मार्च	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान एआईजीजीपीए भोपाल एमपी सरकार	पिनाकी चक्रवर्ती और अमेय सप्रे
	पुडुचेरी के अनुमान जीएसडीपी का तृतीय पक्ष द्वारा आकलन मार्च –	पुडुचेरी सरकार	अमेय सप्रे
	राष्ट्रीय अनुकूलन संचार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफसीसी भारत सरकार फरवरी	मंत्रालय के लिए नीतिगत इनपुट कोई फंडिंग नहीं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	लेखा चक्रवर्ती अजय नारायण झा और अमनदीप कौर
	एनआईपीएफपी डीईए अनुसंधान कार्यक्रम अप्रैल से मार्च	आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय	आर. कविता राव राधिका पांडे प्रमोद सिन्हा रचना शर्मा अशिम कपूर रितिका सिंह सिमरन कौर उत्सव सक्सेना कृति वट्टल राम्या आर. कुमार और आनंदिता गुप्ता
	भारत के लिए कार्बन रणनीति और निवेश के लिए इसके दीर्घकालिक प्रभाव जनवरी से दिसंबर	नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड	सुरंजलि टंडन
	बाल संरक्षण सार्वजनिक व्यय समीक्षा	यूनिसेफ	लेखा चक्रवर्ती और

क्र.सं.	शीर्षक	प्रायोजक	टीम के सदस्य
	ओडिशा यूनिसेफ फरवरी		अमनदीप कौर
9	भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के वित्तीय बोझ का आकलन संभावित प्रारंभ – अप्रैल	स्वयं द्वारा शुरू किया गया	सच्चिदानंद मुखर्जी
	उपराष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता विश्लेषण और वित्तीय जोखिम अप्रैल से जून	विश्व बैंक	आर. कविता राव मनीष गुप्ता और सोनल अग्रवाल
	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के लिए पारदर्शिता आडिट जून से दिसंबर	केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सौंपा गया	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
	राज्य वित्त का डिजिटलीकरण और अद्यतन डाटा बैंक अप्रैल से मार्च	एनआईपीएफपी	एच.के. अमरनाथ रोहित दत्ता और श्री हरि नायडू ए.

अनुबंध एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र श्रृंखला

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
	भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-एनएएम कितना प्रभावी है प्याज बाजार से साक्ष्य अप्रैल सं.	रुद्राणी भट्टाचार्य और सबरनी चौधरी
	कोविड -9 महामारी के समय में भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन मई सं.	सच्चिदानंद मुखर्जी और शिवानी बडोला
	भारत में उप-राष्ट्रीय बजट विश्वसनीयता संस्थागत परिप्रेक्ष्य और सुधार एजेंडा जुलाई सं.	प्रताप रंजन जेना और अभिषेक सिंह
	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र: वित्त निवेश और फर्मों का प्रदर्शन अगस्त सं. 9	मनोहर अग्रवाल और रूमी अज़ीम
	दिल्ली में स्कूलों के लिए विनियमन और अनौपचारिक बाजार अगस्त सं.	सुकन्या बोस प्रियंत घोष अरविंद सरदाना और मनोहर बोडा
	वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाना अगस्त सं.	लेखा चक्रवर्ती
	परिवर्तन के साथ निरंतरता: पंद्रहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण अगस्त सं.	अजय नारायण झा
	भारतीय परिवारों की खपत मात्रा : सीपीआई सीईएस और सीपीएचएस से अनुमानों की तुलना करना अगस्त सं.	अनन्या गोयल राधिका पाण्डेय और रेणुका साने
9	वित्तीय शिक्षा के माध्यम से उत्पाद-विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करना अगस्त सं.	ओल्गा बालाकिना विमल बालासुब्रामणियम अदिति डिमरी और रेणुका साने
	नेटवर्क में अनेक सार्वजनिक वस्तुएं अगस्त सं.	राजेंद्र पी. कुंडू और सिद्धिज्ञान पाण्डेय
	सहयोगी नेटवर्कों का उद्भव	सिद्धिज्ञान पाण्डेय

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
	□अगस्त □□□□□सं. □□□□	
□□	जीएसटी विधि और प्रक्रियाओं में उभरते मुद्दे : एक आकलन □अगस्त □□□□□सं. □□□□	सच्चिदानंद मुखर्जी
□□	विनिर्मित वस्तुओं में अंतर-उद्योग व्यापार: भारत का मामला □अगस्त □□□□□सं. □□□□	मनमोहन अग्रवाल और नेहा बेताई
□□	दिल्ली उच्च न्यायालय में भूमि और संपत्ति से संबंधित मुकदमे की विशेषता □अगस्त □□□□□सं. □□9□	देवेंद्र दामले और करण गुलाटी
□□	भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बौद्धिक अधिकार □अगस्त □□□□□सं. □□□□	करण गुलाटी और तुषार आनंद
□□	कोविड-□9 संदर्भ और पंद्रहवां वित्त आयोग: राजकोषीय आवश्यकता और व्यापक आर्थिक स्थिरता को संतुलित करना □अगस्त □□□□□सं. □□□□	पिनाकी चौधरी
□□	कोविड-19 टीकाकरण के मैक्रो डायनैमिक्स पर □अगस्त □□□□□सं. □□□□	सौम्या दत्ता और सी. सरतचंद
□□	भारत की विनिमय दर प्रणाली का विश्लेषण □सितम्बर □□□□□सं. □□□□	इला पटनायक और राजेश्वरी सेनगुप्ता
□9	कर डिजिटल अर्थव्यवस्था के समाधान की तलाश में □अक्टूबर □□□□□सं. □□□□	सुरांजलि टंडन
□□	कोविड-□9 और बच्चों के लिए सार्वजनिक निवेश: भारतीय राज्य कर्नाटक का मामला □अक्टूबर □□□□□सं. □□□□	जेनेट फरीदा जैकब और लेखा चक्रवर्ती
□□	राजस्व में कमी और जीएसटी प्रतिकर : एक आकलन □अक्टूबर □□□□□सं. □□□□	सच्चिदानंद मुखर्जी
□□	भारत की त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि: एक कारक-संवर्धित समय-भिन्न गुणांक प्रतिगमन मॉडल (एफए-टीवीसीआरएम□ □अक्टूबर □□□□□सं. □□□□	रुद्राणी भट्टाचार्य□बोर्नाली भंडारी और सुदीप्तो मंडल

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
□□	भारत में जीएसटी दरों के पुनर्गठन की राजस्व विवक्षाएं: एक विश्लेषण □नवम्बर □□□□□सं. □□□□	सच्चिदानंद मुखर्जी
□□	भारत में राजकोषीय प्रभुत्व : एक व्यावहारिक अनुमान □नवम्बर □□□□□सं. □□9□	अंशुमन कामिला
□□	आर्थिक सिद्धांत बनाम आर्थिक वास्तविकता: महामारी और अन्य वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं और बुराइयों से निपटना □नवम्बर □□□□□सं. □□□□	विटो तांजी
□□	कारक-संवर्धित समय-भिन्न गुणांक प्रतिगमन मॉडल के आधार पर □□□□□□□ जीडीपी विकास और □□□□□□□ के लिए पूर्वानुमान का नाउकास्ट □दिसम्बर □□□□□सं. □□□□	रुद्राणी भट्टाचार्य और सुदीप्तो मंडल
□□	कोविड -□9 और जेंडर बजटिंग: भारत में केंद्रीय बजट में □जेंडर अन्वेषण□लागू करना □दिसम्बर □□□□□सं. □□□□	लेखा चक्रवर्ती
□□	वैश्विक दक्षिण में राजकोषीय संघवाद का विश्लेषण: दक्षिण अफ्रीका□ केन्या□इथियोपिया और नेपाल □दिसम्बर □□□□□सं. □□□□	लेखा चक्रवर्ती□गुरलीन कौर□ दिव्य रंगन□अमनदीप कौर और जेनेट फरीदा जैकब
□9	भारतीय वित्तीय विनियामकों में शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) से संबंधित मुद्दे □जनवरी □□□□□सं. □□□□	करण गुलाटी और कार्तिक सुरेश
□□	क्या भारतीय वित्तीय फर्मों के पास एक मजबूत शिकायत निवारण ढांचा है□ □जनवरी □□□□□सं. □□□□	विमल बालासुब्रामणियम□रेणुका साने□मिथिला और कार्तिक सुरेश
□□	एक सुदृढ़ जीआरएम डिजाइन करना: सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव □जनवरी □□□□□सं. □□□□	सुदीप्तो बनर्जी और अदिति डिमरी।
□□	राजकोषीय भ्रम और वैगनर का नियम: भारतीय उप-राष्ट्रीय वित्त से साक्ष्य □जनवरी □□□□□सं. □□□□	भावेश हज़ारिका और दिनेश कुमार नायक

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
□□	कोविड-□9 और बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त: भारत के ओडिशा राज्य का एक मामला अध्ययन □जनवरी □□□□□सं. □□□□	अमनदीप कौर और लेखा चक्रवर्ती
□□	राज्य के वित्त पर कोविड-□9 महामारी का □प्रतिकूल प्रभाव□□व्यय पर उभरते साक्ष्य □जनवरी □□□□□सं. □□9□	मीता चौधरी और प्रीतम दत्ता
□□	भारत में जिला स्तर पर बाल विकास सूचकांक का अनुमान – क्रियाविधि □फरवरी □□□□□सं. □□□□	रितु माथुर□ नम्रता जैती और एच.के. अमरनाथ
□□	भारत में बाल विकास सूचकांक : जिला स्तर पर प्रदर्शन □फरवरी □□□□□सं. □□□□	रितु माथुर□ नम्रता जैती और एच.के. अमरनाथ
□□	कोविड-□9 और अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था: भारत में राजकोषीय नीति और समय आवंटन पर साक्ष्य □फरवरी □□□□□सं. □□□□	लेखा चक्रवर्ती
□□	भारत में विनिवेश का इतिहास □□99□□□□□□ □मार्च □□□□□सं. □□□□	सुदीप्तो बनर्जी□रेणुका साने□श्रष्टि शर्मा और कार्तिक सुरेश
□9	भारतीय उप-नागरिकों पर आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: दूसरी पीढ़ी की पैनल सह-एकीकरण तकनीकें □मार्च □□□□□सं. □□□□	दिनेश कुमार नायक और भावेश हजारिका
□□	भारत में उप-राज्य स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय की प्रगति: तमिलनाडु और बिहार में अनुभवजन्य जांच □मार्च □□□□□सं. □□□□	प्रीतम दत्ता□जय देव दुबे और मीता चौधरी
□□	जीएसटी□मुआवजा व्यवस्था की समाप्ति और राज्य के वित्त पर दबाव □मार्च □□□□□□o. □□□□	आर. कविता राव
□□	भारत में शिक्षा पर अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण और व्यय: राज्य स्तरीय विश्लेषण□□□□□ से □□□□ □मार्च □□□□□सं. □□□□	सुकन्या बोस□नुपुर और श्री हरी नायडू ए.
□□	केंद्रीय बजट □□□□□□□□राजवित्तीय-मौद्रिक इंटरफेस	लेखा चक्रवर्ती

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक
	□मार्च □□□□□□o. □□□□	
□□	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और बच्चों के लिए बजट: तेलंगाना□ भारत से साक्ष्य □मार्च □□□□□सं. □□9□	अनिंदिता घोष□दिवी रंगन और लेखा चक्रवर्ती

अनुबंध एनआईपीएफपी आंतरिक संगोष्ठी श्रृंखला

दिनांक	शीर्षक
सितम्बर **ऑनलाइन**	पार्थसारथी शोम और एडुआर्डो बैस्ट्रोची (एलएसई) और जॉन स्नेप (वारविक) द्वारा कराधान इतिहास सिद्धांत कानून और प्रशासन पर पुस्तक चर्चा - सुरांजलि टंडन
अक्तूबर **ऑनलाइन**	एलिस पिर्लोट (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय) द्वारा कार्बन सीमा समायोजन उपाय: एक सीधा बहुउद्देश्यीय जलवायु परिवर्तन उपकरण सुरांजलि टंडन
नवम्बर **ऑनलाइन**	'क्या स्तंभ-दो अंतरराष्ट्रीय कानून की बाध्यताओं का उल्लंघन कर रहा है पीटर हौंग्लर (सेंट गैलेन विश्वविद्यालय) द्वारा - सुरांजलि टंडन
जनवरी **ऑनलाइन**	'चिन्मय एन. कोरगांवकर (आईआरएस) द्वारा भारत में कर मनोबल के निर्धारक – सुरांजलि टंडन

अनुबंध शासी निकाय के सदस्यों की सूची

शासी निकाय ने 18 जून 2020 को हुई अपनी बैठक में निकाय का 4 और वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 05 अप्रैल 2020 से 04 अप्रैल 2024 तक पुनर्गठन किया

22 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार शासी निकाय

डा. ऊर्जित पटेल **अध्यक्ष**
एनआईपीएफपी
18/2 सत्संग विहार मार्ग
विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के पास)
नई दिल्ली- 11 0067

नियम 7(ख)(एक) के अंतर्गत
वित्त मंत्रालय के तीन नामिती

श्री तरुण बजाज **सदस्य**
राजस्व सचिव
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री अजय सेठी आईएएस **सदस्य**
सचिव (आर्थिक कार्य)
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

डा. वी. अनंता नागेश्वरन **सदस्य**
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली 110001

नियम 7(ख)(दो) के अंतर्गत
भारतीय रिजर्व बैंक का एक नामिती

डा. राजीव रंजन **सदस्य**
प्रभारी सलाहकार
मौद्रिक नीति विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
24वीं मंजिल केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग फोर्ट मुंबई-400 001

नियम 7(ख)(तीन) के अंतर्गत
योजना आयोग का एक नामिती

सुश्री अन्ना रोया **सदस्य**
वरिष्ठ सलाहकार
नीति आयोग

नियम 7(ख)(चार) के अंतर्गत
राज्य सरकारों के तीन नामिती

श्री समीर कुमार सिन्हा आईएएस **सदस्य**
प्रमुख सचिव
वित्त विभाग
असम सरकार
असम सचिवालय
दिसपुर गुवाहाटी-781005

श्री संजय एम. कौल आईएएस **सदस्य**
सचिव (वित्त-व्यय)
वित्त विभाग
केरल सरकार
सचिवालय
तिरुवनंतपुरम-695001

श्री मनोज सौनिक आईएएस **सदस्य**
अपर मुख्य सचिव (वित्त)
वित्त विभाग
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय
मुंबई 400 032

नियम 7(ख)(छह) के अंतर्गत
आईसीआईसीआई बैंक का एक नामिती

श्री बी. प्रसन्ना **सदस्य**
प्रमुख - वैश्विक बाजार
आईसीआईसीआई बैंक
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा पूर्व
मुंबई-400 051

नियम 7(ख)(सात) के अंतर्गत
संस्थाओं के दो नामिती

श्री सुमंत सिन्हा **सदस्य**
अध्यक्ष
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

5□सरदार पटेल मार्ग
चाणक्यपुरी
(होटल डिप्लोमैट के पास)
नई दिल्ली-110 021
□

श्री संजीव मेहता □ □ **सदस्य** □
अध्यक्ष
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
फेडरेशन हाउस□तानसेन मार्ग□
नई दिल्ली-110001
□

नियम 7(ख)(सात) के अंतर्गत □
तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री□

डा. माला लालवाणी□ □ □ □ **सदस्य** □
प्रोफ़ेसर
मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी
मुंबई विश्वविद्यालय
विद्यानगरी परिसर□कलिना□सांताक्रूज (पूर्व)
मुंबई 400 098
□

डा. एम. गोविंद राव□ □ □ □ □ **सदस्य**□
□□वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य
निवास: □बी□शोभा एमराल्ड□जक्कुर□
बैंगलोर □□□□□□
□

डा. ज्योत्सना जालान□ □ □ □ □ **सदस्य**□
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर
सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र□कलकत्ता
आर-1□वैष्णबघाटा पटुली टाउनशिप□
कोलकाता - 700 094
□

नियम7(ख)(नौ) के अंतर्गत□
सहयोगी संस्थानों के तीन प्रतिनिधि □

डा. पूनम गुप्ता□ □ □ □ □ **सदस्य**□
महानिदेशक
नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
11□पेरिसिला भवन
आई.पी. एस्टेट□रिंग रोड
नई दिल्ली - 110 002
□

सुश्री यामिनी अय्यर□ □ □ □ **सदस्य** □
अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी
नीति अनुसंधान केंद्र
धर्म मार्ग□चाणक्यपुरी
नई दिल्ली □□□ □□□
□

नियम 7(ख)(दस) के अंतर्गत

शासी निकाय द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो सदस्य

सीए सुश्री किमिशा सोनी **सदस्य**
आईसीएआई की परिषद की सदस्य
मार्फत उप सचिव (परिषद मामले)
इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया
आईसीएआई भवन
आई.पी. मार्ग
नई दिल्ली-

नियम 7(ख)(ग्यारह) के अंतर्गत
संस्थान का एक निदेशक (पदेन)

डा. आर.कविता राव **सदस्य**
निदेशक, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

नियम 7(ख)(बारह) के अंतर्गत
संस्थान का चक्रानुक्रम से एक प्रोफेसर

डा. लेखा चक्रवर्ती **सदस्य**
प्रोफेसर एनआईपीएफपी
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रिती

श्री नितिन गुप्ता **सदस्य**
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री विवेक जोहरी **सदस्य**
अध्यक्ष
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-

अनुबंध□□□समूल्य□प्रकाशनों□की□सूची□

क्रमांक□	समूल्य□प्रकाशन□की□सूची□
□.	**भारत□में□अप्रत्यक्ष□कराधान□की□घटनाएं□**□□□□□□आरजे चेलिया और आरएन लाल □9□□□।□R □□. हिंदी संस्करण □9□□□।□R □□
□.	**भारतीय□संघीय□वित्त□में□रुझान□और□मुद्दे□**□आरजे चेलिया एंड एसोसिएट्स □एलाइड पब्लिशर्स□□9□□□ ।□R □□.
□.	**बिहार□में□बिक्री□कर□प्रणाली□**□आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित □सोमैया प्रकाशन□□9□□□।□R □□.
□.	**राज्य□सरकारों□के□कर□प्रयास□का□मापन□**□□□□□□□□आरजे चेलिया और एन सिन्हा □सोमैया प्रकाशन□ □9□□□।□R □□.
□.	**व्यक्तिगत□आयकर□का□प्रभाव□**अनुपम गुप्ता और पवन के अग्रवाल □9□□□।□R □□.
□.	**निजी□कॉरिट□क्षेत्र□में□संसाधन□जुटाना□**विनय डी. लाल□श्रीनिवास मधुर और केके अत्री □9□□□।□R □□.
□.	**वित्तीय□प्रोत्साहन□और□कॉर्पोरेट□कर□बचत□**विनय डी. लाल □9□□□।□R □□.
□.	**निजी□ट्रस्टों□का□कर□उपचार□**के श्रीनिवासन □9□□□।□R □□□.
9.	**केंद्र□सरकार□का□व्यय□विकास□संरचना□और□प्रभाव□**□□□□□□**से**□□□□□□□□केएन रेड्डी□जेवीएम सरमा और एन सिन्हा □9□□□।□R □□.
□□.	**चुंगी□के□विकल्प□के□रूप□में□प्रवेश□कर□**एमजी राव □9□□□।□R □□ पेपरबैक□।□R □□ हाईकवर।
□□.	**सूचना□प्रणाली□और□तमिलनाडु□में□बिक्री□कर□की□चोरी□**आरजे चेलिया और एमसी पुरोहित □9□□□।□R □□.
□□.	**भारत□में□उत्पाद□शुल्क□की□चोरी□तांबे□प्लास्टिक□और□सूती□वस्त्रों□के□कपड़े□का□अध्ययन□**ए बागची एट अल। □9□□□।□R □□□.
□□.	**भारत□में□काली□अर्थव्यवस्था□के□पहलू□जिसे□ब्लैक□मनी□रिपोर्ट□भी□कहा□जाता□है□**शंकर एन आचार्य एंड एसोसिएट्स□आरजे चेलिया द्वारा योगदान के साथ □9□□□पुनर्मुद्रण संस्करण।□R □□□.
□□.	**मुद्रास्फीति□लेखा□और□कॉरिट□कराधान□**तापस कुमार सेन □9□□□।□R 9□.
□□.	**पश्चिम□बंगाल□में□बिक्री□कर□प्रणाली□**ए बागची और एसके दास □9□□□।□R 9□.
□□.	**ग्रामीण□विकास□भता□आयकर□अधिनियम□**□□□□**की□धारा**□□□□□एक समीक्षा□एचके सोंधी और जेवीएम सरमा □9□□□।□R □□.
□□.	**दिल्ली□में□बिक्री□कर□प्रणाली□**आरजे चेलिया और केएन रेड्डी □9□□□।□R □□□.
□□.	**निवेश□भता□आयकर□अधिनियम□**□□□□**की□धारा**□□**ए**□**एक□अध्ययन□**जेवीएम सरमा और एचके सोंधी □9□9□।□R □□पेपरबैक□।□R □□□हाईकवर।
□9.	**धर्मार्थ□योगदान□के□लिए□कर□प्रोत्साहन□के□अनुकरणीय□प्रभाव□भारतीय□कॉर्पोरेट□क्षेत्र□का□एक□ अध्ययन□**पवन के अग्रवाल □9□9□।□R □□□.

क्रमांक□	समूल्य प्रकाशन की सूची□
□□.	**भारत में डाक सेवाओं का मूल्य निर्धारण** □राघवेंद्र झा□एमएन मूर्ति और सत्य पॉल □99□□I□R □□□.
□□.	**भारत में घरेलू बचत□रुझान और मुद्दे**□□उमा दत्ता रॉय चौधरी और अमरेश बागची □सं.□□99□□I□R □□□.
□□.	**मध्य प्रदेश में बिक्री कराधान**□□एम गोविंदा राव□केएन बालासुब्रमण्यम और वीबी तुलसीधर □विकास पब्लिशिंग हाउस□□99□□I□R □□□.
□□.	**मोडवैट का संचालन**□□एवीएल नारायण□अमरेश बागची और आरसी गुप्ता □विकास पब्लिशिंग हाउस□□99□□I□R □□□.
□□.	**राजकोषीय प्रोत्साहन और संतुलित क्षेत्रीय विकास**□धारा □□ एचएच का मूल्यांकन□□ पवन के. अग्रवाल और एचके सोंधी □विकास पब्लिशिंग हाउस□□99□□I□R □9□.
□□.	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर□एक प्रोफ़ाइल□वॉल्यूम I और□I**□I□R □□□.
□□.	**भारत में एल्युमीनियम उद्योग के लिए प्रभावी प्रोत्साहन मोनोग्राफ श्रृंखला**□□□बी गोल्डर □99□□I□R □□□.
□□.	**भारत में राजकोषीय संघवाद पर अनुसंधान का सर्वेक्षण मोनोग्राफ श्रृंखला**□□□□एम गोविदा राव आर आरजेचेलिया □99□□I□R □□□.
□□.	**राजस्व और व्यय अनुमान□मूल्यांकन और कार्यप्रणाली**□□वीजी राव□अतुल सरमा द्वारा संशोधित और संपादित □विकास पब्लिशिंग हाउस□□99□□I□R □9□.
□9.	**भारत में बिक्री कर प्रणाली□एक प्रोफाइल**□99□□□□□रुपये
□□.	**भारत में राज्य वित्त**□□अमरेश बागची□जेएल बजाज और विलियम ए□बर्ड □सं.□□99□□I□R □□□.
□□.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राजकोषीय नीति**□□महेश सी. पुरोहित□सी. साई कुमार□गोपीनाथ प्रधान और ओ.पी. बोहरा □99□□I□R □□□.
□□.	**विनिर्माण क्षेत्र मोनोग्राफ श्रृंखला□□□में आयात प्रतिस्थापन**□हाशिम एन सलीम □99□□I□R□□□.
□□.	**भारत में बिक्री कर प्रणाली□एक प्रोफाइल**□99□□I□R □□□.
□□.	**नौवां वित्त आयोग□मुद्दे और सिफारिशें□कागजात का चयन**□□□□□□□I□R □9□□
□□.	**चयनित देशों में प्रत्यक्ष कर□एक प्रोफ़ाइल□खंड**□□□□के. कन्नन और ममता शंकर द्वारा संकलित □99□□I□R □□.
□□.	**आर्थिक विकास और जीवन स्तर में अंतर राज्यीय और अंतर राज्यीय बदलाव□मोनोग्राफ सीरीज**□□□□□□□□उमा दत्ता रॉय चौधरी I□R □□□.
□□.	**विकासशील देशों में कर नीति और योजना**□अमरेश बागची और निकोलस स्टर्न □सं.□□99□□□ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस□I□R □□□.
□□.	**भारत में घरेलू व्यापार करों में सुधारः मुद्दे और विकल्प अध्ययन दल**□□□□□□I□R □□□.
□9.	**निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र□धन का सृजन और पुनर्जनन**□उमा दत्ता रॉय चौधरी □विकास पब्लिशिंग हाउस□□99□□I□R □9□.

क्रमांक	समूल्य प्रकाशन की सूची
1.	**प्रदूषण को नियंत्रित करना प्रोत्साहन और विनियम** शेखर मेहता सुदीप्तो मुंडले और यू. शंकर सेज प्रकाशन 1999 ISBN
2.	**भारत नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कर नीति से वित्तीय संसाधन अध्यक्ष पार्थसारथी शोम पर संचालन समूह की कर नीति पर कार्य समूह की रिपोर्ट** सेंटैक्स प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 1999 ISBN
3.	**भारत में मूल्य वर्धित कर एक प्रगति रिपोर्ट** पार्थसारथी शोम सं. सेंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 1999 ISBN
4.	**राजकोषीय नीति सार्वजनिक नीति और शासन** पार्थसारथी शोम सं. सेंटैक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड 1999 ISBN
5.	**भारत में सरकारी सब्सिडी** डीके श्रीवास्तव और तापस के. सेन 1999 ISBN
6.	**पर्यावरण स्थिरता के लिए आर्थिक उपकरण** यू. शंकर और ओम प्रकाश माथुर 1999 ISBN
7.	**भारत शहरी शासन की चुनौती** ओम प्रकाश माथुर सं. 1999 ISBN
8.	**राज्य वित्तीय अध्ययन असम** डीके श्रीवास्तव सौमेन चट्टोपाध्याय और टीएस रंगमन्नार 1999 ISBN
9.	**राज्य वित्तीय अध्ययन पंजाब** इंदिरा राजारमन एच. मुखोपाध्याय और एच.के. अमरनाथ 1999 ISBN
10.	**राज्य वित्तीय अध्ययन केरल** डीके श्रीवास्तव सौमेन चट्टोपाध्याय और प्रप रंजन जेना 1999 ISBN
11.	**दिल्ली राजकोषीय अध्ययन** ओम प्रकाश माथुर और टीएस रंगमन्नार ISBN
12.	**भारत में राजकोषीय संघवाद ग्यारहवें वित्त आयोग के समक्ष समसामयिक चुनौतियां मुद्दे** डीके श्रीवास्तव सं. हर आनंद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ISBN 9
13.	**राज्य वित्तीय अध्ययन हरियाणा** तापस के. सेन आर. कविता राव ISBN
14.	**सार्वजनिक धन का नियंत्रण विकासशील देशों में राजकोषीय तंत्र** ए प्रेमचंद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ISBN
15.	**मूल्यवर्धित कर पर प्राइमर** आरजे चेलिया पवन के अग्रवाल महेश सी. पुरोहित और आर कविता राव हर आनंद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ISBN 9
16.	**भारत में केंद्रीय बजटीय सब्सिडी** डीके श्रीवास्तव और एचके अमरनाथ ISBN .
17.	**राज्य नगरपालिका वित्तीय संबंधों के लिए दृष्टिकोण विकल्प और परिप्रेक्ष्य** ओम प्रकाश माथुर ISBN
18.	**व्यापार और उद्योग एनआईपीएफपी फोर्ड फाउंडेशन फेलो द्वारा निबंध** एके गुहा केएल कृष्णा और अशोक के.लाहिरी सं. विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड ISBN
19.	**भारत के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और विनियम अनुमोदन और विकल्प** एसपी सिंह और

क्रमांक□	**समूल्य प्रकाशन की सूची□**
	अमरेश बागची आरके बजाज द्वारा योगदान के साथ □यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड□ □□□□□I□R □9□.
□9.	**विदेशी उत्पादों की तुलना में घरेलू का भेदभावपूर्ण कर व्यवहार□एक आकलन**□पवन के. अग्रवाल और वी. सेल्वाराजू □□□□□I□R □□□.
□□.	**नियमन का अभ्यास और राजनीति□भारतीय विद्युत में नियामक शासन**□□नवरोज के. दुबाशंद डी. नरसिम्हा राव □□□□□I□R □9□. □स्टॉक में□□□□
□□.	**मानव विकास पर गरीबी की कमी से निपटना□मध्य प्रदेश में वित्तीय रणनीतियाँ□मानव विकास□ मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण**□तापस के सेन□एचके अमरनाथ□मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी □□□□□I□R □□□. □स्टॉक में□□□
□□.	**तमिलनाडु में मानव विकास का वितपोषण□उपलब्धि पर समेकित और निर्माण□मानव विकास□ मोनोग्राफ श्रृंखला का वितपोषण**□तापस के. सेन□एच.के. अमरनाथ□मीता चौधरी और अनीत मुखर्जी □□□□□I□R □□□. □स्टॉक में□□□□
□□.	**भारतीय संघ में स्वास्थ्य व्यय का अंतर राज्यीय समानता**□एम. गोविंदा राव और मीता चौधरी □□□□□ I□R□□□.□स्टॉक में□9□□
□□.	**भारत में व्यय प्रबंधन के□□वर्षों के इनकार के आराम क्षेत्र में फंस गया**□ए प्रेमचंद □□□□□आईएनआर□ □□□. □स्टॉक में□□□□
□□.	**राजकोषीय विकेंद्रीकरण और जेंडर बजटिंग**□एम. गोविंदा राव□लेखा चक्रवर्ती□अमरेश बागची □□□□□ I□R □□□. □स्टॉक में□9□□
□□.	**वित्तीय सुधार□लगातार गरीबी और मानव विकास□उड़ीसा का मामला□मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला□ का वित्तपोषण**□तापस के. सेन□एच.के. अमरनाथ□मीता चौधरी और प्रोतिया कुंडू □□□□□I□R □□□. □स्टॉक में□9□□
□□.	**पश्चिम बंगाल में मानव विकास के सार्वजनिक वित्त पोषण पर वित्तीय बाधाओं से निपटना□मानव विकास□ मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण**□□तापस के. सेन□एच.के. अमरनाथ□मीता चौधरी और प्रोतिवा कुडू □□□9□I□R □□□. □स्टॉक में□□□□□
□□.	**भारत के निम्न कार्बन आर्थिक विकास की संभावनाएं और नीतियां**□रामप्रसाद सेनगुप्ता □□□□□□□□ रुपये □स्टॉक में□□□□□
□9.	**भारत में निम्न कार्बन और उच्च विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत साधन**□यू. शंकर □□□□□□□□ रुपये। □स्टॉक में□□□□□
□□.	**राजस्थान□आर्थिक और मानव विकास को समवर्ती रूप से बढ़ावा देना□मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला□ का वित्तपोषण**□तापस के□सेन□एच.के. अमरनाथ□मीता चौधरी और सुरजीत दास □□□□□I□R □□□. □स्टॉक में□□□□□
□□.	**भारत□सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही□सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट**□ प्रताप रंजन जेना □□□□□I□R □□□. □स्टॉक में□□9□

क्रमांक	समूल्य प्रकाशन की सूची
.	**हिमाचल प्रदेश में सतत मानव विकास के लिए संसाधन मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण** तपस के. सेन एच.के अमरनाथ मीता चौधरी और सुरजीत दास I R . स्टॉक में
.	**एक युवा राज्य का परिपक्वता में तेजी से संक्रमण छत्तीसगढ़ में मानव विकास के लिए संसाधन मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण** तपस के. सेन एच.के. अमरनाथ मीता चौधरी और सुरजीत दास I R . स्टॉक में
.	**केरल में मानव विकास का वित्तपोषण मुद्दे और चुनौतियाँ मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण** पिनाकी चक्रवर्ती लेखा चक्रवर्ती एचके अमरनाथ और सोना मित्रा I RI . स्टॉक में
.	**अपने आर्थिक विकास के साथ पूरे महाराष्ट्र में मानव विकास का मिलान मानव विकास मोनोग्राफ श्रृंखला का वित्तपोषण** तापस के. सेन अमरनाथ एच.के. मीता चौधरी और सुरजीत दास रुपये। स्टॉक में
.	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अव्ययित शेष और निधि प्रवाह तंत्र** एनआर भानुमूर्ति एचके अमरनाथ अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता I R . स्टॉक में 9
.	**मध्य प्रदेश राज्य एमडीजी रिपोर्ट** एन.आर. भानुमूर्ति एच.के. अमरनाथ सुकन्या बोस परमा चक्रवर्ती और अक्राज्योति जाना । स्टॉक में 9
.	**मध्य प्रदेश में मानव विकास परिणामों में विचलन राजकोषीय नीति और शासन की भूमिका** एनआर भानुमूर्ति एचके अमरनाथ मनीष प्रसाद शाइनी चक्रवर्ती और ऋचा जैन । स्टॉक में
9.	**राज्य के वित में उभरते मुद्दे चौदहवें वित्त आयोग के बादः राज्य बजट का विश्लेषण** मनीष गुप्ता लेखा चक्रवर्ती और पिनाकी चक्रवर्ती । स्टॉक में
.	**राज्य के बजट का विश्लेषण उभरते मुद्दे विद्युत क्षेत्र के ऋण का प्रभाव राज्य के वित्त पर उदय** पिनाकी चक्रवर्ती मनीष गुप्ता लेखा चक्रवर्ती अमनदीप कौर I R
.	**राज्य के बजट का विश्लेषण प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ बजट विश्वसनीयता और वित्तीय पूर्वानुमान त्रुटियाँ** मनीष गुप्ता लेखा चक्रवर्ती अमनदीप कौर

**संबंधित प्रकाशकों के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।*

** एनआईपीएफपी के साथ सह-प्रकाशित/उपलब्ध।*

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के खिलाफ प्रकाशन भेजे गए। डाक खर्च INR 80 प्रति प्रति।

टिप्पणी: प्रकाशन क्रमांक 1 से 69 तक, बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इन्हें एनआईपीएफपी लाइब्रेरी से एक्सेस किया जा सकता है

अनुबंध□□□एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री□

□पुस्तकें□जर्नल□मोनोग्राफ और अन्य लोकप्रिय लेखन-कार्य□

चक्रवर्ती□पिनाकी □

- पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय: □□□□ की जनसंख्या और क्षैतिज असमानता का उपयोग (मनीष गुप्ता के साथ) द रूटलेज हैंडबुक ऑफ पोस्ट-रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी, रूटलेज इंडिया, पीपी *239-258*, नवंबर *2021* में।
- कोविड-*19* संदर्भ और पंद्रहवां वित्त आयोग: राजकोषीय आवश्यकता और व्यापक आर्थिक स्थिरता को संतुलित करना, एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अगस्त □□□□.
- कोविड-*19* संदर्भ और पंद्रहवां वित्त आयोग: राजकोषीय आवश्यकता और व्यापक आर्थिक स्थिरता को संतुलित करना, आर्थिक और राजनीतिक वीकली, खंड □□□□□□□□□□9, अगस्त 2021.
- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक व्यय की निजी-सार्वजनिक संरचना: भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल और अनुभव (स्टेनली एल. विनर, जे. स्टीफन फेरिस और भारती भूषण दास के साथ), अंतर्राष्ट्रीय कर और सार्वजनिक वित्त, स्प्रिंगर; अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त संस्थान, खंड □□□□□□□□□□□□□□□□.

राव, आर. कविता

- जीएसटी, मुआवजा व्यवस्था की समाप्ति और राज्य के वित्त पर दबाव, एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. *376*, मार्च *2022*.

पटनायक, आईएलए □

- द राइज़ ऑफ़ द बीजेपी: द मेकिंग ऑफ़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी (भूपेंद्र यादव के साथ)□पेंगुइन विकिंग□जनवरी □□□□.
- भारत में स्व-रिपोर्ट स्वास्थ्य वितरण: आय और भूगोल की भूमिका (रेणुका साने□अजय शाह और एस.वी. सुब्रमण्यम के साथ)□लीप ब्लॉग□□□ सितंबर □□□□.
- भारत की विनिमय दर व्यवस्था का विश्लेषण (राजेश्वरी सेनगुप्ता के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□सितंबर □□□□.
- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में आजीविका की रक्षा करना भारत का अगला मोर्चा है (कमल किशोर के साथ)□न्यूज़लेटर - दक्षिण एशिया की देखभाल: दक्षिण एशिया परियोजना के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन□खंड । □दिसंबर □□□□.
- "ये □कारक आकार देंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड की दूसरी लहर के झटके से उबरती है" (रेणुका साने के साथ)□द प्रिंट□□□ मई □□□□.

चक्रवर्ती□लेखा □

- वित्तीय-मौद्रिक इंटरफेस और ग्रीन बांड□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□खंड 57(13):47-51□मार्च 2022.

- बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और बजट: तेलंगाना□भारत से साक्ष्य (अनिंदिता घोष और दिव्य रंगन के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 379□मार्च 2022.
- केंद्रीय बजट 2022-23: राजकोषीय-मौद्रिक इंटरफेस□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 378□मार्च 2022.
- कोविड-19 और अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था: भारत में राजकोषीय नीति और समय आवंटन पर साक्ष्य□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 372□फरवरी 2022.
- कोविड -19 और वित्तीय-मौद्रिक नीति समन्वय (हरिकृष्णन एस के साथ)□लेवी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□कार्यकारी पत्र सं. 1002□फरवरी 2022.
- एशिया-प्रशांत में सतत विकास के लिए राजकोषीय नीति: भारत में जेंडर बजटिंग (हरिकृष्णन एस के साथ)□ पालग्रेव मैकमिलन□ फरवरी 2022. □ttp□□□□□□.□arn□□andno□l□.com□□□i□cal□polic□□or□ □u□taina□l□□d□□□lopm□nt□in□a□ia□paci□ic□l□□□a□□c□a□ra□ort□□□□□□□□□□□□
- कोविड-□9 और बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त: भारत के ओडिशा राज्य का मामला अध्ययन (अमनदीप कौर के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□जनवरी □□□□.
- कोविड-□9 और राजकोषीय-मौद्रिक नीति समन्वय - भारत से अनुभवजन्य साक्ष्य (हारिकृष्णन एस. के साथ)□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□खंड □□□□□□□□□□□□□□ जनवरी □□□□.
- वैश्विक दक्षिण में वित्तीय संघवाद का विश्लेषण: दक्षिण अफ्रीका□केन्या□इथियोपिया और नेपाल (गुरलीन कौर□दिव्य रंगन□अमनदीप कौर और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□ दिसंबर □□□□.
- कोविड-□9 और जेंडर बजटिंग: भारत में केंद्रीय बजट में □जेंडर लेंस□लागू करना□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□दिसंबर □□□□.
- कोविड-□9 और बच्चों के लिए सार्वजनिक निवेश: भारतीय राज्य कर्नाटक का मामला (जेनेट फरीदा जैकब के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अक्टूबर □□□□.
- कोविड -□9 आर्थिक प्रोत्साहन और बिजली वितरण कंपनियों का राज्य-स्तरीय प्रदर्शन (अमनदीप कौर और दिव्य रंगन के साथ)□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□खंड □□ □□□□□□□□□□□□ अक्टूबर □□□□.
- वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाना□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अगस्त □□□□.
- भारत में पारिस्थितिक वित्तीय हस्तांतरण और राज्य-स्तरीय बजटीय व्यय (अमनदीप कौर□रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन के साथ)□कार्यकारी पत्र सं. 99□□लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□जुलाई □□□□.
- कोविड-□9 और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज: एशिया-प्रशांत क्षेत्र से साक्ष्य (अमनदीप कौर□दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)□एनआईपीएफपी प्रकाशन□अप्रैल □□□□.
- कोविड-□9 और मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता (इमैनुएल थॉमस के साथ) कपिला□ उमा (एड)□इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया (ईडीआई) सीरीज□□□□□□एकेडमिक फाउंडेशन□वी □□□□□□□□□□ में।
- कपिला में वित्तीय-मौद्रिक इंटरफेस□उमा (संपा.)□भारत में आर्थिक विकास (ईडीआई) श्रृंखला□□□□□□अकादमिक फाउंडेशन□खंड ।□□□□.
- वित्त आयोगों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को मुख्यधारा में लाना□आर्थिक और

राजनीतिक साप्ताहिक□खंड □□□□□□□□□□□□□□□□ अगस्त □□□□.

- कोविड-□9 से निपटने के लिए मौद्रिक-राजकोषीय नीति प्रतिक्रिया□अर्थ बीकशन□□9□□□□□□□□.

लेवी ब्लॉग

- एक समायोजनात्मक राजकोषीय रुख भारत के लिए महत्वपूर्ण है (हरिकृष्णन एस के साथ)□लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□न्यूयॉर्क का गुणक प्रभाव ब्लॉग।
- क्या जलवायु परिवर्तन एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति चुनौती है□ बार्ड कॉलेज□लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□न्यूयॉर्क का गुणक प्रभाव ब्लॉग□□□ नवंबर □□□□.
- लेख चक्रवर्ती द्वारा जेंडर बजटिंग - पोडकास्ट माइकल स्टीफेंस द्वारा पोस्ट किया गया□लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□न्यूयॉर्क का गुणक प्रभाव ब्लॉग□□□ जून □□□□.

पॉपुलर मीडिया (ओपी-डी)

- "आरबीआई का कठोर रुख"□द फाइनेंशियल एक्सप्रेस□□□ अप्रैल □□□□.
- "क्या आरबीआई मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है□" द प्रिंट और द हिंदू पॉडकास्ट में□□□ अप्रैल □□□□.
- "उच्च राजकोषीय घाटा एक विकास मंत्र हो सकता है"□द न्यू इंडियन एक्सप्रेस□□ फरवरी □□□□.
- "व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटना"□द हिंदू□□□ जनवरी □□□□.
- "हेल्पिंग इंडियन इकॉनमी डाउन द रोड टू रिकवरी" (हरिकृष्णन एस के साथ)□द इंडियन एक्सप्रेस□□□ जनवरी□□□□□.
- "हरित मौद्रिक नीति"□द फाइनेंशियल एक्सप्रेस□□□ अक्टूबर □□□□.
- "विकास सर्वप्रथम"□द इंडियन एक्सप्रेस□□□ अक्टूबर □□□□.
- "भारतीय राज्यों को अपनी योजना में जेंडर बजटिंग को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है□" द वायर□□□ अगस्त □□□□.
- "महामारी राजकोषीय घाटे के बारे में चिंता करने का समय नहीं है" (अभिषेक आनंद के साथ)□द इंडियन एक्सप्रेस□□□ मई □□□□.

जेना□प्रताप रंजन □

- उप-राष्ट्रीय बजट विश्वसनीयता: भारत में संस्थागत परिप्रेक्ष्य और सुधार एजेंडा (अभिषेक सिंह के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□जुलाई □□□□.
- नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स: ड्रैग फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर (डॉली गौर और दीप्ति रंजन महापात्र के साथ)□इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च□खंड □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□. □

चौधरी□मीता□

- भारत में उप-राज्य स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च की प्रगति: तमिलनाडु और बिहार में एक अनुभवजन्य जांच (प्रीतम दत्ता और जय देव दुबे के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□.

- राज्य के वित्त पर कोविड-□9 महामारी का □प्रतिकूल प्रभाव□□व्यय पर उभरते साक्ष्य (प्रीतम दत्ता के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□9□जनवरी □□□□.

मुखर्जी□सच्चिदानंद □

- भारत में जीएसटी दरों के पुनर्गठन की राजस्व विवक्षाएं : एक विश्लेषण□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□नवंबर □□□□.
- राजस्व की कमी और जीएसटी मुआवजा: एक आकलन□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अक्टूबर □□□□.
- जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में उभरते मुद्दे: एक आकलन (दिवा मेहता के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अगस्त □□□□.
- कोविड□□9 महामारी के समय में भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (शिवानी बडोला के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मई □□□□.
- भारत में मानव विकास का सार्वजनिक वित्तपोषण: एक समीक्षा (शिवानी बडोला के साथ)□□भारतीय मानव विकास जर्नल□खंड □□□□□□□□□□□□. □ttp□□□doi.org□□□. □□□□□□9□□□□□□□□□□□□□□□□□
- भारत में अनिगमित उद्यमों के बीच आईसीटी अंगीकरण और वैट पंजीकरण: इकाई स्तर के डेटा का विश्लेषण□□ विकास और परिवर्तन की समीक्षा□ खंड□ □□□□□□□□□□□□□□. □ttp□□□doi.org□□□. □□□□□□9□□□□□□□□□□□□□□□□□
- भारत: एक संघीय राज्य में वैट लागू करने की चुनौतियाँ□□रॉबर्ट एफ वैन ब्रेडरोड (सं.) में□□वैट के गुण और भ्रम: □□वर्षों के बाद एक मूल्यांकन□□अध्याय □□□पीपी □□□□□□□□□क्लूवर लॉ इंटरनेशनल□यूके।□
- भारत के लिए लो-कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी: एक्सप्लोरिंग एशिया-पैसिफिक एनर्जी कोऑपरेशन□□संजय के भारद्वाज (सं.)□□द चाइनीज शैडो ऑन इंडियाज ईस्टवर्ड एंगेजमेंट: द एनर्जी सिक्योरिटी डाइमेंशन□□चैप्टर □□□ पीपी 99□□□□□□रूटलेज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भारत और चीन श्रृंखला पर□□रूटलेज इंडिया□□नई दिल्ली□□ □□□□. □

अमरनाथ□एच.के. □

- भारत में बाल विकास सूचकांक - जिला स्तर पर प्रदर्शन (रितु माथुर और नम्रता जेटली के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□फरवरी □□□□.
- भारत में बाल विकास सूचकांक का आकलन - एक पद्धति (रितु माथुर और नम्रता जेटली के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□फरवरी □□□□.

साने□रेणुका □

- भारत में विनिवेश का इतिहास: □99□□□□□□ □सुदीप्तो बनर्जी□सृष्टि शर्मा और कार्तिक सुरेश के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□.
- क्या भारतीय वित्तीय फर्मों के पास एक मजबूत शिकायत निवारण ढांचा है□ □विमल बालासुब्रमण्यम□मिथिला सारा और कार्तिक सुरेश के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□जनवरी □□□□.
- क्या वित्तीय और समष्टि नीति सोने में घरेलू निवेश की व्याख्या करती है□ □मनीष कुमार सिंह के साथ)□द्वारा रिसर्च कार्यकारी पत्र सीरीज डब्ल्यूपी□□□□□□□□□जनवरी □□□□.

- वित्तीय शिक्षा के माध्यम से उत्पाद-विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करना (ओल्गा बालाकिना□विमल बालासुब्रमण्यम और अदिति डिमरी के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अगस्त □□□□.
- भारतीय परिवारों की खपत मात्रा : सीपीआई□सीईएस और सीपीएचएस के अनुमानों की तुलना (अनन्या गोयल और राधिका पांडे के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अगस्त □□□□.

दि लीप ब्लॉग

- क्या वित्तीय और समष्टि नीति स्वर्ण में घरेलू निवेश की व्याख्या करती है□ □मनीष कुमार सिंह के साथ)□□□ जनवरी□ □□□□.□ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□□do□□□inancial□and□macro□polic□□ □□plain.□tml
- भारत में स्व-सहायता किए गए स्वास्थ्य का वितरण: आय और भूगोल की भूमिका (इला पटनायक□अजय शाह और एस.वी. सुब्रमण्यम के साथ)□ □□ सितंबर □□□□.□ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□9□di□tri□ution□o□□□l□r□port□d□□alt□in.□tml
- सेबी के व्हाट्सएप ऑर्डर का विश्लेषण: नियमन और निर्णय पर कुछ प्रेक्षण□ □□ अगस्त □□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□an□anal□□i□□o□□□□i□□at□app□ord□r□.□tml
- उन्नत अर्थव्यवस्था के इतिहास में कौन सा वर्ष इंडिया टुडे जैसा है□ □अनन्या गोयल और अजय शाह के साथ)□ □□ अगस्त□ □□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□□□at□□ar□in□□i□tor□o□□ ad□anc□d.□tml
- सेबी के व्हाट्सएप आदेशों का विश्लेषण: विनियमन और निर्णय पर कुछ प्रेक्षण (रजत अस्थाना और विवेक के साथ)□ □□ मई □□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□an□anal□□i□□o□□□□i□ □□at□app□ord□r□.□tml□
- क्या उपभोक्ताओं को अपने कार्ड डेटा को इंटरनेट पर संग्रहीत करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए□ □अजय शाह और भार्गवी जावेरी के साथ)□□□ मई □□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□□ould□ con□um□r□□□□r□□trict□d□rom.□tml
- भारत में टीकाकरण: जब □□ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे तो मांग में परिवर्तन कैसे होगा□ □□ अप्रैल□□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□accination□in□india□o□□ill□ d□mand.□tml
- भारत के केवाईसी ढांचे का विश्लेषण: क्या हम चीजें बेहतर कर सकते हैं□ □□ अप्रैल □□□□.□ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□anal□□ing□india□□□c□ram□□or□□can□□□.□tml
- भारत में विनिवेश का इतिहास (सुदीप्तो बनर्जी□सृष्टि शर्मा और कार्तिक सुरेश के साथ)□□□ मार्च □□□□. □ttp□□□□log.t□□l□ap□ournal.org□□□□□□□□□i□tor□□o□di□in□□□tm□nt□in□india.□tml
- "राजस्थान सरकार का पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का निर्णय एक वित्तीय आपदा क्यों है" (राजीव महर्षि के साथ)□ द इंडियन एक्सप्रेस□ □ मार्च □□□□. □ttp□□□indian□□pr□□□.com□articl□□opinion□column□□□□□ra□a□t□an□go□t□d□ci□ion□r□turn□old□ p□n□ion□□c□□m□□i□cal□di□a□t□r□□□9□□□□□
- "दिवाला और शोधन-अक्षमता संहिता महामारी के बाद का आकलन" (एडम फेबेलमैन के साथ)□ब्लूमबर्ग क्विंट□ □□ जुलाई □□□□. □ttp□□□□□□.□loom□□rg□uint.com□in□ol□□nc□a□po□t□pand□mic□ a□□□□□m□nt□o□t□□□in□ol□□nc□and□□an□ruptc□□cod□
- "ये □कारक आकार देंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड की दूसरी लहर के आघात से उबरती है" (इला पटनायक के साथ)□द प्रिंट□□□ मई □□□□. □ttp□□□t□□print.in□ilanomic□t□□□□□□□actor□□□ill□□ap□□ □o□□indian□□conom□r□□ound□□□rom□□□oc□□o□□co□id□□□cond□□a□□□□□□□□□

गुप्ता□मनीष□

- वन कवर के लिए वित्तीय हस्तांतरण: एक संघीय सेटिंग में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय उद्देश्यों को संरेखित करना (इंदिरा राजारमन के साथ)□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□खंड □□□□□□□□□□□□□□.
- अंतरसरकारी वित्तीय प्रबंधन में वित्त आयोगों की बढ़ती भूमिका (अतुल सरमा के साथ)□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□खंड L□II (□□□□□□□□□□□□□.
- पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय : □□□□की जनसंख्या और क्षैतिज असमानता का उपयोग (पिनाकी चक्रवर्ती के साथ) पोस्ट-रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी की रूटलेज हैंडबुक□रूटलेज इंडिया□पीपी □□9□□□□□नवंबर □□□□.

भट्टाचार्य□रुद्राणी□

- कारक-संवर्धित समय-भिन्न गुणांक प्रतिगमन मॉडल□सुदीप्तो मुंडले के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□दिसंबर □□□□के आधार पर □□□□की जीडीपी वृद्धि और □□□□□□के लिए पूर्वानुमान।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को नाउकास्टिंग: एक कारक-संवर्धित समय-भिन्न गुणांक प्रतिगमन मॉडल (एफए-टीवीसीआरएम) (बोर्नाली भंडारी और सुदीप्तो मुंडले के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□अक्टूबर □□□□.
- भारत में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को एकीकृत करने में ई-नाम कितना प्रभावी है□ प्याज बाजार से साक्ष्य (सबरनी चौधरी के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□अप्रैल □□□□.
- उमा कपिला (संपा.)□इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया वॉल्यूम में कारक-संवर्धित समय-भिन्न गुणांक प्रतिगमन मॉडल के आधार पर □□□□की जीडीपी वृद्धि और □□□□□□के लिए पूर्वानुमान (सुदीप्तो मुंडले के साथ)□□□□□9□□□□□□□□.

आनंद□मुकेश कुमार □

- “भारत की सामाजिक सुरक्षा समस्या को मरम्मत से अधिक की आवश्यकता है" (राहुल चक्रवर्ती के साथ)□द फाइनेंशियल एक्सप्रेस□□□ मार्च □□□□.

बोस□सुकन्या □

- भारत में शिक्षा पर अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण और व्यय: राज्य स्तरीय विश्लेषण□□□□□से □□□□ □नूपुर और श्री हरि नायडू ए के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□मार्च □□□□.
- विश्व बैंक को प्रस्तुत रिपोर्ट□भारत में शिक्षा के लिए अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण□□माइमोग्राफ)□नवंबर □□□□.
- □एन इंक्वायरी इन द एग्जिट एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड□□माइमोग्राफ) नामक परियोजना पर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट। सितंबर □□□□.
- दिल्ली में स्कूलों के लिए विनियमन और अनौपचारिक बाजार (प्रियंता घोष□अरविंद सरदाना और मनोहर बोड़ा के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□अगस्त □□□□.
- समावेश और संसाधन प्रश्न (प्रियंता घोष□अरविंद सरदाना के साथ)□युक्ति शर्मा और हनीत गांधी (संपा.) स्कूलों में समावेश: परिप्रेक्ष्य और संभावनाएं□शिप्रा प्रकाशन□पीपी.□□□□□□□□□□□□.

- भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र: हाइमन मिन्स्की के लेंस का उपयोग करते हुए कुछ प्रतिबिंब□व्यासदेब दासगुप्ता□अर्चिता घोष और बिशाखा घोष (संपा.)□भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में नवउदारवाद□रूटलेज□ ऑक्सफोर्ड और न्यूयॉर्क□पीपी □□□□□ में□□□□□.
- हाशिए पर पड़े बच्चों के दृष्टिकोण से महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा का सार्वजनिक वित्त-पोषण (माइमोग्राफ)। मार्च □□□□.

टंडन□सुरांजलि □

- कर डिजिटल अर्थव्यवस्था के समाधान की तलाश में□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□अक्टूबर □□□□.
- अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर लगाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन (स्मारक स्वैन के साथ)□अंतर्राष्ट्रीय कर के लिए बुलेटिन□आईबीएफडी□खंड □□□नंबर □. जुलाई □□□□.
- स्तंभ □ और □ को प्रभावी बनाना□टैक्स नोट्स इंटरनेशनल□□ नवंबर □□□□.

नायक□दिनेश कुमार □

- भारतीय उप-राष्ट्रिको में आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: दूसरी पीढ़ी की पैनल सह-एकीकरण तकनीकें (भावेश हजारिका के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□□
- वित्तीय भ्रम और वैगनर का कानून: भारतीय उपराष्ट्रीय वित्त से साक्ष्य (भावेश हजारिका के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□.
- एक्ट ईस्ट (पूर्वोदय) नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था का उत्थान□पूर्वोदय: अवसरों का उदय□। □□□□नवंबर-दिसंबर □□□□.

श्री हरि नायडू ए. □

- भारत में शिक्षा पर अंतरसरकारी वित्तीय हस्तांतरण और व्यय: राज्य स्तरीय विश्लेषण□2005 से 2020 (सुकन्या बोस और नूपुर□ए के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. 377□मार्च 2022.

हजारिका□भावेश □

- भारतीय उप-नागरिकों पर आय और सरकारी व्यय के बीच संबंध: दूसरी पीढ़ी पैनल सह-एकीकरण तकनीक (दिनेश कुमार नायक के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□.
- राजकोषीय भ्रम और वैगनर का कानून: भारतीय उपराष्ट्रीय वित्त से साक्ष्य (दिनेश कुमार नायक के साथ)□ एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□मार्च □□□□.

कौर□अमनदीप□

- बच्चों के लिए कोविड-□9 और सार्वजनिक वित्त: भारत के ओडिशा राज्य का मामला अध्ययन (लेखा चक्रवर्ती के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□जनवरी □□□□.
- वैश्विक दक्षिण में वित्तीय संघवाद का विश्लेषण: दक्षिण अफ्रीका□केन्या□इथियोपिया और नेपाल (लेखा चक्रवर्ती□गुरलीन कौर□दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)□एनआईपीएफपी कार्यकारी पत्र सं. □□□□दिसंबर □□□□.

- कोविड-□9 आर्थिक प्रोत्साहन और बिजली, वितरण कंपनियों का राज्य-स्तरीय प्रदर्शन (लेखा चक्रवर्ती और दिव्य रंगन के साथ)□आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक□kखंड | □□□□□□□□□□□□ अक्टूबर □□□□.
- भारत में पारिस्थितिक वित्तीय हस्तांतरण और राज्य-स्तरीय बजटीय व्यय (लेखा चक्रवर्ती□रंजन कुमार मोहंती और दिव्य रंगन के साथ)□कार्यकारी पत्र सं. 99□□लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज□ जुलाई □□□□.
- कोविड-□9 और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज: एशिया-प्रशांत क्षेत्र से साक्ष्य (लेखा चक्रवर्ती□दिव्य रंगन और जेनेट फरीदा जैकब के साथ)□एनआईपीएफपी प्रकाशन□अप्रैल □□□□.

अनुबंध □□□□□.□□.□□□□ की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची □

संकाय □

□.	डा. पिनाकी चक्रवर्ती	निदेशक □□.□□.□□□□ को त्यागपत्र दिया□
□.	डा. (सुश्री) आर. कविता राव	प्रोफेसर
□.	डा. (सुश्री) इला पटनायक	प्रोफेसर □□.□□.□□□□ को त्यागपत्र दिया□
□.	डा. एन.आर. भानुमूर्ति	प्रोफेसर □□.□□.□□□□ से प्रतिनियुक्ति पर□
□.	डा. सव्यसाची कार	प्रोफेसर □आरबीआई चेयर□□□.□□.□□□□ को त्यागपत्र दिया□
□.	डा. (सुश्री) लेखा एस. चक्रवर्ती	प्रोफेसर
□.	डा. प्रताप रंजन जेना	एसोसिएट प्रोफेसर
□.	डा. (सुश्री) मीता चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर
9.	डा. सच्चिदानंद मुखर्जी	एसोसिएट प्रोफेसर
□□.	डा. एच.के. अमरनाथ	एसोसिएट प्रोफेसर
□□.	डा.रेणुका साने	एसोसिएट प्रोफेसर
□□.	डा. मनीष गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर □9.□□.□□□□ को कार्यभार ग्रहण किया□
□□.	डा. रुद्राणी भट्टाचार्य	एसोसिएट प्रोफेसर □9.□□.□□□□ को कार्यभार ग्रहण किया□
□□.	डा. अमय सप्रे	एसोसिएट प्रोफेसर □9.□□.□□□□ को कार्यभार ग्रहण किया□
□□.	डा. मुकेश आनंद	सहायक प्रोफेसर
□□.	डा. सुकन्या बोस	सहायक प्रोफेसर
□□.	डा. सताद्रू सिकदर	सहायक प्रोफेसर □□.□□.□□□□ को मृत्यु हो गई□
□□.	डा. सुरांजलि टंडन	सहायक प्रोफेसर
□9.	डा. श्रुति त्रिपाठी	अर्थशास्त्री □□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त□
□□.	डा. दिनेश कुमार नायक	अर्थशास्त्री
□□.	डा. ए. श्री हरी नायडू	अर्थशास्त्री
□□.	डा. भावेश हजारिका	अर्थशास्त्री
□□.	सुश्री अमनदीप कौर	अर्थशास्त्री

प्रशासनिक स्टाफ □

□.	सुश्री अलका मट्टा□ □	सचिव □
□.	श्री पंकज कुमार सिन्हा □ □	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (□□.□9.□□□□ को कार्यभार ग्रहण किया) □
□.	श्री विक्रम सिंह चौहान	निदेशक के निजी सचिव □□
□.	श्री प्रवीण कुमार □□ □	निजी सचिव □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□.	श्री परविंदर कपूर □	निजी सचिव □□.□□.□□□□ को सेवानिवृत□□
□.	श्री बी.एस. रावत □ □	लेखा अधिकारी □
□.	सुश्री प्रोमिला राजवंशी □ □	आशुलिपिक ग्रेड.I
□.	सुश्री कविता इस्सर □ □	आशुलिपिक ग्रेड.I□
9.	श्री अनुरोध शर्मा □ □	आशुलिपिक ग्रेड.I □

श्री दर्शन सिंह पंवार		आशुलिपिक ग्रेड.II से प्रतिनियुक्ति पर
सुश्री अमिता मनहास		आशुलिपिक ग्रेड.II
श्री कपिल कुमार अहूजा		आशुलिपिक ग्रेड.II
सुश्री उषा माथुर		आशुलिपिक ग्रेड.II
श्री वसीम अहमद		स्टेनो-टाइपिस्ट से प्रतिनियुक्ति पर
सुश्री रुचि आनंद		सहायक
सुश्री दीपिका राय		सहायक
श्री शुभम कुमार वर्मा		लिपिक (लेखा)
सुश्री मोनिका माथुर		स्वागतकर्ता-सह-टेलीफोन ओपरेटर
9. श्री राजू		चालक को सेवानिवृत्त
श्री परशुराम तिवारी		चालक
श्री मोहन सिंह बिष्ट		फोटोकॉपी प्रचालक
श्री के.एन. मिश्रा		होस्टल अटेंडेंट
श्री किशन सिंह		होस्टल अटेंडेंट
श्री शिव प्रताप		माली
श्री रमेश कुमार		माली
श्री हरीश चंद		मैसेंजर
श्री अजय कुमार		मैसेंजर
श्री मुकेश		मैसेंजर
9. श्री राजेन्द्र कुमार		मैसेंजर से प्रतिनियुक्ति पर
श्री बिशम्भर पाण्डेय		सुरक्षाकर्मी
श्री सुरेन्द्र सिंह यादव		सुरक्षाकर्मी

कम्प्युटर यूनिट

श्री एन.के. सिंह		ईडीपी मैनेजर को सेवानिवृत्त
श्री रोबी थॉमस		अधीक्षक

पुस्तकालय स्टाफ

सुश्री सोनम सिंह	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
सुश्री सारिका गौर	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर)
श्री पी.सी.उपाध्याय	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी 9. को सेवानिवृत्त)
सुश्री मंजू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
सुश्री आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
श्रीराजन ढाका	वरिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट
श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय अटेंडेंट

श्री पूरन सिंह	मैसेंजर

शैक्षणिक स्टाफ (संविदात्मक)

श्री ए एन झा	सीनियर फेलो
डॉ. राधिका पांडे	सीनियर फेलो
श्री रत्नेश	सीनियर फेलो
श्री प्रमोद सिन्हा	फेलो-II
सुश्री रचना शर्मा	फेलो-II
श्री जय देव दुबे	फेलो-II
श्री देवेंद्र दामले	फेलो-II
श्री प्रीतम दत्ता	फेलो-II
श्री आशिम कपूर	रिसर्च फेलो
श्री राहुल चक्रवर्ती	रिसर्च फेलो
सुश्री सृष्टि शर्मा	रिसर्च फेलो
श्री रोहित दत्ता	रिसर्च फेलो
सुश्री सबरनी चौधरी	रिसर्च फेलो
सुश्री शिवानी बडोला	रिसर्च फेलो
सुश्री स्मृति मेहरा	रिसर्च फेलो
सुश्री अनन्या गोयल	रिसर्च फेलो
सुश्री स्मृति शर्मा	रिसर्च फेलो
सुश्री रागिनी	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री गरिमा नैन	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
श्री डेनी जॉर्ज	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री स्मृति बहल	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री सोनल जैन	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री ऐश्वर्या गवली	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री अर्चिता श्रीधर	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री सिमरन कौर	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री सोनल अग्रवाल	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री प्रियांशी गर्ग	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री मार्गी पंड्या	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
सुश्री देवयानी गुप्ता	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
श्री उत्सव सक्सेना	रिसर्च फेलो (को कार्यभार ग्रहण किया)
31. सुश्री रितिका सिंह	रिसर्च फेलो (20.12.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
32. सुश्री कृति वट्टल	रिसर्च फेलो (05.01.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
33. श्री वी. राम्या राजश्री कुमार	रिसर्च फेलो (07.01.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)
34. सुश्री अनिंदिता गुप्ता	रिसर्च फेलो (18.01.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)

35. सुश्री चेतना चौधरी	रिसर्च फेलो (01.02.022 को कार्यभार ग्रहण किया)□
36. सुश्री नैन्सी गुप्ता □	रिसर्च फेलो (25.02.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)□
37. श्री अशोक भाकर	रिसर्च फेलो (08.03.2022 को कार्यभार ग्रहण किया)□
38. श्री आदित्य रेड्डी	रिसर्च फेलो (07.06.2021 को कार्यमुक्त)□
39. श्री मनीष कुमार प्रसाद □	रिसर्च फेलो (21.06.2021 को कार्यमुक्त)□
40. सुश्री मधुर मेहता	रिसर्च फेलो (30.06.2021 को कार्यमुक्त)□
41. श्री ऋषभ बेली	रिसर्च फेलो (30.06.2021 को कार्यमुक्त)□
42. श्री एम. वासुकी नंदन	रिसर्च फेलो (30.06.2021 को कार्यमुक्त)□
43. डॉ.द्वीपोबोटी ब्रह्म	फेलो-□□□30.06.2021 को कार्यमुक्त)□
44. सुश्री कनिका गुप्ता	रिसर्च फेलो (30.07.2021 को कार्यमुक्त)□
45. सुश्री अमृता पिल्लई	रिसर्च फेलो (31.07.2021 को कार्यमुक्त)□
46. श्री कार्तिक सुरेश	रिसर्च फेलो (31.08.2021 को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री संप्रीत कौर □	रिसर्च फेलो (□□.□9.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री राशि मित्तल	रिसर्च फेलो (□□.□9.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□9.सुश्री नूपुर	रिसर्च फेलो (□□.□9.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री सुनेत्रा घटक	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री यश जालुका □	रिसर्च फेलो (□9.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री प्रज्ञा जैन	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री बिदिशा मंडल	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री अभिषेक	अंशकालिक रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री गुंटास कौर उप्पल □	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री करण गुलाटी □	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री तुषार आनंद □	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री मोहम्मद अहद	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□9.सुश्री रिधि वर्मा □	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री गणेश गोपालकृष्णन □	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री मिथिला ए सारा	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.श्री दिव्य रंगन	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□ को कार्यमुक्त)□
□□.सुश्री अरुमा खान	रिसर्च फेलो (□□.□□.□□□□को कार्यमुक्त)□

प्रशासनिक स्टाफ (संविदात्मक)□

1. श्री नवीन भल्ला	परामर्शक
2. श्री हरि शंकर गुप्ता	परामर्शक
3. श्री आर. मणि फ्रीलांस	परामर्शक (28.09.2021 को कार्यमुक्त हुए)
4. सुश्री दीपिका गुप्ता	परामर्शक (09.03.2022 को कार्यमुक्त हुए)
5. श्री रोहित भदौरिया	परामर्शक
6. सुश्री लता बालासुब्रमण्यम	कार्यक्रम सहायक

7. श्री कुलदीप सिंह	डाटा एंट्री ऑपरेटर
8. श्री मानेश वी एम	आईटी (परामर्शक)
9. श्री सुरेश कुमार	परामर्शक (कार्यक्रम सहायक)
10. सुश्री श्रेया चंद्र	डाटा एंट्री ऑपरेटर (14.12.2021 को कार्यमुक्त हुए)
11. श्री राजू	चालक (15.0□.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)
12. सुश्री मीना	डाटा एंट्री ऑपरेटर (20.12.2021 को कार्यभार ग्रहण किया)

अनुबंध □ □□□□□.□□.□□□□ की स्थिति के अनुसार प्रायोजक□निगमित□स्थायी और सामान्य सदस्यों की सूची□

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

□. आंध्र प्रदेश
□. असम
□. गुजरात
□. कर्नाटक
□. केरल
□. महाराष्ट्र
□. उड़ीसा
□. पंजाब
9. राजस्थान
□□. तमिलनाडु
□□. उत्तर प्रदेश
□□. पश्चिम बंगाल

अन्य

□. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
□. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
□. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ख. स्थायी सदस्य – राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

□. अरुणाचल प्रदेश
□. गोवा□दमन और दीव
□. हिमाचल प्रदेश
□. मध्य प्रदेश
□. मेघालय
□. मणिपुर
□. नागालैंड

ग. सामान्य सदस्य - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

□. हरियाणा
□. त्रिपुरा सरकार

घ. अन्य

□. मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

□ □

अनुबंध □□ वित्त और लेखा □

मैसर्स अनीश आशीष एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से लेखापरीक्षित संस्थान के वित्तीय वर्ष □□□□□□ के लिए लेखाओं का विवरण □

□ □

अनीश आशीष एंड कंपनी□

के - □□ तीसरी मंजिल□सरिता विहार □नई दिल्ली - □□□□□□
हैंडसेट : + 9□ □9□□□□9□□9□ □□ 9□ □9□□□□□□□□□
लैंडलाइन : □□□ □□99□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट□

□
सेवा में□

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान जनरल बॉडी के सभी सदस्य□
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

मत□

हमारे द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट□□□□□ (इकाई) के अंतर्गत पंजीकृत विनय के वित्तीय विवरणों□ जिनमें □□ मार्च□□□□□ को समाप्त अवधि के तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार□प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से □□ मार्च□□□□□ की यथास्थिति को इकाई की वित्तीय स्थिति एवं वर्ष के दौरान इसके वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

मत का आधार□

हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसरण में किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत उल्लेख हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग में प्रस्तुत लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्र में वर्णित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में हम इकाई से स्वतंत्र हैं तथा हमारे द्वारा अपने अन्य आचार उत्ततरदायित्वों का निर्वाह आचार संहिता के अनुरूप किया गया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षण प्रमाण हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं शासी प्रभारियों के उत्तरदायित्व□

भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई के इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के प्रति प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्र में सत्य एवं स्वच्छ स्वरूप में एवं किसी भी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्याकथन□किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण□से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति करने से संबद्ध डिजाइन□आंतरिक नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया जाना शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान प्रबंधन सोसायटी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने□गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंद्ध मामलों□यदि कोई हों□का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा इकाईको बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग

कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारी ही इकाई के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण यदि कोई हों की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोकता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं-:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियांएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्य परक हों पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठगांठ धोखाधड़ी किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं ।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना ।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए इकाई की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसीप्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणोंकी ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परिक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम इकाईकी प्रक्रियाओं को

गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंडएएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति□संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंडएएस वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

□

हम□अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

□

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों□जहां लागू हों□के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

□

अन्य अपेक्षाओं की रिपोर्ट□

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

i. हमने□वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं□
ii. हमारे मतानुसार□इकाई द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण विधि अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है तथा ऐसा इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है□तथा
iii. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं□

□

अनीश आशीष एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर 002535एन

□ह/--

आशीष गुस्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या- □□□□□9
यूडीआईएन: □□□□□□□9□□□□□□□□□□
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: □□ सितम्बर □□□□

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची	31 मार्च 22 की स्थिति	31 मार्च 21 की स्थिति
कायिक/पूंजीगत निधि एवं देनदारियां			
कायिक/पूंजीगत निधि	**1**	13,63,36,103	13,33,76,532
आरक्षित और अधिशेष	**2**	22,08,10,714	21,08,10,714
आस्थगित आय	**3**	1,62,43,516	1,67,64,168
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**4**	35,83,88,507	34,15,47,253
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	**5**	14,39,29,545	16,82,09,034
कुल		**87,57,08,385**	**87,07,07,701**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	**6**	6,02,98,435	6,34,93,588
निवेश- धर्मादा/विनिश्चित निधियां	**7**	39,65,58,451	39,18,87,062
निवेश - अन्य	**8**	31,58,60,073	23,07,65,770
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**9**	10,29,91,426	18,45,61,281
योग		**87,57,08,385**	**87,07,07,701**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**17**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**18**		

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आशीष आशीष एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002535N

(आशीष गुप्ता)
पार्टनर
एम.सं.: 503829
यूडीआईएन: 22503829AYFYEV5127
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक ; 30 सितम्बर 2022

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रु. में

	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2022	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2021
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	**10**	13,30,92,481	8,89,26,623
अकादमिक क्रियाकलापों से आय	**11**	10,16,42,260	13,09,67,871
अर्जित ब्याज	**12**	1,96,46,661	1,90,89,972
अन्य आय	**13**	1,35,68,317	1,81,05,683
योग		**26,79,49,719**	**25,70,90,149**
व्युय			
स्थापना व्यय	**14**	12,31,63,293	6,17,14,931
अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय	**15**	9,27,10,617	12,01,70,070
प्रशासनिक व्यय	**16**	3,54,97,770	3,23,13,708
प्रकाशन स्टॉक में कमी		71,220	-
मूल्यह्रास	**6**	35,47,248	37,82,326
योग		**25,49,90,148**	**21,79,81,035**
वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के नाते शेष		1,29,59,571	3,91,09,114
घटाएं : पूर्व अवधि की मदें		-	19,907
व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के नाते शेष		1,29,59,571	3,90,89,207
घटाएं : अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व से अंतरित राशि		50,00,000	1,60,00,000
घटाएं : सामान्य रिजर्व को अंतरित राशि		50,00,000	1,60,00,000
कायिक/पूंजीगत निधि से ले जाए गए अधिशेष के नाते शेष		**29,59,571**	**70,89,207**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**17**		
लेखाओं पर टिप्पणियां	**18**		

अनुसूची 1 से 18 लेखाओं का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के लिए

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(बी.एस. रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डा. आर.कविता राव)	(डा. उर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आशीष आशीष एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002535N

(आशीष गुप्ता)
पार्टनर
एम.सं.: 503829
यूडीआईएन: 22503829AYFYEV5127
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक ;30 सितम्बर 2022

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

		31 मार्च, 22 की स्थिति		31 मार्च, 21 की स्थित
अनुसूची 1 - कायिक/पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	13,33,76,532		12,62,87,325	
जोड़ें : आय और व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष	29,59,571		70,89,207	
		13,63,36,103		13,33,76,532
कुल		**13,63,36,103**		**13,33,76,532**
अनुसूची 2 - रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	8,71,89,863		7,11,89,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	50,00,000		1,60,00,000	
		9,21,89,863		8,71,89,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले लेखा के अनुसार	12,31,20,851		10,71,20,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	50,00,000		1,60,00,000	
		12,81,20,851		12,31,20,851
ग. मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व		5,00,000		5,00,000
योग		**22,08,10,714**		**21,08,10,714**
अनुसूची 3 - आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से अनुदान				
पिछले लेखा के अनुसार	1,61,30,658		1,64,44,537	
घटाएं : आय और व्यय लेखा में अंतरित ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि	3,13,879		3,13,879	
		1,58,16,779		1,61,30,658
विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान पूंजीगत आस्तियों के लिए प्रयुक्त				
पिछले लेखा के अनुसार	6,33,510		4,43,119	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			4,98,320	
घटाएं: ऐसी आस्तियों के मूल्यह्रास के समतुल्य राशि आय औरव्यय लेखा को अंतरित	2,06,773		3,07,929	
		4,26,737		6,33,510
योग		**1,62,43,516**		**1,67,64,168**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 4 - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां

राशि रु. में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कायिक निधि	राजा चेल्लैया व्याख्यान माला और अतिथि प्रोफेसरशिप निधि	कुल
प्रारंभिक निधि	61,77,924	1,00,00,000	4,00,00,000	7,27,406	4,20,000	50,000	29,300	12,00,00,000	2,00,00,000	
(क) निधियों का अथशेष	1,68,09,521	1,00,00,000	6,84,78,615	27,34,883	15,77,609	1,17,982	75,315	20,50,38,238	3,67,15,090	34,15,47,253
(ख) निधियों में अभिवृद्धियां										
(i) अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निवेश से आय	12,18,967	7,25,675	52,11,139	1,35,839	77,423	5,437	3,339	1,28,70,261	21,58,887	2,24,06,967
योग (क+ख)	**1,80,28,488**	**1,07,25,675**	**7,36,89,754**	**28,70,722**	**16,55,032**	**1,23,419**	**78,654**	**21,79,08,499**	**3,88,73,977**	**36,39,54,220**
(ग) निधि के प्रयोजनों के लिए उपयोग/व्यय	9,26,405	7,25,675	7,13,633	-	-	-	-	32,00,000		55,65,713
योग (ग)	**9,26,405**	**7,25,675**	**7,13,633**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,00,000**	**-**	**55,65,713**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख)-(ग)	**1,71,02,083**	**1,00,00,000**	**7,29,76,121**	**28,70,722**	**16,55,032**	**1,23,419**	**78,654**	**21,47,08,499**	**3,88,73,977**	**35,83,88,507**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च, 22 की स्थिति	31 मार्च, 21 की स्थिति
अनुसूची 5 - वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
क. वर्तमान देनदारियां		
1 माल और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	60,01,067	40,51,241
2 बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	11,62,083	9,97,613
3 अप्रयुक्त परियोजना अनुदान (देखिए अनुसूची 5(क))	6,72,12,546	6,19,03,757
4 केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान (देखिए अनुसूची 5(ख)	-	3,26,36,540
5 सांविधिक देय	53,21,498	48,71,529
6 अन्य वर्तमान देनदारियां	1,35,81,576	1,71,82,220
योग	**9,32,78,770**	**12,16,42,900**
ख. प्रावधान		
1 छुट्टी नकदीकरण	5,06,50,775	4,65,66,134
योग	**5,06,50,775**	**4,65,66,134**
सकल योग	**14,39,29,545**	**16,82,09,034**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

परियोजना **राशि रु. में**

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त	1 अप्रैल 2021 की स्थिति के वसूलीयोग्य	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	योग	प्रयुक्त/प्राप्त की गई और आय और व्यय लेखा में क्रेडिट की	प्रयुक्त और आस्थगित आय में क्रेडिट की गई	योग	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त
1	वित्तीय वैश्वीकरण और आर्थिक विकास-आईसीएसएसआर	1,77,433	-	-	1,77,433	-	-	-	-	1,77,433
2	स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	1,00,95,978	-	-	1,00,95,978	-	-	-	-	1,00,95,978
3	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - स्वास्थ्य पर अनुसंधान और नीतियों में सुधार और उसका वित्त-पोषण - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	55,20,988	-	6,78,197	61,99,185	-	-	-	-	61,99,185
4	राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण - यूएनडीपी	5,12,553	-	-	5,12,553	-	-	-	-	5,12,553
5	डिजिटल लैंड का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - एनसीईएआर उप-अनुदान	9,27,993	-	-	9,27,993	-	-	-	-	9,27,993
6	एनआईपीएफपी - टीएआरआई सहयोग कार्यक्रम	42,521	-	-	42,521	-	-	-	-	42,521
7	क्या मौद्रिक नीति भारत में वित्तीय स्थायित्व की दिशा में कार्य कर सकती है - आईसीएसएसआर	1,61,916	-	-	1,61,916	-	-	-	-	1,61,916
8	भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स	1,48,29,595	-	3,74,16,591	5,22,46,186	2,76,54,775	-	2,76,54,775	-	2,45,91,411
9	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - भारत में स्वास्थ्य के लोक वित्त-पोषण के दृष्टिकोण : भावी मार्ग - बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	26,30,503	-	2,58,863	28,89,366	-	-	-	-	28,89,366
10	वित्त में परिणामों गेट्स									
11	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन - लोक वित्त में परिणामों के लिए नवाचार -बिल एंड गेट्स	12,75,960	-	-	12,75,960	12,75,960	-	12,75,960	-	-
12	डेटा संरक्षण में सहमति फ्रेमवर्क में सुधार - ओम्डियार नेटवर्क	1,21,098	-	-	1,21,098	1,21,098	-	1,21,098	-	-
13	प्राकृतिक प्रबंध सुदृढ़ीकरण - - II	1,87,710	-	-	1,87,710	-	-	-	-	1,87,710
14	हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए सहयोगी सेवा, हिमाचल प्रदेश - यूएनडीपी	-	1,01,803	80,437	(21,366)	-	-	-	21,366	-
15	हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए सहयोगी सेवा, सिक्किम - यूएनडीपी	-	2,28,080	2,28,080	-	-	-	-	-	-
	अग्रेनीत									

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त	1 अप्रैल 2021 की स्थिति के वसूलीयोग्य	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	योग	प्रयुक्त/प्राप्त की गई और आय और व्यय लेखा में क्रेडिट की	प्रयुक्त और आस्थगित आय में क्रेडिट की गई	योग	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वसूलीयोग्य	1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त
	कुल अग्रानीत									
16	एनआईपीएफपी - डीईए अनुसंधान कार्यक्रम - आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 2020-21	-	49,24,890	49,24,890	-		-	-	-	-
17	एनआईपीएफपी - डीईए अनुसंधान कार्यक्रम - आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 2020-21			59,15,172	59,15,172	96,79,663	-	96,79,663	37,64,491	-
18	भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	2,29,86,670	-	54,85,185	2,84,71,855	1,13,07,344	-	1,13,07,344	-	1,71,64,511
19	अनुदान के लिए ब्याज आबंटन -भारत में वित्तीय समावेशन के लिए शिकायत निवारण मॉडल- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन	11,04,578	-	9,92,201	20,96,779	-	-	-	-	20,96,779
20	भूमि और संपत्ति अधिकारों पर अनुसंधान को समर्थन - ओमिडियार नेटवर्क-III	9,82,240	-	-	9,82,240	46,88,528	-	46,88,528	37,06,288	-
21	सरकारी स्कूलों से बहिर्गमन की जांच - अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय	56,767	-	-	56,767	56,767	-	56,767	-	-
22	न्याय चुनौती के लिए डेटा - नागरिकों के लिए व्याम फोरम	41,404	-	8,00,848	8,42,252	8,42,252	-	8,42,252	-	-
23	भारत में लोक अधिप्राप्ति और औषधि गुणवत्ता - ठाकुर फाउंडेशन	2,47,850	-	-	2,47,850	2,47,850	-	2,47,850	-	-
24	भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन:जीवीए और निवेश में अंशदान-एमसीए	-	-	9,52,200	9,52,200	8,00,518		8,00,518	-	1,51,682
25	राज्य वित्त आयोग - यूनिसेफ	-	-	12,57,665	12,57,665	10,57,703	-	10,57,703	-	1,99,962
26	संरक्षण व्यय समीक्षा									

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

5( ) : केंद्रीय अप्रयुक्त

	As at	As at
अप्रयुक्त अनुदान का आदिशेष	3,26,36,540	(6,87,35,837)
जोड़ें : वेतन और भत्तों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	8,88,00,000	18,91,00,000
आवर्ती व्ययों वर्ष प्राप्त		
	12,14,36,540	**12,03,64,163**
घटाएं : वेतन और भत्तों के लिए अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखा में आय के रूप में विचार किया गया)	13,18,94,481	8,77,27,623
आवर्ती व्ययों के लिए अप्रयुक्त अनुदान (आय और व्यय लेखा में आय के रूप में विचार किया गया)	-	
अप्रयुक्त वसूलीयोग्य		

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

स्थायी परिसंपत्तियां

Amount in ₹

Description	Gross Block				Depreciation				Net Block	
स्वयं की निधियों अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
1 पट्टा-धृति भूमि	1,88,09,202	-	-	1,88,09,202		-	-	-	1,88,09,202	1,88,09,202
2 भवन	3,39,05,360	-	-	3,39,05,360	1,38,32,608	8,35,123	-	1,46,67,731	1,92,37,629	2,00,72,752
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,06,79,820	2,03,364	5,950	3,08,77,234	2,85,33,463	12,56,877	-	2,97,90,340	10,86,894	21,46,357
4 कार्यालय उपकरण	1,00,03,978	17,670	-	1,00,21,648	91,01,506	3,14,036	-	94,15,542	6,06,106	9,02,472
5 फर्नीचर और जुड़नार	1,25,40,539		-	1,25,40,539	1,09,89,933	1,90,862	-	1,11,80,795	13,59,744	15,50,606
6 छात्रावास, पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	36,41,172		-	36,41,172	36,38,974	406	-	36,39,380	1,792	2,198
7 एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	75,50,950	1,11,816	-	76,62,766	58,13,160	2,15,980	-	60,29,140	16,33,626	17,37,790
8 विद्युत संस्थापनाएं	70,33,421	25,195	-	70,58,616	63,00,305	98,272	-	63,98,577	6,60,039	7,33,116
9 वाहन	14,24,148		-	14,24,148	6,49,221	1,15,040	-	7,64,261	6,59,887	7,74,927
10 बागवानी उपकरण	1,09,780	-	-	1,09,780	1,09,780	-	-	1,09,780	-	-
11 चल रहे पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**12,56,98,370**	**3,58,045**	**5,950**	**12,60,50,465**	**7,89,68,950**	**30,26,596**	**-**	**8,19,95,546**	**4,40,54,919**	**4,67,29,420**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
केंद्रीय										
1 भवन - अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	2,12,89,579	-	-	2,12,89,579	51,58,921	3,13,879	-	54,72,800	1,58,16,779	1,61,30,658
2 विद्युत, अग्निशामक एवं एचवीएसी कार्य-अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	69,00,850	-	-	69,00,850	69,00,850	-	-	69,00,850	-	-
योग	**2,81,90,429**	**-**	**-**	**2,81,90,429**	**1,20,59,771**	**3,13,879**	**-**	**1,23,73,650**	**1,58,16,779**	**1,61,30,658**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां										
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	41,56,385	-	-	41,56,385	40,24,368	-	-	40,24,368	1,32,017	1,32,017
1 कार्यालय उपकरण	2,16,380	-	-	2,16,380	2,07,206	-	-	2,07,206	9,174	9,174
2 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईसीएसएसआर	51,500	-	-	51,500	48,925	-	-	48,925	2,575	2,575
3 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण-एमएमएसएसपीएसवाई, एमपी से साक्ष्य	89,000	-	-	89,000	12,509	28,183	-	40,692	48,308	76,491
5 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आरबीआई	1,06,650	-	-	1,06,650	21,929	33,772	-	55,701	50,949	84,721
योग	**46,19,915**	**-**	**-**	**46,19,915**	**43,14,937**	**61,955**	**-**	**43,76,892**	**2,43,023**	**3,04,978**
स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										-
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	-
2 फर्नीचर और जुड़नार	15,23,860	-	-	15,23,860	15,23,860	-	-	15,23,860	-	-
3 बागवानी उपकरण	6,24,980	-	-	6,24,980	6,24,980	-	-	6,24,980	-	-
योग	**21,58,720**	**-**	**-**	**21,58,720**	**21,58,720**	**-**	**-**	**21,58,720**	**-**	**-**
परियोजना अनुदानों से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियां - एफसीआरए										
1 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - आईडीआरसी	1,54,571	-	-	1,54,571	1,46,842	-	-	1,46,842	7,729	7,729
2 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-II	7,80,953	-	-	7,80,953	4,86,878	1,27,406	-	6,14,284	1,66,669	2,94,075
3 कार्यालय उपकरण - एनसीईएआर उप-अनुदान	22,000	-	-	22,000	16,617	4,180	-	20,797	1,203	5,383
4 डेटा प्रोसेसिंग उपकरण - बीएमजीएफ-III	1,62,250	-	-	1,62,250	1,40,905	13,232	-	1,54,137	8,113	21,345
योग	**11,19,774**	**-**	**-**	**11,19,774**	**7,91,242**	**1,44,818**	**-**	**9,36,060**	**1,83,714**	**3,28,532**
सकल योग	**16,17,87,208**	**3,58,045**	**5,950**	**16,21,39,303**	**9,82,93,620**	**35,47,248**	**-**	**10,18,40,868**	**6,02,98,435**	**6,34,93,588**
पिछला वर्ष	**15,97,51,368**	**32,16,284**	**11,80,444**	**16,17,87,208**	**9,45,11,294**	**37,82,326**	**-**	**9,82,93,620**	**6,34,93,588**	

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

			31 मार्च 2022 की स्थिति		31 मार्च 2021 की स्थिति
अनुसूची 7 - निवेश - धर्मादा/विनिर्धारित निधियां					
दीर्घकालिक निवेश					
सरकारी प्रतिभूतियों में			9,70,13,079		9,58,13,079
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			19,26,31,348		16,97,31,349
वर्तमान निवेश					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			10,69,14,024		12,63,42,634
योग			**39,65,58,451**		**39,18,87,062**
अनुसूची 8 - निवेश - अन्य					
दीर्घकालिक निवेश					
सरकारी प्रतिभूतियों में			9,50,10,000		6,50,10,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			12,95,00,963		9,24,00,963
वर्तमान निवेश					
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां			9,12,70,611		7,32,76,308
प्रतिभूति निक्षेप के विरुद्ध अनुसूचित बैंकों के पास नियत निक्षेत			78,499		78,499
योग			**31,58,60,073**		**23,07,65,770**
अनुसूची 9 - वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि					
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :					
1. वस्तु-सूची					
प्रकाशनों का स्टॉक			19,717		90,937
2. विविध लेनदार			2,03,218		1,20,780
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/अप्रदाय सहित)			24,768		16,435
4. बैंक शेष					
अनुसूचित बैंको के साथ - बचत खाते					
केनरा बैंक जीत सिंह मार्ग खाता सं.1484101001555	3,12,44,787		3,12,40,580		
केनरा बैंक जीत सिंह मार्ग खाता सं. 1484106026094	3,101		9,55,74,281		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू खाता सं.10596549875	18,677		18,180		
अनुसूचित बैंकों के साथ - चालू खाते					
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू एफ.सी.खाता सं. 10596547368	1,31,47,036		1,01,05,117		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा बचत बैंक खाता सं. 40070210371	33,294		-		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	42,009		42,658		
		4,44,88,904			13,69,80,816
ख.. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां :-					
1. अग्रिम और अन्य राशियां नकद अथवा सामान अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूलीयोग्य					
क) पूर्वसंदत्त व्यय	79,64,628		74,79,570		
ख) व्ययों के लिए स्टाफ को अग्रिम	1,40,198		63,174		
ग) अन्य अग्रिम	2,32,176		5,47,642		
घ) प्रतिभूति जमा	5,88,719		5,88,719		
ड) इनपुट कर क्रेडिट	72,550		4		
		89,98,271			86,79,109
2. प्रोद्भूत आय					
क) निवेश आय - विनिर्धारित/धर्मादा निधियां	37,06,316		40,78,363		
ख) निवेश आय - अन्य	19,56,516		17,25,239		
ग) राज्य सरकार का अनुदान	1,00,000		5,00,000		
घ) पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	77,62,530		1,38,81,715		
ड.) परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	74,92,145		52,54,773		
च) अप्रयुक्त/(प्राप्तियोग्य) अनुदान - एमओएफ	1,04,57,941		-		
		3,14,75,448			2,54,40,090
3. प्राप्तियोग्य दावे					
क) प्राप्तियोग्य आयकर		1,77,81,100			1,32,33,114
योग		**10,29,91,426**			**18,45,61,281**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 10 - केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. **केंद्रीय सरकार से अनुदान**		
वेतन अनुदान (अनुसूची 5(ख) देखें)	13,18,94,481	8,77,27,623
योग (क)	**13,18,94,481**	**8,77,27,623**
ख. **राज्य सरकारों से अनुदान**		
सामान्य सहायता अनुदान		
ओडिशा सरकार	5,00,000	5,00,000
महाराष्ट्र सरकारa	98,000	99,000
तमिलनाडु सरकार	1,00,000	1,00,000
गुजरात सरकारt	5,00,000	5,00,000
योग (ख)	**11,98,000**	**11,99,000**
सकल योग (क+ख)	**13,30,92,481**	**8,89,26,623**
अनुसूची 11- अकादमिक क्रियाकलापों से आय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना आय	1,21,60,321	1,80,96,665
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान (अनुसूची 5(क) देखें)	8,94,81,939	11,28,71,206
योग	**10,16,42,260**	**13,09,67,871**
अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज - बैंक/वित्तीय संस्थाएं		
अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा पर	44,39,783	15,64,650
अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खातों पर	4,36,464	4,34,286
सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों पर	1,47,03,606	1,25,48,297
आयकर वापसी पर ब्याज	-	44,68,779
अन्य ब्याज	66,808	73,960
योग	**1,96,46,661**	**1,90,89,972**
अनुसूची 13 - अन्य आय		
प्रकाशनों की बिक्री	200	-
वसूलियां	1,19,15,528	1,54,09,442
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	1,20,122	-
विविध आय	8,30,777	14,97,737
मकान किराया वसूलियां	1,15,894	1,42,820
एनआईपीएफपी स्टाफ से प्राप्त परामर्श शुल्क	-	4,10,433
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	65,144	23,443
आस्थगित आय से अंतरित राशि (अनुसूची 3 देखें)	5,20,652	6,21,808
योग	**1,35,68,317**	**1,81,05,683**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

राशि रु. में

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 14 -स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	12,43,89,907	7,98,69,171
बोनस	-	2,41,780
पीएफ और पेंशन निधि को अंशदान	1,17,95,602	78,38,639
उपदान	29,61,210	73,98,130
चुट्टी वेतन	1,04,14,291	26,25,265
कर्मचारी लाभ और कल्याण	39,60,995	35,87,839
ईडीएलआई और प्रशासनिक प्रभार	2,16,136	1,72,971
परमर्श शुल्क	7,79,075	2,82,500
	15,45,17,216	**10,20,16,295**
घटाएं : अकादमिक क्रियाकलापों के लिए प्रभारित	3,13,53,923	4,03,01,364
योग	**12,31,63,293**	**6,17,14,931**
अनुसूची 15 - अकादमिक क्रियाकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना व्यय	32,28,678	72,98,864
परियोजना अनुदानों का उपयोग (अनुसूची 5(क) देखें)	8,94,81,939	11,28,71,206
योग	**9,27,10,617**	**12,01,70,070**
अनुसूची 16 - प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और परिवहन	4,00,638	1,29,619
दरें और कर	11,88,962	12,03,556
विद्युत प्रभार	66,36,218	60,45,931
जल प्रभार	3,33,907	8,33,230
मुद्रण और लेखन-सामग्री	4,02,718	3,28,667
डाकशुल्क और टेलीफोन	8,72,537	12,89,133
मरम्मत और अनुरक्षण	1,66,83,867	1,35,36,841
कार संचालन और अनुरक्षण	1,08,019	1,18,430
लेखापरीक्षा शुल्क	1,87,614	1,86,448
लेखापरीक्षा शुल्क- आंतरिक	1,33,473	1,12,844
लेखापरीक्षा शुल्क (पीएफ न्यास)	24,962	22,000
लेखापरीक्षा शुल्क (उपदान न्यास)	25,960	26,064
विविध व्यय	17,86,080	3,06,069
विधिक व्यय	4,76,782	4,44,695
विज्ञापन व्यय	4,90,767	4,16,390
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	1,22,580	46,000
पुस्तकें और पत्रिकाएंऽ	89,82,164	1,04,20,334
प्रकाशन की लागत	1,19,680	1,40,878
बैठकें और संगोष्ठियां	1,59,600	8,578
सामान्य/शासी निकाय की बैठक	-	930
बीमा व्यय	1,43,417	1,39,479
वसूलीयोग्य बट्टे खाते में डाला गया	-	3,66,187
व्यावसायिक शुल्क	1,13,500	1,59,658
25वीं वर्षगांठ पर व्यय	30,000	-
	3,94,23,445	3,62,81,961
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	7,25,675	7,68,253
घटाएं : धर्मादा/निर्धारित निधियों के लिए प्रभारित	32,00,000	32,00,000
योग	**3,54,97,770**	**3,23,13,708**

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान□

मार्च □□□□को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां□

□

अनुसूची □□□लेखांकन नीतियां □

□ वित्तीय विवरणों का निर्माण बीमांकिक आधार पर ऐतिहासिक अभिसमय के अधीन उपचय आधार पर और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखाकरण मानकों□यदि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है□के अनुसार किया जाता है। सामान्य सदस्यता शुल्क को नकद आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

□ वित्तीय विवरणिकाएं तयार करने के लिए ऐसे प्राक्कनों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है जिनसे प्रतिवेदन अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों□राजस्व और व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित होती है। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आधार पर किए जाते हैं□वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम परिणत होते हैं।

□. दीर्घावधिक निवेशों को ह्रास□अस्थाई के अलावा□के समायोजन के पश्चात उनकी वहन लागत पर अग्रेनित किया जाता है। चालू निवेश लागत और उचित मूल्य में से न्यूनतर के आधार पर अग्रेनित किए जाते हैं। निवेशों की लागत में□यदि अन्यथा उल्लेय न किया गया हो□प्रीमियम सहित सभी अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई चेयर औफ इंस्टीट्यूट के लिए दी गई कायिक निधि में से प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों□जब इन्हें प्रीमियम पर अधिग्रहीत किया गया हो□का उल्लेख आरबीआई और संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन के नियमों और शती के अनुसार आरबीआई कायिक निधि से उपार्जित ब्याज आय के सापेक्ष किया गया है।

□. प्रकाशनों की मानसूची का मूल्यांकन लागत पर किया गया है। लागत का निर्धारण एफआईएफओ आधार पर किया गया है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशन और परियोजना अनुदानों से वित्त-पोषित प्रकाशनों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है।

□. अचल परिसम्पतियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया गया है जिसमें अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय भी शामिल हैं। अचल परिसम्पतियों का मूल्यांकन लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है।

□. प्रबंधन द्वारा पाँच प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार के पश्चात परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोज्यता काल के आधार पर सरल रेखा पद्धति से मूल्यहास प्रभारित किया गया है। परिसम्पत्तियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है-:

परिसम्पति विवरण 	**उपयोज्यता काल**
भवन	वर्ष
डेटा संसाधन उपकरण	वर्ष
कार्यालय उपकरण	वर्ष
फर्नीचर एवं जुडनार	वर्ष
होस्टलपुस्तकालयकम्प्यूटर एवं सेमिनार कक्ष फर्नीचर	वर्ष
एयर कंडीनर एवं वाटर कूलर	वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं	वर्ष
वाहन	वर्ष
बागवानी उपकरण	वर्ष

. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से किसी परिसम्पत्ति का क्षय होने के संबंध में आकलन किए जाते हैं। ऐसे क्षय के किसी संकेत के मामले मेंप्रबंधन द्वारा परिसम्पति के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी वाहित राशि से कम हैतो परिसम्पत्ति की वाहित राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और अंतर को अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. अल्पावधिक कर्मचारी लाभों को आय एवं व्यय के लेखे में छूट न दी गई राशि के व्यय के रूप में सेवाएं प्रदान किए जाने के वर्ष में प्रभारित किया गया है।

. रोजगार के बाद के और अन्य दीर्घावधिक लाभों को उस वर्ष के आय व्यय लेखे में छूट न दी गई राशि पर हुए व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए निर्धारित देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर स्वीकृति दी गई है। रोजगार-पश्चात और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को सामान्यतः संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखा पुस्तिकाओं में लेखाबद्ध किया गया है।

□□. चिह्नित/वृत्ति निधियों से निवेशों पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि के शेष को□यदि कोई हो□संबंधित चिह्नित/वृत्ति निधियों में रखा गया है।

□□. विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभिक तौर पर देनदारी माना गया है और वर्ष के दौरान उपयोगिता के अनसार समायोजित किया गया है। अनुदानों को□मूल्यह्रास के योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक□आस्थगित आय माना गया है और इन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक आधार पर आय और व्यय लेखे में स्वीकृति दी गई है। राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त सीमा तक वेतनों और परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय माना गया है। आवर्ती व्ययों के लिए अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

□□. प्रावधानों को वहां स्वीकृति दी गई है जब विगत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी हो तथा जिसके लिए यह संभव हो कि देनदारी के समाधान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होगा और विश्वसनीय प्राक्कलन संभव हो सकेगा। देनदारी के समाधान के लिए अपेक्षित प्रावधानों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और जहां देनदारी के चालू सर्वोत्तम प्राक्कलन के लिए आवश्यक हो□ समायोजित किया गया है।

□□. किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया गया है जब एक संभावित देनदारी या वर्तमान देनदारी हो जिसके लिए संसाधनों का वह बर्हिप्रवाह अपेक्षित हो सकता हो□जो संभावित रूप से अपेक्षित नहीं है। उस वर्तमान देनदारी के संबंध में भी प्रकटीकरण किया जाएगा जिसके लिए संभवतः संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो□जहां संबंधित बहिर्प्रवाह का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जाना संभव न हो।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

मार्च 31 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग को निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – लेखाओं पर टिप्पणियाँ

. आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां संस्थान के विरूद्ध एवं संस्थान द्वारा दायर किए न्यायिक मामलों के संबंध में देयता है। सकता जा किया नहीं निर्धारण का राशि :

2. आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां

. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की संज्ञान की गई एवं एमएसएमईडी अधिनियम के खंड में अनुपालन में संस्थान में उपलब्ध देयताएं:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को चुकता न की गई मूल राशि।		9 9
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को देय ब्याज तथा वर्ष के अंत में चुकता न की गई बकाया राशि।	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन के पश्चात आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता को तथा एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार भुगतान की राशि के साथ चुकता किए गए ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान किए जाने में देरी की अवधि के लिए देय एवं बकाया व्याज (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता किया गया है) जिसे एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट व्याज जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उससे संबंधित उद्भूत और चुकता न किया गया ब्याज	-	-
आगामी वर्षों में भुगतान न किए जाने के कारण देय और भुगतान किए जाने योग्य बढ़त ब्याज की राशि जिसे ऐसी तारीख तक जब ऊपर उल्लिखित ब्याज देय को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से चुकता किया जाना है।	-	-

. संस्थान के प्रबंधन के मतानुसार चालू परिसम्पत्तियों ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कारोबार के सामान्य क्रम में कम से उस राशि के समान है जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान वित्तीय विवरणिका में किया गया है। मार्च को कुल रु. के वसूलीयोग्य आयकर में से 9 रु. की वसूलीयोग्य आयकर की राशि वित्तीय वर्ष और पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित है।

□. □□ मार्च□□□□□ को कुल □□□□□□□□□□ रु. के वसूलीयोग्य आयकर में से□□□□□□□□9 रु. की वसूलीयोग्य आयकर की राशि वित्तीय वर्ष □□□□□□□ और पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित है।अन्य निधियों में 31,57,81,574 रूपए की राशि का निवेश अनुद्धृत निवेश है।

□. वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यताप्राप्त परिभाषित अंशदायी योजना का विवरण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 1□10□36□735 रु. (पिछले वर्ष 70□04□889 रु.)

पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान 7□58□867 रु. (पिछले वर्ष 8□33□750 रु.)

एक न्यास द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना परिभाषित लाभ योजना विद्यमान है। देनदारी के वर्तमान मूल्य का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है□जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के रूप में स्वीकृत किया गया है और अंतिम देनदारी निर्मित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा गया है। छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी को इसी तरीके से ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत किया गया है।

तुलन□पत्र की तारीख के अनुसार मूल बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार है:

क) आर्थिक अनुमान□

मूल पूर्वानुमान इस प्रकार हैं (1) छूट की दर (2) वेतन वृद्धि। छूट वृद्धि लेखाकरण तिथि को सरकारी बंधपत्रों पर उपलब्ध बाजार अर्जन पर उस शर्त पर आधारित है जो देयताओं की शर्तों से मिलती हो और वेतन वृद्धि में मूल्यवृद्धि□वरिष्ठता□प्रोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि□अक्षमता के लिए कोई सुस्पष्ट भते का उपयोग नहीं किया गया है।

	विवरण□	□□**मार्च** □□□□□	□□**मार्च** □□□□□
i□	छूट की दर	□.□□□	%6.75
ii□	भावी वेतन वृद्धि	9.□□□	9.□□□
iii□	उपदान के लिए योजना परिसम्पत्तियों की प्रत्याशित प्रतिफल दर (पोषित-वित्त)	□.□□□	□.□□□
ख)□	**जनसांख्यिकी अनुमान**□	□□ मार्च □□□□	□□ मार्च □□□□
i□	सेवानिवृत्ति आयु	वर्ष 60	वर्ष 60
ii□	मृत्यु सारणी	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
iii□	निकासी दर (प्रतिवर्ष)	□.□□□	□.□□□

□. गत वर्ष के आंकड़ों को□जहां कहीं भी इन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक हो□ पुनर्निर्मित□पुन:प्रतिशत समूहबद्ध□पुनःव्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

कृते राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
(बीएस रावत)	(पंकज कुमार सिन्हा)	(डॉ. आर. कविता राव)	(डॉ. ऊर्जित पटेल)
लेखा अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार।

अनीश आशीष एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002535एन

आशीष गुप्ता
पार्टनर
एम.सं.: □□□□□9
यूडीआईएन: □□□□□□□9□□□□□□□□□□
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक□□□ सितम्बर □□□□

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थागत क्षेत्र (जेएनयू के समीप),
नई दिल्ली-110067

वेबसाइट: www.nipfp.org.in